RNI NO.DELHIN/2012/48369
वर्ष 10 अंक 89
नई दिल्ली, शुक्रवार, 4 फरवरी, 2022
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

खेल में सुधार के लिए आईपीएल नहीं खेलने का फैसला किया
स्पोर्ट्स-12

चीन के 50 से अधिक सैनिक मारे गए थे गलवान में

- ऑस्ट्रेलियाई अखबार का दावा, लद्दाख में 2020 में भारतीय सेना के साथ संघर्ष में चीन ने दावे से कई गुना अधिक नुकसान उठाया

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

फाइल फोटो

लद्दाख के गालवान घाटी में वर्ष 2020 में भारतीय सैनिकों के साथ हुए खूनी संघर्ष में चीन के 40 से अधिक सैनिक मारे गए थे। यह खुलासा एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार द्वारा किया गया है जो चीन के हताहतों की आधिकारिक आंकड़ों की स्वीकारोक्ति से कई गुना अधिक है। जबकि खुफिया रिपोर्ट के अनुसार चीनी सैनिकों के मरने वालों की संख्या 50 से अधिक है। दोनों देशों के बीच 15 जून 2020 को हुई यह झड़प पिछले 40 सालों में सबसे खूनी संघर्ष थी। जिसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर सहित बीस जवान मारे गए थे। मौके से खुफिया रिपोर्टों ने संकेत दिया कि लगभग 50 चीनी सैनिक भी मारे गए लेकिन बीजिंग हताहतों की संख्या को सार्वजनिक करने से हमेशा बचता रहा। हालांकि कुछ महीने पहले चीन ने कहा था कि गालवान संघर्ष में उसके चार सैनिक मारे गए थे। ऑस्ट्रेलियाई समाचार पत्र द क्लैक्सन द्वारा उद्धृत सोशल मीडिया शोधकर्ताओं के एक समूह की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने जून 2020 में गालवान घाटी संघर्ष में 42 सैनिकों को खो दियाए जो चार से कम से कम नौ गुना अधिक है। एक साल की लंबी जांच के बाद तैयार किए गए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020 में भारत.चीन के बीच 15-16 जून की झड़प के शुरुआती दौर में तेजी से बहने वाली गालवान नदी को चीनी सैनिकों द्वारा पार करने के प्रयास में कम से कम 38 सैनिक मारे गए थे। सैनिक शून्य से भी कम तापमान और अंधेरे में नदी पार कर रहे थे। खोजी अखबार ने गालवान डिकोडेड शीर्षक वाली रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिन चार सैनिकों की मरने की चीन ने पुष्टि की थी उनमें से केवल एक जूनियर सार्जेंट वांग जुओरान कथित तौर पर डूबने से मरा था। रिपोर्ट में कई वीआइबो उपयोगकर्ताओं का हवाला देते हुए कहा गया कि उस रात वांग के साथ झड़प में कम से कम 38 पीएलए सैनिकों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कामरेडों के हाथ से हथियार फिसलते रहे और वे बहती धारा की ओर भागे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि घटना के बाद सैनिकों के शवों को पहले शिकान्हे शहीद कब्रिस्तान ले जाया गया उसके बाद मारे गए सैनिकों के शहरों में स्थानीय समारोह आयोजित किए गए।इस क्षेत्र में काम करने वाले एक वीआइबो उपयोगकर्ता कियांग का दावा उद्धृत करते हुए यूजर ने दावा किया कि चीनी सेना आपसी समझौते का उल्लंघन करते हुए बफर जोन में बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है और अप्रैल 2020 से बफर जोन के भीतर अपनी गश्त सीमा का विस्तार करने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएलए ने अपने वादे का पालन नहीं किया और सहमति के अनुसार अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे को खत्म करने के बजाय भारतीय सेना द्वारा बनाए गए नदी पार करने वाले पुल को गुप्त रूप से ध्वस्त कर दिया। बीजिंग ने इस संघर्ष की चर्चा को दबाने के लिए चरम सीमा तक चला गयाए विशेष तौर से चीनी हताहतों की सही संख्या बताने के बारे में। क्लेक्सन ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि झिंजियांग सैन्य क्षेत्र के एक डिवीजन ने शहीद हुए अधिकारियों (शेष पेज 9)

भारत के शीर्ष राजनयिक बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन, समापन समारोह में नहीं जाएंगे

भाषा। नई दिल्ली

- नई दिल्ली ने इस समारोह में गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक सैन्य कमांडर को ओलंपिक मशाल वाहक बनाए जाने को दुखद बताया

भारत ने बृहस्पतिवार को घोषणा की है कि चीन की राजधानी में होने वाले 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में उसके शीर्ष राजनयिक शामिल नहीं होंगे। साथ ही नई दिल्ली ने इस समारोह में गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक सैन्य कमांडर को ओलंपिक मशाल वाहक बनाए जाने को अफसोसनाक बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन ने ओलंपिक जैसे आयोजन का राजनीतिकरण करना चुना और हमारे बीजिंग में भारतीय दूतावास के प्रभारी शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। भारतीय दूतावास के प्रभारी वहां के वरिष्ठतम राजनयिक हैं क्योंकि अगले राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया है। चीन की जन मुक्ति सेना के गलवान घाटी के कमांडर को शीतकालीन ओलंपिक मशाल देकर चीन द्वारा सम्मानित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमने इस मुद्दे पर रिपोर्ट देखी है। यह अफसोस की बात है कि चीन ने ओलंपिक जैसे आयोजन का राजनीतिकरण करना चुना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सैन्य कमांडर को इस तरह से सम्मानित करने के चीन के कदम को अफसोसजनक करार दिया। शुक्रवार को 24वें शीतकालीन ओलंपिक समारोह का उद्घाटन होगा। चीनी ग्लोबल टाइम्स समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, जप मुक्ति सेना के रेजिमेंट कमांडर क्वी फाबाओ 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत के साथ संघर्ष में शामिल रहे थे और चीन ने ओलंपिक समारोह में उन्हें मशाल वाहक के रूप में चुना। इस संघर्ष में फाबाओ को सिर में गंभीर चोटे लगी थी और वह बुधवार को टार्च रिले में 1200 मशाल वाहकों में शामिल थे। विदेश मंत्रालय की घोषणा के बाद प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि दूरदर्शन का खेल चैनल ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह का प्रसारण नहीं करेगा। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी। भारत की यह कदम ऐसे समय में आया है जब दो महीने पहले उसने रूस-भारत-चीन त्रिस्तरीय ढांचे के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन द्वारा बीजिंग ओलंपिक की मेजबानी का समर्थन किया था।

पांच फीसद से कम सकारात्मकता वाले जिलों में स्कूल खोलने की अनुमति

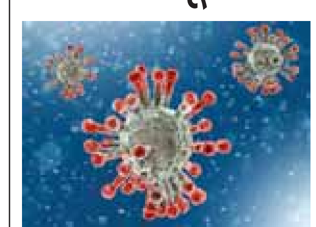

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि जिन जिलों में कोविड संक्रमण की दर पांच प्रतिशत से कम है वे स्कूल पुन: खोलने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं लेकिन इस पर राज्य सरकारों को निर्णय लेना होगा। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वी के पॉल ने कहा कि देश में महामारी की स्थित में सुधार हुआ है और कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल पुन: खोलने की दिशा में सरकार का विश्वास और मजबूत हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि 11 राज्यों में स्कूल पूरी तरह खुले हैं जबकि 16 राज्यों में ज्यादातर उच्चतर कक्षाओं में लिए स्कूल पुन: खोले गए हैं।

अधिकारियों ने कहा कि टीकाकरण के व्यापक अभियान के बाद मंत्रालय ने स्कूल पुन: खोलने के लिए दिसंबर में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। अधिकारियों ने कहा कि नौ राज्यों में स्कूल पूरी तरह बंद हैं और सभी राज्यों में कम से कम 95 प्रतिशत शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों ने टीका लगवाया है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में सौ प्रतिशत टीकाकरण पूरा कर लिया गया है। पॉल (शेष पेज 9)

महामारी ढलान पर, 34 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सकारात्मकता दर गिरी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने गुरुवार को पहली बार कहा कि महामारी की स्थिति में सुधार हुआ है और कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी आई है। महामारी का चरम समाप्त हो चुका है। इसलिए अब कोविड लहर या वेव नहीं कहा जाना चाहिए। केंद्र ने कहा कि अत्यधिक संक्रामक ओमीक्रोन वैरिएंट द्वारा संचालित तीसरी लहर में दूसरी लहर की तुलना में थोड़ी कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भारत मे दूसरी लहर के चरम पर दैनिक कोविड मामले चार लाख से अधिक आए थे। इसके विपरीत देश में गुरुवार को 1.72 लाख ताजा मामले दर्ज किए गए और ये बीते 21 जनवरी को दर्ज किए गए मामलों से आधे हैं। सरकार के अनुसार 21 जनवरी को तीसरी लहर का चरम था। उसके बाद से (शेष पेज 9)

असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग ग्रेटर नोएडा का युवक गिरफ्तार

- एआईएमआईएम प्रमुख के बयान से नाराज था आरोपी, पिस्टल बरामद

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

कार पर लगी गोलियों के निशान

चुनाव प्रचार खत्म कर दिल्ली लौट रहे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर तीन से चार राउंड फायरिंग की गई। इस गोलीकांड में ओवैसी बाल-बाल बच गए। वहीं पुलिस ने इस सिलसिले में ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियाई गांव से एक युवक को हापुड़ पुलिस ने हिरासत में लिया है। सबसे पहले ओवैसी ने इस बारे में ट्वीट किया कि उन पर अज्ञात लोगों ने गाजियाबाद स्थित छिजारसी टोल प्लाजा के पास पर हमला किया है।

उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई और हमलावर मौके से फरार हो गए। एडिशनल एसपी हापुड़ के अनुसार ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन ने साथी शुभम के साथ मिलकर फायरिंग की थी। सचिन हिरासत में लिया गया उसके पास से 9एमएम बरामद हुई है। ओवैसी के कुछ बयानों से सचिन नाराज बताया जा रहा है। घटना के बाद दूसरी गाड़ी से दिल्ली पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि गोलीबारी की घटना की स्वतंत्र जांच कराई जाए। घटना के संबंध में मेरठ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईजी प्रवीन कुमार ने कहा कि सूचना के आधार पर घटनास्थल का मुआयना किया। मामले में सबूत इकट्ठे किए हैं। सीसीटीवी की मदद से एक व्यक्ति की पहचान की गई, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। ओवैसी के (शेष पेज 9)

पेगासस पैनल ने कहा, जांच के लिए केवल दो लोगों ने मोबाइल दिए

- फोन जमा करने की तारीख आठ फरवरी तक बढ़ाई गई
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच पैनल ने जारी किया विज्ञापन

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पेगासस जांच पैनल ने गुरुवार को कहा कि जांच के लिए पिछले महीने सिर्फ दो व्यक्तियों ने मोबाइल फोन जमा किए हैं। इसलिए मोबाइल जमा करने की तारीख 8 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है। एक विज्ञापन में पैनल ने कहा है कि फोन कॉपी करते समय फोन का मालिक तकनीकी समिति के साथ बैठ सकते हैं।

न्यायमूर्ति आरवी रवींद्रन की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त पैनल का यह दूसरा विज्ञापन है। पहला विज्ञापन 2 जनवरी को अखबारों में छपा था। इसके जवाब में केवल दो व्यक्तियों ने डिजिटल चित्र लेने के लिए अपने मोबाइल उपकरणों का उत्पादन किया है।

इसलिए तकनीकी समिति एक बार फिर उन लोगों से अनुरोध करती है जिनको लगता है कि उनका मोबाइल उपकरण पेगासस स्पाइवेयर से संक्रमित है, वो लोग आगे आकर तकनीकी समिति से संपर्क करें। विज्ञापन में कहा गया कि जिनको लगता है कि उनका मोबाइल उपकरण पेगासस मैलवेयर से संक्रमित हो सकता है 8 फरवरी 2022 को या दिए ईमेल पर संपर्क करें। द पायनियर के पत्रकार जे गोपीकृष्णन ने 12 जनवरी को ही पैनल को एक मोबाइल फोन सौंप दिया था। पैनल को फोन जमा करने वाले एक अन्य व्यक्ति झारखंड के एक आदिवासी कार्यकर्ता रूपेश कुमार सिंह हैं। वह पेगासस विवाद की जांच के लिए शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता भी थे।

पैनल ने कहा कि जब एक उपकरण का उत्पादन किया जाता हैए तो उपकरण बनाने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में एक डिजिटल छवि ली जाएगी और उसके तुरंत बाद इसे बनाने वाले व्यक्ति को उपकरण वापस कर दिया जाएगा। मोबाइल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले व्यक्ति को एक डिजिटल इमेज कॉपी भी दी जाएगी। न्यायमूर्ति रवींद्रन ने पेगासस जांच पैनल का नेतृत्व किया जिसमें सलाहकार पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी और टेक्नोक्रेट सीनियर संदीप ओबेरॉय शामिल थे। तकनीकी समिति (शेष पेज 9)

हरियाणा में निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण पर रोक

भाषा। चंडीगढ़

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75 फीसदी आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के कानून पर बृहस्पतिवार को अंतरिम रोक लगा दी। इस फैसले से राज्य में काम कर रही निजी कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति अजय तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज जैन की पीठ ने फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और हरियाणा की एक अन्य एसोसिएशन की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।

इन याचिकाओं में कानून की वैधता को चुनौती दी गई थी। हरियाणा के अतिरिक्ता महाधिवक्ता जगबीर सिंह मलिक ने कहा कि अदालत के आदेश को राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। अदालत का यह आदेश क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है, जिनका मानना था कि इस कानून का भविष्य में उनके कामकाज और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। हरियाणा राज्य स्थानीय अभ्यर्थी रोजगार कानून, 2020 राज्य के नौकरी पाने के इच्छुक लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देता है। यह कानून 15 जनवरी से प्रभावी हुआ है। यह आदेश अधिकतम 30,000 रुपए से मासिक वेतन पाने वालों पर लागू होगा। राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण, 2019 विधानसभा चुनावों में जननायक जनता पार्टी का प्रमुख चुनावी घोषणा था।

चुनाव के बाद जजपा ने राज्य में भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार बनाई है। उच्च न्यायालय से अंतरिम स्थगनादेश मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री व जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट किया, हम हरियाणा के युवाओं के रोजगार अवसरों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। 75 फीसदी आरक्षण। यह कानून हरियाणा में स्थित निजी क्षेत्र की कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्ट, साझेदारी वाली लिमिटेड कंपनियों, साझेदारी फर्म, 10 से ज्यादा (शेष पेज 9)

तमिलनाडु के राज्यपाल ने नीट से छूट संबंधी राज्य सरकार का विधेयक लौटाया

भाषा। चेन्नई

तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने राज्य को राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (नीट) से छूट देने की मांग वाला विधेयक राज्य सरकार को लौटा दिया है। उन्होंने तर्क दिया है कि यह विधेयक ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के हितों के खिलाफ है। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्यपाल ने विधेयक और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावु को लौटा दी है। बयान के मुताबिक, राज्यपाल स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट से छूट देने से संबंधित साल 2021 के एलए बिल संख्या 43 और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन करने तथा सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए मेडिकल प्रवेश में सामाजिक न्याय की नीट पूर्व स्थिति पर गौर फरमाने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह विधेयक छात्रों, (शेष पेज 9)

बाजार

सेंसेक्स	58,788	↓ 770	
निफ्टी	17,560	↓ 219	
सोना	47,902	↑ 37	/10g
चांदी	61,102	↓ 536	/kg

क्विक न्यूज

सरकारी विभागों में 8.72 लाख पद रिक्त

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में एक मार्च 2020 तक 8.72 लाख पद रिक्त पड़े थे। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एकप्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक मार्च 2019 को 9,10,153 पद रिक्त पड़े थे जबकि एक मार्च 2018 को 6,83,823 पद रिक्त थे। उन्होंने कहा कि एक मार्च 2020 केंद्रीय सरकार के विभागों में 8,72,243 पद रिक्त पड़े थे। मंत्री ने कहा कि प्रमुख भर्ती एजेंसियों कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एवं रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2018-19 और 2020-21 में 2,65,468 भर्तियां की थी। उल्लेखनीय इतनी संख्या में रिक्त पद भरने की मांग उठती रहती है।

कर्नाटक के एक और कालेज में हिजाब पर पाबंदी से बढ़ा विवाद

भाषा। मेंगलुरु

कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुर में स्थित सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में बृहस्पतिवार को हिजाब पहनकर आईं मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज के प्राचार्य ने गेट पर ही रोक लिया। प्राचार्य ने छात्रों से कहा कि उन्हें कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है और उन्हें हिजाब उतारकर कक्षाओं में जाने को कहा। छात्रों ने प्राचार्य से बात की और उन्हें बताया कि यथास्थिति के सरकारी आदेश में कुंडापुर कॉलेज का जिक्र नहीं है। प्राचार्य ने उन्हें बताया कि सरकार की ओर से जारी परिपत्र पूरे राज्य में लागू होता है। कॉलेज में बुधवार को उस समय गंभीर स्थिति देखी गई थी जब कक्षाओं के अंदर छात्राओं के हिजाब पहनने के विरोध में लगभग 100 हिंदू छात्र भगवा चोला पहनकर कक्षाओं में आ गए थे। हालांकि, उन्होंने बृहस्पतिवार को अपना विरोध प्रकट नहीं किया। कुंडापुर के विधायक एच. श्रीनिवास शेट्टी द्वारा बुधवार को मुस्लिम लड़कियों और उनके माता-पिता के साथ बुलाई गई बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई और माता-पिता ने जोर देकर कहा कि उनके बच्चों को हिजाब पहनने का अधिकार है। इस बीच, राज्य के मत्स्य पालन मंत्री और उडुपी के जिला प्रभारी एस अंगारा ने उडुपी में संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार द्वारा कक्षाओं के अंदर हिजाब को प्रतिबंधित करने का आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए नियुक्त समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती। उन्होंने कहा, सभी को शिक्षण संस्थानों में निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना होगा। अलग-अलग संस्थानों में अलग-अलग ड्रेस कोड नहीं हो सकते।

संयुक्त किसान मोर्चा ने की भाजपा के खिलाफ वोट की अपील

- उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में गांव-गांव पहुंचेगा एसकेएम
- प्रेसवार्ता कर केंद्र सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप

अजीत तिवारी। नई दिल्ली

नई दिल्ली में गुरुवार को पत्रकारों को संबोधित करते किसान नेता

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा को वोट नहीं करने की अपील की है। इसके लिए एसकेएम के 57 किसान संगठन यूपी और उत्तराखंड के गांव-गांव में अपनी बात पर्चों के माध्यम से पहुंचाएंगे। एसकेएम ने केंद्र सरकार पर वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। ज्ञात रहे कि केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद दिल्ली की सीमाओं से डटे किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया था। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ हमारे 57 किसान संगठन यूपी के गांव-गांव में पहुंचेंगे। जहां किसानों और आम जनता से केंद्र सरकार द्वारा वादों को पूरा नहीं करने और वोट नहीं देने और भाजपा की सजा देने की अपील करेंगे। प्रेसवार्ता में एसकेएम के योगेंद्र यादव, दर्शनपाल और राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा अपने वादों से मुकर गई है। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी मंत्री अपने पद पर हैं। किसान आंदोलन में सरकार ने जिन वादों पर काम करने के लिए भरोसा दिलाया था, अब वह उन्हें भूल चुकी है। अब चुनाव में भाजपा को वही वादे याद दिलाने हैं। किसान नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोगों को बताया जाएगा कि भाजपा ने किसानों के साथ धोखा किया है। अभी तक सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश के 57 किसान संगठनों के साथ मिलकर एसकेएम के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अनेक गांवों में पहुंचेंगे। दूसरे व तीसरे चरण के लिए प्रचार इसी सप्ताह शुरू हो जाएगा।

किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं

भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं है। अगर कोई नेता ऐसा करता है तो उसका एसकेएम से कोई नाता नहीं होगा। एसकेएमए गांव-गांव में जाकर लोगों को पर्चा वितरित करेगा। इसमें भाजपा की किसान विरोधी नीतियों को खुलकर बताया जाएगा। एसकेएम नौ जगहों पर प्रेसवार्ता करेगी। इनमें मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, झांसी, सिद्धार्थनगर, बनारस, गोरखपुर व लखनऊ आदि शामिल है। दूसरे प्रदेशों के किसान नेता भी उप्र-उत्तराखंड जाएंगे। योगेंद्र यादव ने कहाकि हरियाणा और पंजाब से हजारों वालंटियर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में अपनी बात पहुंचाने के लिए गांव-गांव जाएंगे। एसकेएम किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगेगा। वह तो केवल लोगों से इतना कहेगा कि किसानों विरोधी भाजपा को सबक सिखाना है।

नोएडा की तीनों सीटों पर बैलेट मतदान शुरू

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद में 29 टीमों को ड्यूटी पर लगाया

● सुबह नौ से शाम 6 बजे तक चला मतदान घर-घर जाकर वोट ले रहे हैं कर्मचारी

● टीम के सदस्यों के साथ राजनीतिक दल का एक प्रतिनिधि भी शामिल

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

गौतमबुद्धनगर की तीनों विधानसभा सीटों पर गुरुवार से बैलेट मतदान शुरू हो गया है। जिले के 564 वोटर गुरुवार से अपना मतदान दे रहे हैं। सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली, शुक्रवार को यह मतदान प्रकिया पूरी होगी। इसको लेकर गौतमबुद्धनगर के जिला निर्वाचन अधिकारी ने 29 टीमों को ड्यूटी पर लगाया है। इसके अलावा हर एक राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे।

दरअसल, गौतमबुद्धनगर की नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए बैलेट मतदान शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने इस बार दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को बैलेट से मतदान करने का विकल्प दिया है। इसके लिए जनपद में पहले सर्वे किया गया।

ऐसे मतदाताओं से पूछा गया कि वह बैलेट से मतदान करेंगे या फिर पोलिंग बूथ पर आकर वोट डालेंगे। इस सर्वे में 564 मतदाताओं ने बैलेट से वोट डालने का निर्णय लिया।

गौतमबुद्धनगर के जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अपना मतदान करेंगे। इसके लिए 29 टीमें बनाई गई हैं। वैसे गौतमबुद्ध नगर में 7200 से ज्यादा दिव्यांग और 20 हजार से ज्यादा बुजुर्ग वोटर हैं, लेकिन इनमें से कुल 564 वोटर ही बैलेट पेपर पर अपना मतदान देने के लिए राजी हुए हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि इस चुनाव में नोएडा विधानसभा में 214, दादरी विधानसभा में 147 और जेवर विधानसभा में 203 दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता वोट डालेंगे। कुल मिलाकर जनपद में 564 वोटर गुरुवार से अपना मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से करेंगे। मतदान सुबह 9 बजे से शुरू हो गया, जो शाम 6 बजे तक चला।

प्रियंका ने हजारों फ्लैट मालिकों का उठाया मुद्दा

दादरी में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रदेश प्रभारी ने किया रोड शो

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हजारों फ्लैट बायर का बड़ा मुद्दा उठाया है। प्रियंका ने गुरुवार को दादरी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपक भाटी चोटीवाला के लिए रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने फ्लैट खरीदारों से बातचीत की। प्रियंका ने फ्लैट खरीदारों को आश्वासन दिया है कि कांग्रेस उनकी लड़ाई में हर संभव मदद करेगी। इसके बाद प्रियंका के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इस मुद्दे को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए।

पार्टी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार को दादरी पहुंची प्रदेश कांग्रेसी प्रभारी प्रियंका वाड्रा।

प्रियंका वाड्रा ने कहा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट में फ्लैट बायर्स के साथ खुलेआम अन्याय हो रहा है। कई सालों से उन्हें बिना रजिस्ट्री के अपने ही मकानों में किरायेदारों की तरह रहना पड़ रहा है। गलती बिल्डर्स की है। मिलीभगत प्रशासन और बिल्डर्स की है लेकिन भुगतना फ्लैट बायर्स को पड़ता है। नोएडा में जनसंवाद के दौरान फ्लैट खरीदारों को उन्होंने आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है और उनकी लड़ाई में हरसंभव मदद करेगी। गौतमबुद्ध नगर की 2 विधानसभा सीटों दादरी और नोएडा के लिहाज से यह बड़ा मुद्दा है। प्रियंका ने इस मुद्दे को उठाकर लाखों फ्लैट बायर्स का ध्यान कांग्रेस की ओर खींचने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाउसिंग सोसाइटीज में करीब एक लाख परिवार ऐसे हैं, जो अपने घरों में तो रह रहे हैं लेकिन उन्हें कानूनी रूप से अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला है।

कार में रखी ढाई लाख रुपये की नकदी बरामद

नोएडा। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने तथा चुनाव में धन का दुरुपयोग रोकने के लिए बनाई गई 'स्टेटिक टीम' ने बुधवार रात को सेक्टर 58 क्षेत्र के सेक्टर 60 के पास से एक कार से 2,50,000 रुपए बरामद किए। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) रणविजय सिंह ने बताया कि स्टेटिक टीम तथा थाना सेक्टर 58 के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सेक्टर 60 के पास संयुक्त रूप से जांच कर रहे थे, तभी एक कार में दुष्यंत गुप्ता नामक व्यक्ति आया। अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति की कार की तलाशी लेने पर उसमें 2,50,000 रुपए की रकम मिली। उन्होंने बताया कि बरामद रकम के बारे में गुप्ता उचित जवाब नहीं दे पाए। अधिकारी ने बताया कि रकम को जब्त कर लिया गया है और अब तक नोएडा पुलिस ने जांच के दौरान करोड़ों रुपए की रकम बरामद की है।

कुत्तों के अंतिम संस्कार के लिए पीएनजी शवदाह बनकर तैयार

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

कुत्तों के अंतिम संस्कार के लिए नगर निगम ने पीएनजी से चलने वाला शवदाह गृह बनाकर तैयार कर लिया है। राजनगर एक्सटेंशन मार्ग पर नंदी पार्क के पास बने शवदाह गृह तक आईजीएल ने गैस की पाइप लाइन बिछाकर ट्रायल कर लिया है। ट्रायल में मिली लीकेज व अन्य कमियों को दूर किया जा रहा है। जल्द ही इसका संचालन शुरू हो जाएगा।

दरअसल, जनपद में बड़ी संख्या में लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं। मौत के बाद पालतू कुत्तों के शवों का निस्तारण करने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

शवों को दफनाने के लिए जगह न मिलने और दूसरा कोई विकल्प न होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। नगर निगम ने दिल्ली की तर्ज पर आधुनिक शवदाह गृह बनाकर इस समस्या का समाधान किया है। निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण विभाग ने कुत्तों के शवों का निस्तारण कराने के लिए गैस आधारित शवदाह गृह बनवाया है।

अवतार सिंह भड़ाना के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

● थाना प्रभारी की शिकायत पर हुई कार्रवाई

जेवर से समाजवादी पार्टी-राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। यह एफ आईआर बुधवार को दनकौर कोतवाली में दर्ज हुई है।

भड़ाना के खिलाफ इससे पहले आदर्श आचार संहिता तोड़ने के आरोप में 3 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। बुधवार को दनकौर के कोतवाल सुधीर कुमार की ओर से अवतार भड़ाना और उनके डेढ़ सौ समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। भड़ाना पर मंगलवार रात अपने समर्थकों के साथ कनारसी गांव में ट्रैक्टर पर बैठकर चुनाव प्रचार करने, जुलूस निकालने और यातायात को अवरुद्ध करने का आरोप है।

गठबंधन प्रत्याशी ने अपने सैकड़ों समर्थकों संग कनारसी गांव में मंगलवार शाम जुलूस निकाला था। इस दौरान लोगों को असुविधा हुई थी। भड़ाना और उनके समर्थकों पर कोरोना महामारी अधिनियम और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का यह दूसरा केस दर्ज कराया गया है।

पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर बसपा प्रमुख ने बोला हमला

मायावती के भाषण में दिखा बबुआ के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

● एससी-एसटी को सपा ने पहुंचाया नुकसान

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती गुरुवार को कविनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और रालोद पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है।

इस बार विस चुनाव में बसपा 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही हैं। गाजियाबाद में भाषण के दौरान मायावती सबसे ज्यादा आक्रोशित दिखाई दीं। उनका गुस्सा सबसे ज्यादा अखिलेश यादव यानी कि बबुआ पर फूटा। मायावती ने इस दौरान कहा, जब समाजवादी पार्टी सरकार में आई तो अखिलेश यादव ने एससी-एसटी लोगों को सरकारी ठेकों में आरक्षण देना बंद कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने एससी-एसटी समाज के हितों में बिलों को फाड़ दिया था। इतना ही नहीं एससी-एसटी के छात्रों को भी समाजवादी पार्टी ने काफी नुकसान पहुंचाया है। जो छात्र विदेश में पढ़ाई करना चाहते थे, उन छात्रों को समाजवादी पार्टी ने विदेश नहीं जाने दिया। सपा ने पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। समाजवादी पार्टी झूठ बोलती है कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए काम किया है। मायावती ने आगे कहा, कांग्रेस ने दलितों और अति पिछड़ा वर्ग के लिए कोई कार्य नहीं किया। एससीएसटी समाज के लिए हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया है। समाजवादी पार्टी ने तो एससी-एसटी का आरक्षण ही खत्म कर दिया। इस बात को गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश की जनता कभी नहीं भूल सकती। समाजवादी पार्टी ने महापुरुषों का अपमान किया है। इसके अलावा समाजवादी सरकार ने अनुसूचित जाति के अफसरों का प्रमोशन रद्द कर दिया था और दलित समाज की योजनाओं को बंद कर दिया गया।

अखिलेश को गृहमंत्री शाह की चेतावनी

गाजियाबाद। यूपी विधानसभा चुनाव में दांव आजमा रहे राजनीतिक दल इन दिनों एक-दूसरे पर हमलावर हैं। गुरुवार को गाजियाबाद पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह के निशाने पर मुख्य रूप से सपा ही रही। लोनी में आयोजित भाजपा की जनसभा से गृहमंत्री शाह ने सपा प्रमुख को चेतावनी दे डाली। उन्होंने सख्त लहजा अपनाते हुए कहा, कल अखिलेश बाबू यहां आए, उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिए घर में रहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
ए -11, सेक्टर -24, नोएडा -201301

एन एफ एल NFL

लागत लेखा परीक्षा फर्मों की पूर्व-योग्यता और नियुक्ति के लिए निविदा

क्र.सं.	मद का संक्षिप्त विवरण
1.	एनएफएल की नंगल, बठिंडा, पानीपत और विजयपुर-I और II इकाइयों की लागत लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए पूर्व-योग्यता और लागत लेखा परीक्षा फर्मों की नियुक्ति के लिए निविदा का आमंत्रण और वर्ष 2022-23 के लिए सभी पांच इकाइयों की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समेकन।

विवरण के लिए हमारी वेबसाइट देखें: www.nationalfertilizers.com पूर्ण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **08.03.2022 अपराह्न 03.00 बजे तक** है।

वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

@NFL_Kisan @nationalfertilizers National Fertilizers Limited

क्यूबिकल फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 456, अग्रवाल मेट्रो हाइट, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
सीआईएन-एल65993डीएल1990पीएलसी040101
वेबसाइट : www.cubicalrealtors.com ई-मेल : cubfinsser@yahoo.com

31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही हेतु
अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण (रू. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त 12/31/2021 (अलेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 12/31/2020 (अलेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्त 31-03-2021 (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	19.73	45.04	131.19
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले	-1.19	18.12	27.99
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात	-3.52	16.27	20.52
4	इक्विटी शेयर पूंजी	1303.40	1303.40	1303.40
5	संचेय पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर	-	-	14.99
6	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (रू. 2/- प्रत्येक का)			
	मूल	-0.01	0.02	0.03
	तनुकृत	-0.01	0.02	0.03

नोट :- उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.cubicalrealtors.com पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
वास्ते क्यूबिकल फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता./-
दिनांकित : 3 फरवरी, 2022 मंजू गोयल (निदेशक)
स्थान : दिल्ली डीआईएन : 07143651

BEFORE **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL -I DELHI**
4th FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001

O.A.No. 148/2020 **Bank of India** (Applicant) Versus **M/s Saini Flour Mills & Ors.** (Defendants)

To, (1) M/S Saini Flour Mills, Through it's prop. Sh. Mukesh Kumar, 629, Dev Nagar Colony, 2 KM Stone, Jhajjar Road, Bahadurgarh, Haryana - 124507
(2) Mr. Mukesh Kumar s/o Sh. Vijay Singh R/o 22/632, Dev Nagar, Near I.T.I., Jhajjar Road, Bahadurgarh, Haryana - 124507
also at : R/o 22/629, Dev Nagar, Near I.T.I., Jhajjar Road, Bahadurgarh, Haryana - 124507
(3) Mrs. Indra Devi w/o Sh. Mukesh Kumar R/o 22/632, Dev Nagar, Near I.T.I., Jhajjar Road, Bahadurgarh, Haryana - 124507

Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of **Rs. 96,77,928.61 (Rupees Ninty six lakh seventy seven thousand nine hundred twenty eight and sixty one paisa only)** against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before Ld. Registrar on 24.03.2022 at 10:30 A.M. (for further details kindly visit DRT website **www.etribunal.gov.in** Phone Number : 011-23748473)

Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.

Due to ongoing **pandemic situation**, all the matters will be taken up through Video Conferencing and for that purpose :- (1) All the advocates/litigants shall download the **Cisco Webex** application/software; (2) **Meeting ID** and **password** for the next date of hearing qua cases to be taken by Registrar/Recovery Officer-1/and recovery officer-2 shall be available one day prior to the next date at DRT official portal i.e. **drt.gov.in** under the public notice head. (3) In any exigency qua that, the advocates/litigants can contact the concerned official at **Ph. No. 011-23748473.** Given under my hand and seal of this Tribunal on this 21st day of January, 2022.

By order of the Tribunal Asst. Registrar, DRT-1, New Delhi

Respondent may contact under mention phone number for further enquiry. : Mr. Amit K. Dar, Ld. Registrar, DRT-1, New Delhi Phone No. 011-23748473 E mail : drt1delhi-dfs@nic.in

झुग्गी में रहने वाला निकला एक करोड़ का मालिक

पूर्व आईपीएस के घर चार दिन चल रही छापे की कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

शहर के सेक्टर-50 में ए-6 स्थित पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह के घर पर चल रही आयकर विभाग की जांच बुधवार को लगभग पूरी हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार रेड में सिक्योरिटी वॉलेट के कई लोगों के अवैध धन मिला है।

विभाग के कर्मचारियों को मौके पर कई ऐसे लॉकर मिले हैं जो दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई निजी कंपनी में नौकरी करता है तो कोई झोपड़ी में रहता है और किसी का कोविड-19 में कुछ का देहांत हो गया।

लगभग जांच के दौरान 15 लॉकर जप्त किए गए हैं। इसमें से 8 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति बरामद कर ली गई है। आयकर विभाग बरामद रकम को सेक्टर 2 स्थित एसबीआई ब्रांच में आरबीआई बैंक अकाउंट में जमा करवाएगा।

दरअसल कुछ लोग जांच के दायरे में हैं। किराए पर लिए गए लॉकरों के मालिक जब जांच में शामिल नहीं हुए तो आयकर विभाग की टीम ने उनके पते पर पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। यहां एक लॉकर से बरामद 1 करोड़ रुपए जिसके नाम पर लिए हैं वह गाजियाबाद में किराए की झुग्गी में रहता है।

बताया जा रहा है कोरोना के दौरान लॉकर मालिक का देहांत हो गया था। विभाग की टीम गाजियाबाद में कुछ ठिकानों पर जल्द छापेमारी कर सकती है। वही आईपीएस का निजी तौर पर प्राइवेट लॉकर देने का काम बताया जा रहा है। मकान के बेसमेंट में लॉकर बने हुए हैं। इन्हीं में से किसी एक लॉकर में अघोषित नकदी होने की जानकारी आयकर विभाग को मिली थी। बीते 4 दिनों से पूर्व आईपीएस के घर छापेमारी जारी रही। रेड के दौरान इनकम टैक्स की टीम को बेसमेंट में मौजूद लॉकर से लगभग 5 करोड़ कैश और ज्वेलरी मिली है।

मिली जानकारी के मुताबिक इस घर में पूर्व आईपीएस अफसर का बेटा और बहू कभी.कभी रहने के लिए आते हैं। हालांकि दो दिन पहले पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनका बेटा प्राइवेट लॉकर रखकर उन्हें किराए पर देता है। अभी तक कोई ऐसी इनकम टीम को गैर कानूनी संपत्ति नहीं मिली है, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई हो।

कोरोना काल में गई नौकरी तो शुरू किया ठगी का धंधा

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

● साइबर सेल ने गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा

लोन दिलाने और क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साइबर सेल और लोनी पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 मोबाइल फोन और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी कोरोना काल में बेरोजगार होने के बाद से ठगी का काम शुरू कर दिया।

साइबर सेल प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि अशोक विहार लोनी निवासी मोहित ने 25 नवंबर को ठगी की शिकायत साइबर सेल में की थी कि 15 नवंबर को लोन दिलवाने के नाम पर उससे डेढ़ लाख रुपये की ठगी की गई है। साइबर सेल ने जांच करते हुए आरोपियों को ट्रेस कर लिया। पुलिस ने हापुड़ निवासी संदीप कुमार, धर्मेंद्र कुमार और बुलंदशहर के बागूवाला निवासी नितिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

मौसम ने फिर बदली करवट, ग्रेनो में बारिश के साथ पड़े ओले

रुक-रुककर हुई बरसात के साथ तेज हवा चलने से इलाके में बढ़ी ठंड

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

गुरूवार को फिर एक बार मौसम ने करवट बदल दिया है। बीते 2 दिनों से ठंड में राहत मिली थी, लेकिन सुबह दिल्ली-एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश और भारत के कई इलाकों में बारिश हुई। जिसकी वजह से ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। ग्रेटर नोएडा में गुरुवार की सुबह ओले भी पड़े हैं।

गुरुवार सुबह ग्रेटर नोएडा और नोएडा में बारिश के साथ ओले पड़े। जिसकी वजह से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। गुरुवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का तापमान न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर में बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही है। ठंड ज्यादा बढ़ने के कारण लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं। मौसम विभाग की मानें तो अगले करीब 2 दिनों तक हल्की बारिश और ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। बर्फीले इलाके और उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार और देहरादून में तापमान और भी ज्यादा कम हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 24 घंटे के दौरान और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती हैं।

बारिश होने के कारण पोलूशन का स्तर भी काफी ज्यादा कम हो गया है। जिसकी वजह से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदूषण के कारण लोगों को काफी दिक्कतें होती है। जब आप घर से निकलते हो तो सांस लेने में ही दिक्कत नहीं बल्कि आंखों में जलन जैसी समस्या भी पैदा होती हैं। हालांकि बारिश होने के कारण प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, यह राहत की बात है।

सार्वजनिक सूचना

ICICI Bank शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लि., तृतीय तल, प्लॉट नंबर 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत यह सूचना (दीवान हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को समनुदेशित अधोवर्णित समूह के संबंध में) डीएचएफएल तथा निम्नलिखित कर्जदार(रों) के बीच हुए ऋण अनुबंध के अनुसरण में मंजूर की गई आवास ऋण सुविधा के संबंध में प्रतिभूति के प्रवर्तन के विषय में जारी की जा रही है। उक्त कर्जदार/रों ने उनके द्वारा प्रतिभूत लेनदार से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के भुगतान में चूक की है और ये ऋण अनार्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए हैं। उनको उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित सूचना भेजी गई थी, जो बिना सुपुर्दगी वापस प्राप्त की जा चुकी है और इसलिए एतद्द्वारा उनको इस सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम/ऋण खाता संख्या (डीएचएफएल ओल्ड एलएएन एवं आईसीआईसीआई न्यूएलएएन) एवं पता	प्रत्याभूत आस्ति/प्रवर्तित की जाने वाली आस्ति का सम्पत्ति पता	प्रेषित सूचना की तिथि/सूचना की तिथि तक बकाया राशि	एनपीए तिथि
1.	गुलाब सिंह, कंचन सिंह, आरजैडएच-206, द्वितीय तल, बैक साइड गली नंबर 7, राज नगर -2, निकट पालम कालोनी, दिल्ली, खाता नंबर :- 9600001932 एवं क्यूजैडडीईएल00005039346	आरजैडएच-206, प्रथम तल (बैक साइड) केएच नंबर -62/20/2, ग्राम पालम गली नंबर 7, राज नगर -2, नई दिल्ली,	06-Jan-2022, रू 12,77,225/-	12/07/2021
2.	प्रमोद कुमार पात्रो, नमिता पात्रो, प्लॉट नंबर एफ-107-108, फ्लैट नंबर 6, प्रथम तल, आरएचएस मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली, खाता नंबर :- 2660000908 एवं क्यूजैडडीईएल00005019398	एफ 107 एवं 108, प्रथम तल, बैक साइड आरएचएस प्राइवेट नंबर 6, केएच नंबर 604, 605, 606, ब्लॉक-एफ, ग्राम नवादा, मोहन गार्डन एक्सटेंशन, उत्तम नगर, दिल्ली	06-Jan-2022, रू 10,62,191/-	31/08/2021
3.	पूरन रावत, वंदना रावत, आरजैड-686, एफ/16 ई, गली नंबर 6, कैलाश मानसरोवर आश्रम मार्ग, राज नगर पार्ट 1, पालम कालोनी, दिल्ली, खाता नंबर :- 27300000362 एवं क्यूजैडडीडब्ल्यूए00005008502	आरजैड 1/16, प्लॉट नंबर 16, केएच नंबर 59/16/1, तृतीय तल, छत अधिकार के साथ, ग्राम- पालम, राज नगर, नई दिल्ली	06-Jan-2022, रू 10,35,236/-	23/09/2021

सूचना प्रदान करने हेतु वैकल्पिक कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/रों तथा/अथवा उनके गारंटरों (जैसा लागू है) को बकाया राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आगे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे।

तिथि : 04 फरवरी, 2022 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : दिल्ली/एनसीआर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

गोलचक्कर पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक

नोएडा। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर गोल चक्कर पर गुरुवार को बड़ा हादसा टला गया। यहां गोल चक्कर पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और करीब 100 मीटर तक घिसटता हुआ गया। इस दौरान अनियंत्रित होकर पलटा हुआ ट्रक ऑटो में जा टकराया। ऑटो में बैठी सवारी को अचानक झटका लगा। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक युवती के सिर पर चोट आई है।

मिली जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत यह हादसा हुआ है। मौके पर लोगों ने बताया कि एक ट्रक मुड़ रहा था, उसी दौरान ट्रक पलट गया। लोगों का कहना है कि ट्रक काफी पहले पलट गया था और अनियंत्रित होकर दूर तक घसीटता आया।

सेक्टर-78 स्थित अंतरिक्ष बिल्डर का हाउसिंग प्रोजेक्ट

बिल्डर को आवंटित जमीन का प्राधिकरण ने ओसी किया रद्द

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

● अथॉरिटी को लोगों ने भेजी थी शिकायत

नोएडा अथॉरिटी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के सेक्टर-78 में स्थित अंतरिक्ष बिल्डर के हाउसिंग प्रोजेक्ट गोल्फ व्यू टू की जमीन का ओसी रद्द कर दिया। बिल्डर के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने अथॉरिटी को शिकायत दी थी। अथॉरिटी की टीम ने मौके पर जाकर जांच की और सुधार करने के लिए वक्त दिया था। बिल्डर ने नियत वक्त में सुधार नहीं किए। जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने नियोजन विभाग को ओसी रद्द करने का आदेश दिया।

नोएडा अथॉरिटी के महाप्रबंधक नियोजन इश्तियाक अहमद की ओर से बिल्डर को जारी किए गए निरस्तीकरण आदेश में कहा गया है कि हाउसिंग सोसाइटी का दौरा किया गया जिसमें कई बड़ी अनियमितताएं सामने आईं। इनका निराकरण करने के लिए वक्त दिया गया। बिल्डर की ओर से अनियमितताओं को दूर नहीं किया गया। जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने प्रोजेक्ट का ओसी रद्द करने का आदेश दिया।

यह भूखंड कलरफुल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को आवंटित किया गया था। इस पर अंतरिक्ष बिल्डर ने गोल्फ व्यू.2 नाम की हाउसिंग सोसायटी का निर्माण किया है। नोएडा अथॉरिटी के महाप्रबंधक का कहना है कि बिल्डर ने निर्धारित से ज्यादा कवर्ड एरिया हाउसिंग सोसायटी में बना रखा है।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक नरेन्द्र कुमार द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। कार्यकारी संपादक: नवीन उपाध्याय, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।

डीडीएमए की बैठक आज, खुल सकते हैं स्कूल व जिम

संजय राय। नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामले तेजी से कम हो रहे हैं और यहां लगातार दो दिन से संक्रमण दर पांच प्रतिशत से कम है। ऐसे में यहां भी स्कूल खोलने की इजाजत मिल सकती है तथा जिम समेत कुछ और व्यवसायिक गतिविधियों से शर्तों के साथ पाबंदियां हटाई जा सकती है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की 4 फरवरी को स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है, जिसमें जिम से लेकर स्कूल खोलने समेत अन्य राहत देने पर भी फैसला होगा। जिम मालिकों की मांग को देखते हुए माना जा रहा है कि बैठक में जिम खोलने के बारे में फैसला हो सकता है।

वहीं स्कूल खोलने के बारे में भी फैसला होगा। पहले चरण में 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल खोले जा सकते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों की राय के बाद यह तय होगा कि वरिष्ठ कक्षाओं के लिए स्कूल कौन सी तारीख से खोले जाएं। कोविड के कम होते केसों और छात्रों के टीकाकरण के बाद उम्मीद है कि अगले हफ्ते से बड़ी कक्षा के छात्रों को स्कूल जाने का मौका मिलेगा लेकिन शुरु में 50 फीसदी क्षमता का ही नियम लागू हो सकता है।

यानी एक क्लास में एक दिन में आधे छात्र-छात्राएं जाएंगे और दूसरे दिन में बाकी आधे पढ़ाई करेंगे। ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी अभी जारी रहेंगी।

सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को होने वाली बैठक में जिम और स्कूलों को खोलने के बारे में फैसला होना ही है, साथ ही शहर में शर्तों के साथ प्रदर्शनी, ऑडिटोरियम खोलने पर भी चर्चा हो सकती है। शुरु में ऑडिटोरियम में भी 50 फीसदी क्षमता का नियम लागू हो सकते हैं। दिल्ली सरकार भी इस पक्ष में है कि जिम को अब खोला जाना चाहिए।

साथ ही जिम असोसिएशन की ओर से भी लगातार मांग की जा रही है कि अब जिम को जल्द से जल्द शुरू करने का आदेश दिया जाना चाहिए।

विशेषज्ञों की राय के बाद 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू करने पर फैसला

बस-मेट्रो में भी खड़े सफर का मुद्दा

पर्यावरण बस सेवा के तहत निजी बसों के चलने से बसों में तो भीड़ कम हो रही है। लेकिन मेट्रो में व्यस्तम समय में बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। बस व मेट्रो में केवल बैठकर सफर करने की इजाजत है लेकिन व्यस्त समय में मेट्रो में लोग खड़े होकर भी सफर कर रहे है। कई स्टेशनों पर तो सुबह व शाम बहुत भीड़ होती है। ऐसे में बैठक में इस बात पर भी चर्चा होने की उम्मीद है कि क्या बस व मेट्रो में कुछ शर्तों के साथ खड़े होकर सफर की इजाजत दी जा सकती है। इससे पहले गत गुरुवार को हुई डीडीएमए की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू हटाने, बाजारों से ऑड- ईवन का नियम खत्म करने, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल को पचास फीसदी क्षमता के साथ शुरू करने, शादी समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने, सरकारी दफ्तरों में भी स्टाफ को बुलाने जैसे फैसले लिए गए थे। सूत्रों का कहना है कि डीडीएमए की बैठक में नाइट कर्फ्यू हटाने के बारे में भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही नाइट कर्फ्यू हटाने के बारे में फैसला लिया जाएगा। देश के कई राज्यों में नाइट कफ्यू हटाया जा रहा है। ऐसे में राजधानी में भी मामले तेजी से कम हो रहे हैं। अभी दिल्ली में रोजाना रात दस बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू है।

बकाया वेतन के लिए हड़ताल पर अड़े दयानंद अस्पताल के डॉक्टर

- निगमायुक्त ने की काम पर लौटने की अपील

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

बकाया वेतन को लेकर दयानंद अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हालांकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के निगमायुक्त विकास आनंद ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि पूर्वी निगम विषम आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे समय में भी निगम अपने कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है।

वहीं डॉक्टरों का कहना कि नवंबर, दिसंबर और जनवारी के वेतन को लेकर को ठोस आश्वासन निगमायुक्त की तरफ से नहीं दिया गया है। विकास आंनद ने कहा कि इस समय पूर्वी दिल्ली नगर निगम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में उनके समक्ष चुनौती है कि इस समय को अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिततम उपयोग करते हुए नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए।

आनंद ने अस्पताल के डॉक्टर्स को भरोसा देते कहा कि उन्हें फरवरी और मार्च का वेतन समय पर दिया जाएगा। साथ राशि की उपलब्धता के आधार पर मई माह में उनके बकाया एरियर्स का भी भुगतान किया जाएगा।

पूर्वी निगम हड़ताल पर गए डॉक्टर्स की उचित मांगो के प्रति संवेदनशील है और फंड उपलब्ध होने पर उनको पूरा करने के प्रति प्रतिबद्ध है। निगमायुक्त ने यह भी कहा कि अभी तक हड़ताली डॉक्टर्स की बर्खास्तगी के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं हुआ है।

शिक्षा संस्थानों, जिम से पाबंदी हटाए आप सरकार : कांग्रेस

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

डीडीएमए की 4 फरवरी को होने वाली बैठक में शैक्षणिक संस्थानों, जिम और नाइट कर्फ्यू हटाकर आम जनता और व्यापारियों को राहत देने का काम करना चाहिए।

यह अपील कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि डीडीएमए की बैठक में दिल्ली की जनता के हित में सीएम अरविन्द केजरीवाल चुनावी राज्यों के कार्यक्रम से समय निकालकर शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीडीएमए एक्ट के तहत महामारी के कारण बंद रहे बाजारों, संस्थानों को आर्थिक मदद देने का प्रावधान है।

दिल्ली सरकार इन व्यापारियों, दुकानदारों, संस्थानों और छोटे उद्योगों से जुड़े कारोबारियों को आर्थिक राहत प्रदान करें। दिल्ली के लोगों की सुगम जीविका चलाने के लिए विशेष राहत देने का फैसला लिया जाना चाहिए। पाबंदियों ने पिछले 2 वर्षों में सबसे अधिक नुकसान छात्रों की पढ़ाई का हुआ है। इसलिए स्कूल, कॉलेजों के साथ प्रतियोगी शैक्षणिक इंस्टीट्यूट को भी खोलने की इजाजत देने की मांग की।

आबकारी नीति के विरोध में जुड़ेंगे 1 करोड़ कार्यकर्ता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की नई अबाकारी नीति के विरोध में 4 फरवरी को होने वाली भाजपा की वर्चुअल रैली में एक करोड़ कार्यकर्ताओं जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नेतृत्व में विशाल वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ आंदोलन कारगर साबित रहा है, जिसके परिणामस्वरूप निगम द्वारा 300 से अधिक ठेकों को सील किया है। रिहायशी इलाके, विद्यालय एवं मंदिर के नज़दीक खुले शराब के ठेकों को दिल्ली सरकार 48 घंटों में बंद कर दे, अन्यथा भाजपा कार्यकर्ता, निगम के अधिकारियों साथ उन्हें सील कर देंगे।

संक्रमित मरीजों की संख्या में 60 फीसदी से अधिक कमी

- पिछले कुछ हफ्ते में मृतकों की संख्या में खास कमी नहीं आई

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कोविड-19 के संक्रमित मरीजों में पिछले एक सप्ताह में 60 फीसदी से अधिक की कमी दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से रोजाना मामलों की संख्या, संक्रमण दर और कई अन्य स्थितियों में सुधार हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ हफ्ते से मृतकों की संख्या में खास कमी नहीं आई है।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 26 जनवरी को 10.59 फीसदी संक्रमण दर के साथ रोजाना मामलों की संख्या 7498 और मृतकों की संख्या 29 दर्ज की गई। उस दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या 38,315 थी जबकि कुल मृतकों की संख्या 25,710 थी।

दो फरवरी को 4.73 फीसदी संक्रमण दर के साथ रोजाना मामलों की संख्या 3028 रह गई और मृतकों की संख्या 27 रही। उस दिन इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 14,870 रह गई जबकि मृतकों की कुल संख्या 25,919 हो गई।

इस तरह पिछले एक हफ्ते में 210 लोगों की मौत हुई जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या में करीब 61 फीसदी की कमी आई।

लगातार दूसरे दिन संक्रमण दर 5 फीसदी से कम दर्ज

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर लगातार दूसरे दिन पांच फीसदी से कम दर्ज की गई है। बृहस्पतिवार को 4.73 से घटकर 4.3 पर आ गई है। ऐसा करीब एक महीने के बाद हुआ है जब संक्रमण दर 5 प्रतिशत से कम हो गई है। इस दौरान बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,668 नए मामले सामने आए और कोविड-19 महामारी से 13 और मरीजों की मौत हो गई। संक्रमण की दर घटकर 4.3 प्रतिशत रह गई है। इसके साथ ही कुल मामले बढ़कर 18,38,647 हो गए तथा मृतकों की संख्या 25,932 पर पहुंच गई।

डिजिटल भुगतान के लिए पेटीएम गेटवे की दी सुविधा

नई दिल्ली। उत्तरी नगर निगम ने निगम सेवाओं के ऑनलाइन डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम गेटवे का शुभारंभ किया है। इस से सेवाओं के ऑनलाइन डिजिटल भुगतान में पारदर्शिता आएगी और नागरिकों को सुविधा होगी। निगम आयुक्त संजय गोयल ने गुरूवार को बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए पेटीएम गेटवे प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। डिजिटल माध्यम द्वारा भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और नागरिक कहीं से भी निगम सेवाओं का भुगतान कर सकेंगे। आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि नागरिक अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान पेटीएम गेटवे के माध्यम से कर सकते है।

तेज हवा व गरज के साथ हुई बूंदाबांदी, बढ़ी सर्दी

नई दिल्ली। राजधानी में एक बार फिर मौसम में अपना मिजाज बदल लिया है। तीन दिन की धूप के बाद आसमान में बादल छाये रहे और सुबह और शाम को गरज के साथ बारिश होती रही।

न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक, 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बावजूद वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में रही। सुबह आठ बजकर पांच मिनट पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 324 रहा। दिन में आसमान में बादल छाये रहे। इसके साथ ही गरज के साथ छींटे पड़ने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। ठंडी हवाएं के साथ लोगों को दिन भी ठंड का अहसान बना रहा है।

बारिश में यातायात को संभालते पुलिसकर्मी। फोटो रंजन डिमरी

दुकान से बदमाशों ने लूटे सोने और चांदी के आभूषण

- पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दक्षिणी दिल्ली जिले के संगम विहार इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने आभूषणों की दुकान से सोने-चांदी के गहने और इलेक्ट्रॉनिक सामान लूट लिया। पुलिस ने गुरूवार को यह जानकारी दी।

दुकान के मालिक ने पुलिस को बताया कि वह 1990 से आभूषणों का काम कर रहा है और उसे गुरूवार को ही घटना की जानकारी मिली।

दक्षिणी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त बेनिता जयकर के मुताबिक, दुकान का मालिक भी उसी इलाके में रहता है। दुकान पहुंचने पर उसने पाया कि वहां से 150 ग्राम सोना, 25 किलोग्राम चांदी, एक लैपटॉप और एक एलसीडी टेलीविजन गायब था।

पुलिस उपायुक्त ने कहा कि मामला दर्ज किया गया है और विस्तृत जांच की जा रही है।

पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए, इलाके में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। वहीं आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद आसपास के दुकानदारों में खासा रोष है।

कुकर व सिलेंडर से वार कर पत्नी की हत्या

- विवाहेत्तर संबंधों का था शक, थाने में जाकर खुद दी वारदात की जानकारी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाके में 26 वर्षीय एक युवक ने विवाहेत्तर संबंधों के संदेह में गुरुवार तड़के अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी के मुताबिक, आरोपी ने अपनी पत्नी के सिर पर कुकर और सिलिंडर से वार किया। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान तुगलकाबाद एक्सटेंशन निवासी हासिम खान के रूप में हुई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, हासिम गुरूवार की सुबह गोविंदपुरी पुलिस थाने आया और बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर हासिम की पत्नी शाहीन खान (20) बिस्तर पर मृत पाई गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी के सलमान नाम के एक युवक से विवाहेत्तर संबंध थे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला के सिर पर वार के लिए इस्तेमाल कुकर और सिलिंडर जब्त कर लिया गया है।

अधिकारी के अनुसार, पेशे से ऑटो चालक हासिम ने जून 2018 में शाहीन से शादी की थी और दोनों की कोई संतान नहीं थी।

कैंसर मरीजों को मिले एक छत के नीचे इलाज

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही सबकुछ लूट जाने की आशंका हावी हो जाती है। मरीज के साथ परिजनों की चुनौती बढ़ जाती है, इलाज के लिए बड़े शहरों व महानगरों की दौड़ और लंबा सिलसिला आर्थिक और मानसिक दोनों स्तर पर पीड़ा दायक होता है।

इस बार विश्व कैंसर दिवस 'क्लोज द केयर गैप' (सुविधाओं को पास लाना) की थीम पर मनाया जा रहा है। विश्व कैंसर दिवस कैंसर की थीम पर डॉ. कनिका सूद शर्मा, डायरेक्टर एंड क्लीनिकल लीड रेडिएशन आंकोलॉजी धर्मशिला कैंसर अस्पताल का कहना है कि कैंसर मरीजों को पूरा इलाज एक जगह मिलना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरे महानगरों व कुछ बड़े शहरों में ही कैंसर का इलाज संभव है। गांवों व छोटे कस्बों के कैंसर मरीजों को इस तरह दोहरी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

लंबी बीमारी को नजरअंदाज न करें

डॉ. कनिका सूद के अनुसार कैंसर से बचाव के लिए कोई भी बीमारी लंबे समय तक रहने पर इसे नजरअंदाज न करें। महिलाओं को ब्रेस्ट और सर्वाइकल स्क्रीनिंग 40 साल की उम्र के बाद हर साल करवाएं।

डॉ. कनिका

पंचकर्म चिकित्सा से बचाव संभव

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

तंबाकू, शराब, अनाज उत्पादन में रसायन का उपयोग और प्रदूषण जैसे कारणों के चलते कैंसर पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा है। कैंसर के इलाज और बचाव में आयुर्वेदिक चिकित्सा की भूमिका महत्वपूर्ण है।

कैंसर मरीजों को अगर समय रहते इलाज मिले और चिकित्सा पद्यति में आयुर्वेद को भी शामिल किया जाए तो मरने वालों की संख्या कम किया जा सकता है। यह कहना है आयुर्वेद विशेषज्ञ और पंचकर्म हॉस्पिटल प्रशांत विहार के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ आरपी पाराशर का। उनका मानना है कि आयुर्वेद व अन्य देशों की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रयोग से कैंसर चिकित्सा को मजबूती मिलेगी।

डॉ. पाराशर

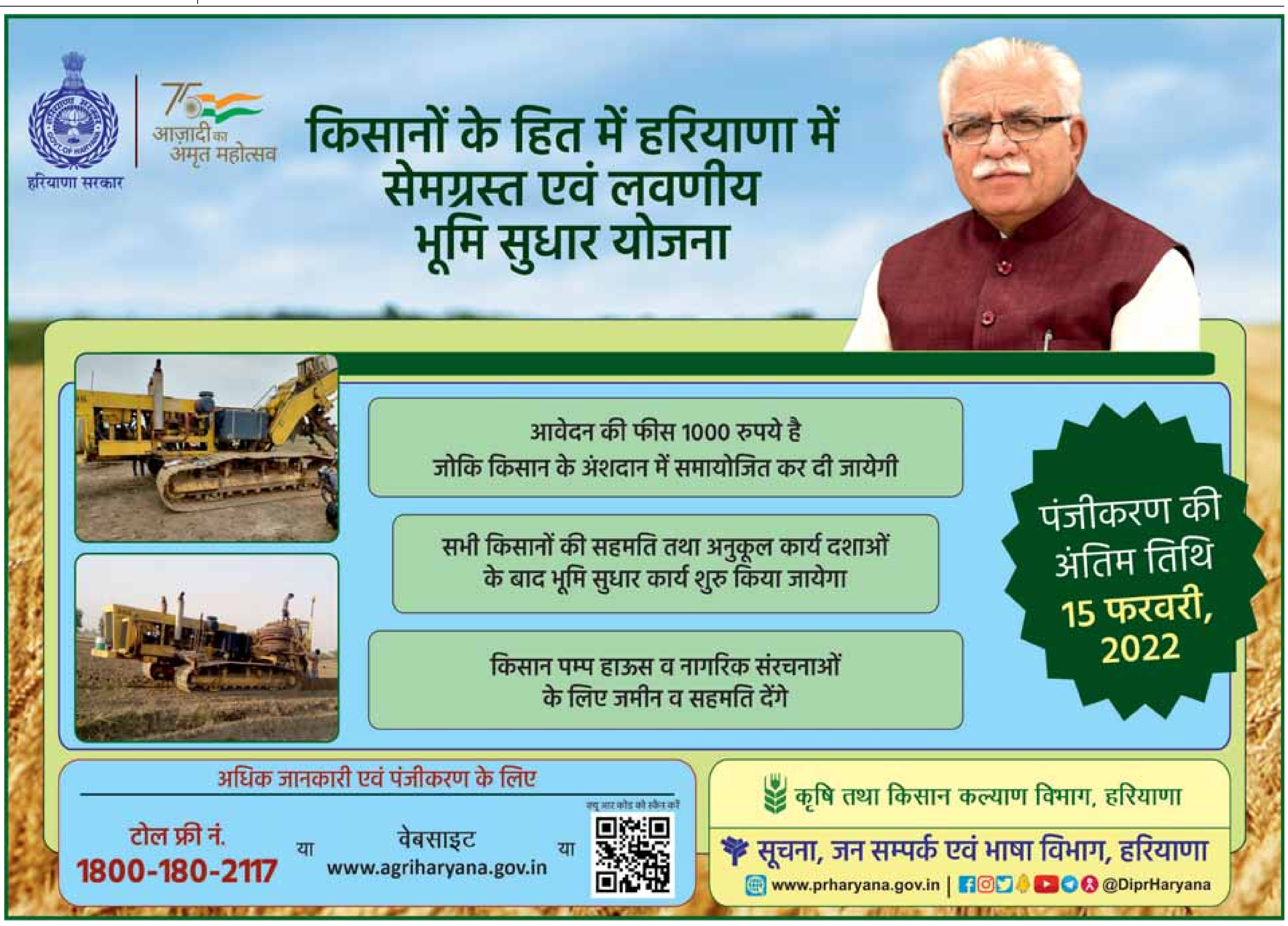

सीएम उड़नदस्ता ने तेल के टैंकरों से डीजल, पेट्रोल निकालते तीन पकड़े

काफी समय से मिल रही थी इस तरह की शिकायतें

आरोपियों में एक कैंटर चालक, एक सह-चालक व तीसरा खरीददार का नौकर

तेल के टैंकर से पेट्रोल, डीजल निकालने के आरोपी।

सोहना-पलवल रोड पर इसी टैंकर से निकाला जा रहा था तेल।

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम/सोहना

काफी समय से मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री उड़नदस्ता व डीएफएसओ गुरुग्राम की टीम ने गुरुवार को तेल के टैंकरों से पेट्रोल, डीजल निकालकर बेचने के तीन आरोपियों को पकड़कर इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सोहना-पलवल रोड पर बंद पड़े एक ढाबे पर टैंकरों से पेट्रोल, डीजल निकालते थे।

मुख्यमंत्री उड़नदस्ता गुरुग्राम को काफी समय से सूचना मिला रही थी कि सोहना क्षेत्र में तेल के टैंकरों के चालकों द्वारा टैंकरों से तेल चोरी करके बेचा जाता है। इसका भंडाफोड़ करने के लिए मुख्यमंत्री उड़नदस्ता गुरुग्राम द्वारा डीएफएसओ गुरुग्राम के साथ मिलकर सोहना-सोहना रोड पर एंजिलस प्लेस इंटरनेशनल स्कूल के पास बंद पड़े ढाबे पर रेड की इस दौरान देखा कि भारत पेट्रोलियम के टैंकर नंबर-एचआर-84-4196 के चालक द्वारा अपने टैंकर से तेल चोरी से निकाला जा रहा है। टीम ने मौके पर इस वारदात में शामिल सभी को काबू किया।

65 रुपये लीटर के हिसाब से बेचते थे डीजल

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि तेल के टैंकर चालक इस बंद पड़े ढाबे पर तेल निकालकर ढाबे के मालिक कृष्ण पुत्र जयप्रकाश को 65 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बेचते थे।

आरोपी इस डीजल को पेट्रोल पम्प रेट से कुछ दाम कम करके बेच देते थे। यह काम काफी समय से किया जा रहा था। आरोपी ने यह भी बताया कि इसके अलावा एलपीजी गैस की गाड़ियों के चालक भी इनको गैस नोजल लगाकर कॉमर्शियल सिलेंडर भरवाकर दिया करते थे।

मौके से डीजल, पेट्रोल से भरे ड्रम बरामद

मुख्यमंत्री उड़नदस्ता में शामिल इंद्रजीत के मुताबिक मौके पर आरोपियों के कब्जे से 200 लीटर वाले 5 ड्रम डीजल के भरे हुए, 2 ड्रम पेट्रोल के भरे हुए बरामद किए गए हैं। इनमें लगभग 1400 लीटर पेट्रोल व डीजल भरा है। इसके अलावा 3 भरे हुए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर व 20 खाली कॉमर्शियल गैस सिलेंडर समेत कुल सिलेंडर 23 सिलेंडर व गैस चोरी में प्रयोग किये जाने वाले बर्नर व नोजल लगी हुई 10/15 फीट लंबी 2 पाइप बरामद की गई। भारत पेट्रोलियम के टैंकर में कुल 24 केएल डीजल था, जिसमें से चालक द्वारा 23 लीटर डीजल उतारा जा चुका था। आरोपियों के खिलाफ सोहना शहर थाना में केस दर्ज किया गया है।

इन्हें किया गया है गिरफ्तार

मौके पर जाहिद पुत्र बब्बल (तेल टैंकर चालक) निवासी बनन चंदा थाना नगर जिला भरतपुर राजस्थान, वकील पुत्र इकबाल (सह-चालक) निवासी गांव खोल थाना फिरोजपुर जिला नूंह, यूसुफ पुत्र दीनू निवासी गांव साचौली थाना सदर सोहना को गिरफ्तार किया गया। इनमें यूसुफ पुत्र दीनू तेल के खरीददार ढाबे के मालिक कृष्ण पुत्र जयप्रकाश निवासी रोजकामेव जिला नूंह का नौकर है। कृष्ण कुमार मौके पर नहीं मिला।

तैमूरपुर में शिविर लगाकर जांची ग्रामीणों की सेहत

गांव तैमूरपुर में ग्रामीणों की जांच करते चिकित्सक व समाजसेवी राजेश भट्ठी को मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्य सम्मानित करने के बाद बैठे हुए।

पायनियर समाचार सेवा। रोहतक

मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से किया गया आयोजन

मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से जिले के गांव तैमूरपुर (जेठपुर) में जांच शिविर लगाया गया। जिसमें ग्रामीणों को नि:शुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। शिविर में ग्रामीणों की ऑक्सीजन, बीपी, शुगर, गठियाबाय, समेत अनेक तरह की जांच की गई।

इस अवसर पर मानव उत्थान सेवा समिति के जिला प्रमुख डा. विरेंद्र स्वामी ने ग्रामीणों की जांच की। इस कार्यक्रम में समिति की तरफ से समाजसेवी राजेश भट्ठी को यहां सम्मान पत्र दिया गया। उनके प्रयासों से क्षेत्र के अनेक गांवों में शिविर लगाकर लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। राजेश भट्ठी ने कहा कि वे लोगों की सेवा में भविष्य में भी इसी तरह से कार्यरत रहेंगे। साथ ही गांव के बच्चों, युवाओं को भी वे इस काम के प्रति प्रेरित करते हैं। जिला प्रशिक्षक प्रमुख राजेश भट्ठी ने इस शिविर में विशेष सहयोग दिया। डा. विरेंद्र स्वामी ने कहा कि राजेश भट्ठी काफी समय से समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। शिविर में मानव उत्थान सेवा समिति के हरिओम शर्मा, शाखा के प्रधान चांद सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इस दौरान विजय, राजिंद्र, नंबरदार हरबंस लाल, पंच सुरेंद्र भट्ठी, समाजसेवी दीपचंद भट्ठी, वेदप्रकाश, कृष्ण मेहरा, सतबीर सिंह, जगदीश, श्रीभगवान, कान्हूराम, अर्जुन चौकीदार, संदीप, प्रदीप, मनोज, नितिन मदान समेत काफी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार

महिला से बदसलूकी करने के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

सोहना। भोंडसी की स्नेह विहार कॉलोनी में आम रास्ता में सफाई के दौरान व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ अभद्र शब्दों में गालियां देते हुए गलत नीयत से छेड़छाड़ की। पीड़िता महिला ने पड़ोसी पर आम रास्ते में अवैध कब्जा करने का आरोप भी लगाया है। स्नेह विहार कॉलोनी में रहने वाले वेद प्रकाश के खिलाफ महिला ने भोंडसी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता महिला ने पुलिस को बताया कि कॉलोनी के आम रास्ता में आरोपी वेदप्रकाश ने अवैध कब्जा किया हुआ था। जिससे अदालत के माध्यम से वे केस जीत चुके है। इसके बावजूद वेदप्रकाश आम रास्ता में बार-बार अवैध कब्जा करता है। बुधवार को वह आम रास्ता में सफाई कर रही थी। तभी वेदप्रकाश अपने घर से बाहर निकला और उसे अभद्र शब्दों में गालियां देने लगा। उसके ऊपर गलत आचरण का आरोप लगाते हुए सीने पर हाथ चलाएं। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।

सड़क हादसे में घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ा

सोहना। चार दिन पहले सड़क हादसे में घायल सोहना निवासी 19 वर्षीय युवक ने गुरुग्राम के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव को गुरुवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। सोहना के वार्ड-15 निवासी मोहित सिंगला पुत्र बिरेन्द्र सिंगला 29 जनवरी को अपने दोस्त योगेश के साथ गुरुग्राम बाइक पर जा रहा था। जब वह गुरुग्राम-सोहना मार्ग पर गांव धुनेला के पास पहुंचा तो अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक पर सवार मोहित सिंगला व योगेश को चोट लगने के दौरान भोंडसी के निजी अस्पताल में दाखिल कराया। जहां से मोहित सिंगला को गंभीर हालत में अस्पताल से डॉक्टरों द्वारा रेफर कर दिया। मोहित को परिजनों ने गुरुग्राम के निजी अस्पताल में दाखिल कराया। जहां बुधवार की दोपहर बाद मोहित सिंगला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृत मोहित सिंगला के चाचा विकास सिंगला की शिकायत पर भोंडसी थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। गुरुवार को पुलिस ने मृत युवक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया।

हमें बता दो किस पथ जाएं, जहां प्रेम विश्वास हो...

गुरुग्राम। हमें बता दो किस पथ जाएं जहां प्रेम विश्वास हो, द्वेष न हो न ईर्ष्या हो, न ही घात-प्रतिघात हो...। अपनी कविता के माध्यम से कवयित्री आभा कुलश्रेष्ठ ने वर्तमान समय पर अपनी कविता की इन पंक्तियों से कटाक्ष किया। महिला काव्य मंच गुरुग्राम इकाई की मासिक डिजिटल काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें कवियों ने अपनी श्रेष्ठ रचनाएं पढ़ीं। कवि नरेश नाज ने सुनाया-मेरे प्यारे देश वासियों सुनो देश का हाल, लगे अगर मैं सच कहता हूं तुम भी देना ताल...। नियति ने सुनाया-सितंबर,अक्टूबर, दिसम्बर, कहां हैं नवम्बर...। डॉ. ज्योति राज ने सुनाया-बचकर रहना चमचों से ए अफसर कुर्सी पर बैठे, कर देंगे ये ढोलबजाई जो तुम्हारे दिल में पैठे...। वीणा अग्रवाल ने सुनाया-हम चाहते हैं आपकी ऊंची उड़ान हो, पैरों तले जमीन अरु सोच में आसमान हो, एक दिन बच्चा-बच्चा जाने आपको यहां कदम सोच कर रखना, जिनके निशान हो...। दीपशिखा श्रीवास्तव दीप ने सुनाया-तेरे अनुराग राग-गीत-उमंग शेष ना रहे, अपना मिलन पासंग, आज हो रहा मन मकरंद लग जा गले कि कर दूं तुझे बसंत...। डॉ. मुक्ता मिश्रा ने सुनाया-इंसान मिट्टी से उपजा मिट्टी में उसे मिल जाना है, मत गुरुर कर बंदे एक दिन सबने यह जग छोड़ वहीं पर जाना है...। कृपाल कौर छाबड़ा ने सुनाया-क्षुद्र कम तेरी माटी का मां तेरी माटी का कण हूं...। राजपाल यादव ने सुनाया-जाती हो क्यों रूठ के मुझे जरा ये समझना सीधे सादे मानुष को नहीं बेगम अब तुम भटकाना...। सविता स्याल ने सुनाया-इक सुन्दर भारत बनाना है...। शंकुतला मित्तल ने सुनाया-राम नाम जपती रहूं, छूटे कभी न ध्यान, संकट में भी कंठ में, रहे राम का नाम...। गुरुग्राम इकाई की महासचिव अंजू सिंह ने सभी साहित्यकारों का धन्यवाद किया।

कोरोना से माता-पिता को खोने वाले बच्चों की पालनहार बनी सरकार

गुरुग्राम। कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की मनोहर सरकार पालनहार बनी है। प्रदेश सरकार ने ऐसे अनाथ बच्चों की हर तरह की मदद के लिए प्रदेशभर में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष तक 2500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। जिला उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने बताया कि योजना के तहत बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों के आवर्ती जमा खाते खोले जाएंगे। जिसमें 18 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये जमा करवाने का प्रावधान किया गया है। इन बच्चों को सरकार ने अन्य खर्चों के लिए 12 हजार रुपये वार्षिक देने का निर्णय भी लिया है। किशोरियों को कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय में नि:शुल्क स्कूली शिक्षा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त किशोरियों के खाते में 51 हजार रुपये जमा किए जाएंगे। विवाह के समय ब्याज सहित शगुन दिया जाएगा। बच्चों के माता-पिता अथवा उनमें से किसी एक के कोरोना के कारण निधन होने से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसे बच्चों के लालन-पालन पर बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत सरकार उनकी देखभाल करेगी। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत यह प्रक्रिया पूरा करने के लिए पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं। कोरोना से माता-पिता को खाने वाले सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा के तहत 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। 18 वर्ष की आयु तक के इन बच्चों के प्रीमियम की राशि का भुगतान पीएम केयर द्वारा किया जाएगा।

वोटर आईडी और पहचान पत्र शिविर का 200 लोगों ने लिया लाभ

शिविर का शुभारंभ करते गगन गोयल व आशा गोयल।

गुरुग्राम। कैनविन फाउंडेशन के सहयोग से गुरुवार को यहां वार्ड-18 के अंतर्गत नया बाजार स्थित चूड़ी वाली गली के प्राचीन शिव मंदिर में एक शिविर आयोजित किया गया।

इस शिविर में वोटर आईडी और पहचान पत्र बनाए गए। करीब 200 लोगों ने इस शिविर का लाभ लिया। भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गगन गोयल एवं समाजसेविका आशा गोयल ने यहां लोगों को अपने कागजात बनवाने व सरकारी योजनाओं के बारे में बताया।

गगन गोयल एवं आशा गोयल ने कहा कि कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डा. डीपी गोयल एवं सह-संस्थापक नवीन गोयल द्वारा लगातार शहर में कोरोना रोधी टीकाकरण कैंप, वोटर आईडी एवं पहचान पत्र कैंप समेत अन्य कार्यों को लेकर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी अनेक लोग ऐसे हैं।

रिटायर्ड ओमप्रकाश का पर्यावरण सेवा रहेगी जारी

बीडीपीओ कार्यालय से उपाधीक्षक पद से सेवानिवृत हुए हैं ओमप्रकाश

पायनियर समाचार सेवा। भिवानी

सेवानिवृत्ति पर उपाधीक्षक ओमप्रकाश को स्मृति चिन्ह भेंट करते स्टाफ के सदस्य।

टहनी टूटे क्षमा मांगने वाली प्रथा चलाऊंगा, चली कुल्हाड़ी अगर तने में इंकलाब चिल्लाऊंगा, आंदोलन की मांग उठी तो चिपको फिर से गाऊंगा, पग-पग चलकर क्षण-क्षण अपना पर्यावरण बचाऊंगा...। ऐसी ही सोच के साथ अपने सेवाकाल में पर्यावरण के प्रति काम करते रहे उपाधीक्षक ओमप्रकाश। ओमप्रकाश भगवान शिव के नाम ओम के प्रकाश से बना है। यह शहर की उस शख्सियत का नाम है, जिसने सरकारी सेवा में रहते हुए अपने नाम को सदा प्रकाशमान रखा। बीडीपीओ कार्यालय से उपाधीक्षक पद से सेवानिवृत हुए ओमप्रकाश से सीख सकते हैं कि हमें नौकरी के साथ क्या ऐसा करना चाहिए, जो पीढ़ियों तक स्मरण रह सके।

सात अक्टूबर 1981 को शुरू हुई थी सेवा : सात अक्टूबर 1981 को डीसी कार्यालय भिवानी में बतौर स्टेनो टाइपिस्ट (एडहॉक) उनकी नौकरी लगी थी। 23 दिसम्बर 1982 तक वे डीसी कार्यालय में रहे। पांच महीने एसडीएम सिवानी में स्टेनो रहे। इसके बाद 9 फरवरी 1983 को वे नियमित हुए और बीडीओ कार्यालय में नियुक्ति हुई। वर्ष 1987 में उनका तबादला दादरी, 1989 में तबादला तोशाम, 1996 में जिला परिषद हिसार और इसी साल ही उनका तबादला जिला परिषद नारनौल हुआ। वर्ष 1999 में वे जिला परिषद भिवानी में आ गए। दिसम्बर 2000 में वे परमोट होकर अकाउंटेंट बनें। वर्ष 2001 में जिला परिषद से एडीसी कार्यालय भिवानी, वर्ष 2004 में बीडीओ कार्यालय कैरू में रहे।

वर्ष 2006 में सीपीएस धर्मबीर के बने पीएम : फरवरी 2006 में वे मुख्य संसदीय सचिव बने धर्मबीर सिंह के पीए के रूप में डेपुटेशन पर लगाए गए। वर्ष 2014 में धर्मबीर सिंह के सांसद बनने के बाद वे भिवानी ब्लॉक में आ गए। वर्ष 2015 में वे पंचायती राज कार्यालय के एक्सईएन कार्यालय में आए और 2017 तक उनकी नियुक्ति रही। इसके बाद फिर से वे बीडीपीओ कार्यालय भिवानी में चले गए।

दिल्ली-एनसीआर में अधेड़ उम्र की महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से ज्यादा प्रभावित

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

यहां पिछले तीन-चार साल में ब्रेस्ट कैंसर के केसों में 50 फीसदी बढ़ोतरी हुई

35 से 50 वर्ष उम्र की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा

भारत में कैंसर के कुल केसों में 14.8 फीसदी ब्रेस्ट कैंसर

विश्व कैंसर दिवस पर विशेष

दिल्ली-एनसीआर ब्रेस्ट कैंसर का केंद्र बनता जा रहा है। यहां पिछले तीन से चार सालों में ब्रेस्ट कैंसर के केसों की संख्या में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहां अधेड़ उम्र (35-40 साल) की महिलाओं में यह कैंसर अधिक हो रहा है। वर्ष 2020 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम (एनसीडीआईआर) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कैंसर में 14.8 प्रतिशत ब्रेस्ट कैंसर होने का अनुमान है।

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के अस्पतालों में अधेड़ उम्र की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के केस बढ़ रहे हैं। पिछले तीन से चार सालों में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ब्रेस्ट कैंसर स्किन कैंसर के बाद महिलाओं में होने वाला सबसे ज्यादा कैंसर है। कोरोना महामारी ने ब्रेस्ट कैंसर के केसों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि इस बीमारी का डायग्नोसिस अब फाइनल स्टेज में हो रहा है। अधेड़ उम्र की महिलाओं विशेष रूप से पोस्ट-मेंनोपॉजल महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए चिकित्सक समय-समय पर परीक्षण और सेल्फ टेस्टिंग (आत्म-परीक्षा) की सलाह देते हैं।

शराब और गर्भ निरोधक के सेवन से भी दिक्कत

अध्ययनों (रिसर्च) से पता चला है कि शराब और ओरल गर्भ निरोधकों के अंधाधुंध सेवन से युवा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के केसे भी बढ़ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर होने के पीछे कई कारण है, जिसमें देर से शादी करना, जोकि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में होना आम है। इसके अलावा अधिक उम्र में बच्चे पैदा करना भी इसका कारण है। कुछ केसों में इसे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थैरेपी को भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना कम हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में हर साल ब्रेस्ट कैंसर से मरने वाली 6 लाख 85 हजार महिलाओं में से 90 हजार से ज्यादा महिलाएं भारत से होती हैं। भारत में कैंसर से संबंधित मौतों का सबसे आम कारण ब्रेस्ट कैंसर है।

2025 तक कैंसर केसों में होगी 12 फीसदी वृद्धि: डा. नीतेश

फोर्टिस अस्पताल में सीनियर डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी डा. नीतेश रोहतगी के अनुसार आईसीएमआर का अनुमान है कि 2025 तक भारत में ब्रेस्ट कैंसर सहित कैंसर के केसों में 12 प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर समय पर इसका डायग्नोसिस किया जाए तो इस कैंसर का इलाज सबसे अच्छे से किया जा सकता है। अगर कैंसर का जल्दी पता नहीं लगता है तो यह जानलेवा हो सकता है। भारत में महिलाओं की जांच के लिए क्लीनिकल ब्रेस्ट जांच (सीबीई) सबसे आम तरीका है, क्योंकि इसमें किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राफी और ब्रेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी (यूएसजी) का भी इस्तेमाल किया जाता है।

इनोवाना ग्रुप ने लॉन्च किया एनीटाइम एस्ट्रो

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

Anytime Astro

भारत की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी इनोवाना ग्रुप ने हाल ही में एनीटाइम एस्ट्रो, एक ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी पोर्टल लॉन्च किया है। जो अपने ग्राहकों को भारत के प्रशंसित ज्योतिषियों से जुड़ने और उनसे परामर्श करने में मदद करेगा।

इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यूजर लाइव कॉल या चैट सेशंस के माध्यम से ज्योतिषीय परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। इस उपयोग में आसान प्लेटफॉर्म में इंडस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों की कई केस स्टडीज और इंटरव्यू की मदद से जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूजर को एनीटाइम एस्ट्रो के माध्यम से सबसे अच्छी भविष्यवाणियां और परामर्श प्राप्त हों।

यूजर, मोबाइल एप्लिकेशन व वेबसाइट के माध्यम से एनीटाइम एस्ट्रो की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। एप्लिकेशन एंड्राइड और आईओएस दोनों के लिए उपलब्ध है। एनीटाइम एस्ट्रो उपयोग करने के लिए बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। अपनी वेबसाइट या एप्लिकेशन में लॉग इन करने के बाद, यूजर को कई उच्च अनुभवी ज्योतिषियों की सूची मिलेगी। उन्हें वेरीफाईड ज्योतिषियों से लाइव गाइडेंस मिलेगा जहां वे अपने भविष्य के बारे में पूछताछ कर सकेंगे या समाधान पाने के लिए अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकेंगे। यदि उस समय उनकी पसंद का ज्योतिषी ऑफलाइन है तो यूजर मैसेज भी छोड़ सकते हैं और अपने सत्र को प्री-बुक कर सकते हैं।

इनोवाना ग्रुप के चेयरमैन और एमडी चंदन गर्ग ने कहा, एनीटाइम एस्ट्रो के लॉन्च के साथ, हमारा उद्देश्य ज्योतिषीय गाइडेंस को सभी के लिए सुलभ बनाना है। हमारा लक्ष्य उन सभी तक पहुंचना है जो कठिन दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों के साथ ऑनलाइन परामर्श करने में सक्षम बनाना है।

एनीटाइम एस्ट्रो की प्रमुख विशेषताओं में से एक ''टॉक टू एस्ट्रोलॉजर'' है। यह पारंपरिक ज्योतिषीय परामर्शों के लिए एक आधुनिक तरीका है, जहां लोगों को अपनी भविष्यवाणियां प्राप्त करने के लिए ज्योतिषियों के पास जाना पड़ता था। यह सेवा यूजर को फोन के माध्यम से एनीटाइम एस्ट्रो के साथ पंजीकृत प्रसिद्ध ज्योतिषियों से परामर्श करने और अपने स्वयं के घर के आराम से तुरंत व्यक्तिगत उत्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। इसकी कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

वैरीफाईड ज्योतिषी: यूजर अपने प्रश्नों का उत्तर केवल जेन्युइन और वैरीफाइड ज्योतिषियों से ही प्राप्त कर सकेंगे।

सेव्ड सेशंस: यूजर के चैट, कॉल और मैसेज को उनके भविष्य के लिए अलग से सेक्शन है।

24/7 उपलब्धता: एनआरआई दर्शकों के लिए भी उनकी सेवा उपलब्ध कराने के लिए, एनीटाइम एस्ट्रो 24/7 परामर्श प्रदान करता है।

सुरक्षित और निजी परामर्श: एनीटाइम एस्ट्रो के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे अपने सभी परामर्शों के लिए गोपनीयता बनाए रखते हैं। इसके ग्राहकों की पहचान और उनके परामर्श का कारण अत्यधिक गोपनीय रखा जाता है।

एक ही स्थान पर इंडस्ट्री के विशेषज्ञों से जुड़ें : एनीटाइम एस्ट्रो कई ज्योतिषियों से जुड़ा होता है, जो ज्योतिष के कई क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं।

युवाओं को एक सकारात्मक दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा देती हैं ये पुस्तकें

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रोमिला देवी सुदर्शन द्वारा लिखित पुस्तक मेरा तो ये मैं भी नहीं एक पुस्तक का सारांश है जिसे उन्होंने 2008 में 2.3 दिनों में लिखा था और समय के साथ उसे खो दिया, लेकिन प्रोमिला ने उन विचारों को याद किया और 8 दिनों में अपने शब्दों में फिर से लिखाए लगभग आधा घंटा हर दिन। प्रोमिला दो बच्चियों की मां हैं और वह बहुत व्यस्त रहती हैं। अपने व्यस्त दिनचर्या से अपना समय निकालना एक चुनौतीपूर्ण काम है। वह किसी तरह अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए स्वयं को एक राही की तरह आगे बढ़ाने में तत्पर हैं। वह उन सभी सपनों को सच करना चाहती हैं जो उन्होंने बचपन से देखे हैं। जिसके लिए वह हर दिन प्रयासरत है।

पुस्तक: मेरा तो ये मैं भी नहीं
लेखिका: प्रोमिला देवी सुदर्शन

लड़कियों के प्रति समाज की कुंठित मानसिकता के विरुद्ध लड़ने का हौसला रखने वाली आनंदी, जिसने कम उम्र से ही अपनी विलक्षण बुद्धिए समाज की कुरीतियों से लड़ने की शक्ति एवं निर्भीक होने का प्रतीक होने की योग्यता प्रदर्शित कर दी थी। संघर्षमय जीवन और गरीबी के परिवेश से जूझते हुए शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता का दामन थाम कर संपन्नता की ओर कदम बढ़ाती एक औरत की कहानी है आनंदी। विषम परिस्थितियों में बुलंद हौसलों के साथ अपने अस्तित्व के लिए लड़ना सिखाती है आनंदी।

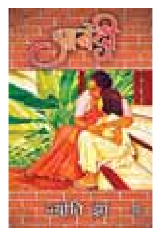

पुस्तक: आनंदी
लेखिका: ज्योति झा

लेखिका लक्षिता भार्गव द्वारा लिखित पुस्तक शिमक्सड इमोशंसश् में बाल कहानी का संग्रह है। जिसमें दो चचेरी बहनें एक वास्तविक लंबी अवधि के बाद एक-दूसरे से मिलती हैं। यह पुस्तक बच्चों के लिए एक सुंदर काल्पनिक कहानी के साथ-साथ अपने असाधारण और अद्भुत चित्रण से आपको विस्मित कर सकती है। इसके अलावा, इसमें एक भी संदेह नहीं है कि यह पुस्तक अविश्वसनीय है और कुछ ऐसा है जिसे बच्चों के लिए एकदम उपयुक्त माना जा सकता है! इस पुस्तक की विशिष्टता उन दृष्टांतों में है। जो पुस्तक के अंदर मौजूद हैं। इस पुस्तक का लगभग हर एक पृष्ठ कुछ दृष्टांतों को चित्रित करता है, जो पुस्तक के अंदर की कहानियों को एक आदर्श विषय देता है। जिस तरह से ये दृष्टांत पूरी किताब में मौजूद हैं, वह बस लीक से हटकर विचार को दर्शाता है।

पुस्तक: मिक्स्ड इमोशंस
लेखिका: लक्षिता भार्गव

लेखक ने रोजगार की समस्याओं और मुद्दों पर जोर दियाए जो मुख्य रूप से पर्याप्त शिक्षा की कमी के कारण हैं। लेखक ने कई टुकड़ों में हमारे देश में उपलब्ध अवसरों की व्याख्या करने का प्रयास किया है। पुस्तक देश के सबसे प्रमुख मुद्देरू बेरोजगारी से निपटती है। हम भारतीय खुशनसीब हैं की हम विश्व के एक सबसे बेहतरीन स्थान में रहते हैं, जिसे पूर्व काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस किताब में बेरोजगारी की समस्या व उसके निदान हेतु अनेक लेख हैं। बेरोजगारी की समस्या भारत में नयी नहीं है पर आज़ादी के 75 साल बाद इस समस्या पर अवलोकन की आवश्यकता थी। पिछले कुछ दशक से भारत ही नहीं विश्व का परिवेश भी बदला है व नयी चुनौतियां मुँह बनाए खड़ी हैं। आज युवाओं का एक वर्ग व ग्रामीण क्षेत्र के भी कई लोग कठिनायों में जी रहे हैं। किताब में लिखे गए लेख जागरूकता और रोजगार सम्बन्धी ज्ञान व आत्मविश्वास बढ़ाने का एक प्रयास है।

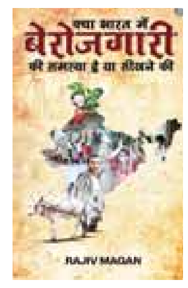

पुस्तक: क्या भारत में बेरोज़गारी की समस्या हैया सीखने की लेखक: राजीव मगन

नवीन चौरे द्वारा लिखित पुस्तक श्कोहरा घना है, सिर्फ कुछ पेजों में छपी काली स्याही ही नहीं अपितु भावनात्मक तस्वीर का जीता जागता उदाहरण है। नवीन की भावुक कविता. मॉब लिंचिंग, कश्मीर और दूसरों के बीच सैनिकों की दुर्दशा आपको राष्ट्रवाद, देशभक्ति और हमारे देश की स्थिति पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देगी। नवीन का युवा आदर्शवाद, एक समतावादी दुनिया के लिए दृष्टि और प्रगतिशील विचार कोहरा घाना है को हमारे समय के सबसे साहसी कार्यों में से एक बनाते हैं। वर्तमान समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग भावनाओं से किस प्रकार खेल रहे है। इंसानियत का गला किस प्रकार घुट रहा है। यह पुस्तक स्वयं में एक जीवन है।

पुस्तक: कोहरा घना है
लेखक: नवीन चौरे

विकास राज सक्सेना, लेखक डायरेक्टर

परिवार नियोजन अपनाने में पुरुष आज भी पीछे

महिलाओं की संख्या पुरुषों से होती है कई गुना अधिक

कविता। फरीदाबाद

बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार परिवार नियोजन में कई तकनीकियों का सहारा ले रही है। जिले में पांच तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पुरूष अब भी इन उपायों को अपनाने में संकोच करते हैं।

परिवार नियोजन के प्रति आशा वर्करों व एएनएम के जरिये जागरुक किया जा रहा है। पुरूषों को लुभाने के लिए नसबंदी के शिविर भी लगाए जा रहे हैं। नसबंदी के फायदे बताए जा रहे हैं बिना टांके व चीरे के ऑपरेशन किए जा रहे है। ऐसा ही 17 से 30 जनवरी तक चले नसबंदी शिविर में देखने को मिला। जिसमें 41 महिलाओं के अलावा मात्र दो पुरूषों ने ही ऑपरेशन करवाया। वहीं अब अप्रैल से दिसंबर माह के आंकड़ों पर नजर डाली जाए, तो कुल 501 ऑपरेशन किए गए है। जिसमें पुरूषों की संख्या मात्र 14 है। जनवरी 2022 में 88 ऑपरेशन किए गए, जिसमें मात्र 8 पुरूष शामिल थे।

बीके अस्पताल में मौजूद पीपी सेंटर।

पुरुषों के लिए है सरल तरीका

परिवार नियोजन शिविरों में आमतौर पर पुरुषों द्वारा कम रूचि दिखाई जाती है। जिसकी वजह से विभाग द्वारा समय-समय पर महिला एवं पुरूष नसबंदी शिविरों का आयोजन किया जाता है। जिसमें ऑपरेशन करवाने वाले महिला और पुरुषों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। लेकिन पुरूष आज भी इस मामले में काफी पीछे हैं। एडिशनल एसएमओ डॉ. हिमा ने बताया कि शिविर में बिना टांके और चीरे के ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन मात्र दस मिनट में सम्पन्न हो जाता है। ऑपरेशन के बाद पुरूष सामान्य रूप से कार्य कर सकते हैं। बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती। शिविर में ऑपरेशन करवाने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि 2100 रुपये दी जा रही है।

कैम्प में पहुंचे मात्र दो पुरुष

डॉ. हिमा ने बताया कि ऑपरेशन महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए बेहद आसान है। महिलाओं को एक से डेढ़ महीने इस ऑपरेशन के बाद सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन पुरुष ऑपरेशन के तुरंत बाद दिनचार्य के कार्य कर सकते हैं। महिलाओं के ऑपरेशन में समय अधिक लगता है, जबकि पुरुषों का ऑपरेशन मात्र दस मिनट का है। पुरुष ऑपरेशन के तुरंत बाद अपने कार्य कर सकते हैं। 17 से 30 जनवरी तक लगाए गए शिविर में मात्र दो ही पुरुष आए। जबकि 41 महिलाएं ऑपरेशन करवा चुकी हैं। छह महिलाओं ने आईयूडी (कॉपर्टी) लगवाई। वहीं माला एन की गोलियां 70 महिलाओं ने ली। वहीं छाया का इस्तेमाल करने वाली महिलाएं 35 रही।

गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

फरीदाबाद। डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान के द्वारा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर सख्त कानूनी कर्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिन पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर-17 की टीम ने आरोपी नीरज को थाना पल्लाक्षेत्र से गांजा पत्ती सहित गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपी नीरज राजस्थान के गांव हरकंदपुरा जिला धौलपुर हाल विनय नगर पल्ला फरीदाबाद में रहता है। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नीरज को गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना पल्लाक्षेत्र से 1.215 किलोग्राम गांजा पत्ती सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ थाना पल्ला में अवैध नशा तस्करी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

कोविड में माता-पिता खोने वाले बच्चों की पालनहार बनी सरकार

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

सीएम बाल सेवा योजना के तहत मिलेगा पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर

हरियाणा प्रदेश की मनोहर लाल सरकार कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की पालनहार बनी है। प्रदेश सरकार ने ऐसे अनाथ बच्चों की हर तरह की मदद के लिए प्रदेशभर में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष तक 2500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी।

फरीदाबाद जिला में मौजूदा समय में 2 बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा पूरे जिला में एक सर्वे आयोजित कर 270 ऐसे बच्चों की पहचान भी की गई है जो इस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं। इन सभी की वेरिफिकेशन व पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य जारी है।

डीसी जितेंद्र यादव ने बताया कि योजना के तहत बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों के आवर्ती जमा खाते खोले जाएंगे, जिसमें 18 वर्ष की आयु तक 15 सौ रुपए जमा करवाने का प्रावधान किया गया है। इन बच्चों को सरकार ने अन्य खर्चों के लिए 12 हजार रुपये वार्षिक देने का निर्णय भी लिया है। किशोरियों को कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय में नि:शुल्क स्कूली शिक्षा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त किशोरियों के खाते में 51 हजार रुपए जमा किए जाएंगे तथा विवाह के समय ब्याज सहित शगुन दिया जाएगा। बच्चों के माता-पिता अथवा उनमें से किसी एक के कोरोना के कारण निधन होने से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसे बच्चों के लालन-पालन पर बुरा असर पडना स्वाभाविक है। ऐसे अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत सरकार उनकी देखभाल करेगी।

क्या है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना: डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय/निजी स्कूल में डे-स्कालर के रूप में दाखिला तथा निजी स्कूल में दाखिला के लिए पीएम केयर्स से आरटीई के तहत फीस, वर्दी, पाठ्यक्रमों व नोटबुक की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के दौरान किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, इत्यादि में दाखिला, निजी स्कूल में दाखिले के लिए पीएम केयर से आरटीई के तहत फीस, वर्दी, पाठ्यक्रमों व नोटबुक की सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा के तहत 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा तथा 18 वर्ष की आयु तक के इन बच्चों के प्रीमियम की राशि का भुगतान पीएम केयर द्वारा किया जाएगा। जितेंद्र यादव ने बताया कि योजना के तहत 18 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति बच्चा प्रति महीना, बिना परिवार के बच्चों की देखभाल करने वाले बाल देखभाल संस्थान को 1500 रुपये प्रति बच्चा प्रतिमास 18 वर्ष तक की आयु तक, अन्य पूरा खर्चा बाल देखभाल संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। इसी प्रकार 18 वर्ष तक पढ़ाई के दौरान प्रतिवर्ष 12000 रुपये अन्य खर्चों के लिए भी सरकार द्वारा दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 8वीं से 12वीं या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को टेबलेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर पीएम केयर्स द्वारा 10 लाख रुपये का कोष, 18 वर्ष की आयु से अगले 5 वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान मासिक वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति तथा 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर बच्चे को व्यक्ति और व्यावसायिक उपयोग हेतु एकमुश्त राशि दी जाएगी।

आप में कार्यकर्ता को पूरा मिलता है सम्मान: भड़ाना

आप के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी में शामिल होते हरियाणा के रागनी गायक रमेश कलवाडिया, बन्टी सिंह, संतोष सिंह और अजय सिंह और अन्य लोग।

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और पूरे हरियाणा में डॉ. सुशील गुप्ता के नेतृत्व में लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों में आस्था जता रहे हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा के प्रसिद्ध रागनी गायकार रमेश कलवाड़िया, सूरज सिंह वालिया, बन्टी सिंह, भूपेन्द्र सिंह, संतोष सिंह, अजय चौधरी, मदन श्रीवास्तव सहित दर्जनो युवकों ने आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मबीर भड़ाना के नेतृत्व में पार्टी का दामन थामा।

रमेश कलवाड़िया ने कहा कि अपनी नियुक्ति पर उन्होंने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, सह प्रभारी डॉ. सुशील गुप्ता एवं जिला अध्यक्ष धर्मबीर भड़ाना का आभार जताया कि उन्होंने अपने जीवनकाल में आम आदमी की दुःख तकलीफों को देखा है। जिससे आहत होकर उन्होंने आम आदमी की सेवा के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी में अपनी आस्था जताई।

इस मौके पर भड़ना ने कहा कि देश में आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो गरीब एवं आम आदमी के दर्द को समझती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्पष्ट एवं साफ छवि के ईमानदार नेता हैं, वो पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरा मान-सम्मान देते हैं। आम आदमी पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरा मान-सम्मान मिलता है। आज जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं।

पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ: सेतिया

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

पत्रकारों के हित के लिए कार्य करे संगठन : त्रिखा

हरियाणा प्रेस क्लब द्वारा बड़खल स्थित ग्रे फाल्कन में बुधवार को सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी त्रिखा, एसडीएम बड़खल पंकज सेतिया एवं आप के व्यापारी नेता अमन गोयल मौजूद रहे।

सभी का हरियाणा प्रेस क्लब की टीम ने बुके देकर एवं शाल पहनाकर सम्मान किया। एसडीएम पंकज सेतिया ने हरियाणा पत्रकार क्लब की नवनियुक्त कार्यकारिणी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। कहा की पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। समाज को आइना दिखाने का काम पत्रकारों का होता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समाज हित में करें। सेतिया ने कहा कि हरियाणा पत्रकार क्लब के सभी साथियों के हित एवं उनकी भलाई के लिए जो भी मदद होगी, मैं तत्पर रहूंगा। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भाजपा नेता अश्वनी त्रिखा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों के आशीर्वाद से ही हमें दो बार बड़खल विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका मिला। त्रिखा ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया माध्यम तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रिंट मीडिया का आज भी अपना महत्व है सरकार भी सोशल मीडिया को लेकर अभी कोई रेगुलेटरी नहीं बना पाई है, मगर सोशल मीडिया इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जो भी घटना घटती है, तुरंत हमें मिलती है। उन्होंने पत्रकारों के पेशे को खतरों से जुड़ा और साहसिक बताया और कहा कि पत्रकारों के हितों के लिए उनसे जो भी बन पड़ेगा, पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमें प्रधान राजेंद्र सिंह ने उप प्रधान- आईपीएस अरोड़ा, जयशंकर सुमन, यशपाल सिंह आदि को बनाया गया। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कमेटी का गठन किया गया।

बजट है जले पर नमक छिड़कने जैसा : लांबा

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

केन्द्रीय आम बजट में कर्मचारियों के लिए आयकर छूट सीमा बढ़ाने से इन्कार करने और कारपोरेट घरानों को टेक्स में भारी छूट देने का फैसला जले पर नमक छिड़कने जैसा है। यह आरोप सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने लगाते हुए बताया कि मंगलवार को पेश किए गए आम बजट में कर्मचारियों को टेक्स में कोई राहत न देने और पुरानी पेंशन बहाली न करने पर कड़ा एतराज जताया।

उन्होंने कहा कि पहले ही सरकार 18 महीने का डीए मार कर बैठी है। ऊपर से सरकार की दोषपूर्ण टेक्स प्रणाली के चलते तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपना डेढ़ से दो मास का वेतन हर साल टेक्स में देना पड़ रहा है। कर्मचारी के पास साल में मुश्किल से दस महीने का वेतन ही बचता है। जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नीति में शामिल करने की बजाए सरकार एनपीएस को बनाए रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार बजट में प्रदेश में 1.62 लाख समेत

सुभाष लाम्बा।

देश भर के करोड़ों कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना तो दूर समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने से भी वंचित रखा गया है। उन्होंने बताया कि जीपीएफ समेत बचत और अल्प बचतों पर ब्याज दरों में भी कोई बढ़ोतरी न होने से कर्मचारी व पेंशनर्ज दोनों में केंद्र सरकार के प्रति भारी गुस्सा है। बजट में सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों पर नियमित भर्ती कर बेरोजगारों को रोजगार व जनता को बेहतर जन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में भी कोई ठोस कदम नही उठाया है। बजट में जिस डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया गया है उससे और बेरोजगारी बढ़नी निश्चित है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा निश्चित रूप से इन कदमों का डटकर विरोध करेगा।

लाम्बा ने कहा कि केंद्रीय बजट पूरी तरह वैश्वीकरण, उदारीकरण व निजीकरण की नीतियों को तेजी से आगे बढ़ाने वाला है। बजट में कोरोना की आड़ में आन लाइन शिक्षा पर जोर देते हुए जो वन क्लास वन टीवी चेनल, ई-प्रयोगशाला व डिजिटल विश्विद्यालय की स्थापना एवं डिजिटल टीचर की व्यवस्था सार्वजनिक शिक्षा के निजीकरण की और सरकार का बढ़ता कदम है। इससे गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनता के इलाज की गारंटी की बजाए डिजिटल इको हेल्थ सिस्टम के तहत हेल्थ कार्ड बनाने के नाम पर जनता को गुमराह करने पर लगी है। सरकार इलाज का जिम्मा बीमा कंपनियों के हवाले कर अपनी जिम्मेवारी से बचना चाहती है। सार्वजनिक शिक्षा व स्वास्थ्य हर नागरिक का मौलिक एवं सवैधानिक अधिकार है। इसलिए इनके निजीकरण को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही करेगा।

एक मुश्त संपत्तिकर जमा कराने पर 10 साल का ब्याज माफ

फरीदाबाद। नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा ने अधिसूचना के द्वारा वर्ष 2010-2011 से 2020-21 तक के संपत्तिकर के बकायाजात पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी करदाताओं को देने के लिए सभी निकायों को आदेश दिए है। जिसकी अन्तिम तिथि 31 मार्च तक है।

निगमायुक्त ने बताया कि जो करदाता इस अवधि तक अपनी सम्पति के बकायाजात नहीं जमा कराता या देरी से भुगतान करता है तो उस से प्रति मास या उसके भाग के लिये 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जायेगा। 31 मार्च तक संपत्ति कर जमा न कराने पर संपत्ति इकाई को सील कर दिया जायेगा और इसकी नीलामी की कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी। निगमायुक्त ने संपत्तिकर दाताओं से अपील की है कि वे अपने सम्पत्ति कर की बकाया राशि को तत्काल जमा कराये और सरकार की उपरोक्त पोलिसी का लाभ उठायें।

जिले में नहीं लगे बच्चों को टीके

टीकें समाप्त होने के कारण बच्चों को लौटाया गया

कहा, बिना टीका लगाए ही बच्चों को लौटाया जा रहा

कविता। फरीदाबाद

जहां एक तरफ स्कूल और कॉलेज खुल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों और कॉलेजों में बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बच्चों को एंट्री नहीं दी जा रही है। जिस कारण बच्चे वैक्सीन लगवाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में बीके अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लेकिन बृहस्पतिवार को 15 प्लस आयुवर्ग के बच्चों को लगाई जाने वाली वैक्सीन समाप्त हो गई थी। जिस कारण बच्चों को यहां से लौटाया गया।

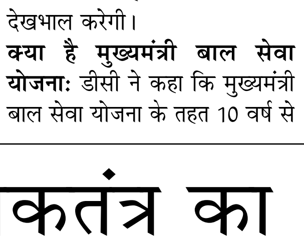
कोरोना से बचाव का टीका लगवाती महिला

जानकारी के मुताबिक जिले में कोविड-19 वैक्सीन जोकि 15 प्लस आयुवर्ग को लगाई जा रही है। वह बृहस्पतिवार को पूरी तरह से समाप्त हो गई। जिस कारण वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगवाने पहुंचे बच्चों और उनके परिजनों को वहां से लौटा दिया गया।

टीकाकरण केंद्र की संख्या बढ़ाए जाने से खपत काफी बढ़ गई है। वहीं जिले में स्कूल खुलने के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी होने के कारण बच्चे अधिक से अधिक संख्या में केन्द्रों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन की कमी हो गई है। बुधवार को समाप्त हुई वैक्सीन बृहस्पतिवार तक नहीं पहुंची। जिससे यहां बच्चों को परेशान होकर वापस लौटना पड़ा।

दूसरी डोज का समय: जिले में 15 प्लस आयुवर्ग के बच्चों को कोवैक्सीन की डोज लगवाई जा रही है। पहली डोज लगे हुए कुछ बच्चों को 28 दिन पूरे हो चुके हैं। जिस कारण दूसरी डोज का समय पूरा होने पर बच्चे अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंच रहे है। लेकिन बृहस्पतिवार को वैक्सीन न होने से बच्चे अपने परिजनों के साथ वैक्सीनेशन सेंटरों से लौटते नजर आए। उन्हें परेशानी हो रही है कि 28 दिन बाद वैक्सीन नहीं लगी तो क्या होगा, यह सवाल वह मौके पर मौजूद कर्मचारियों से पूछते नजर आए। बच्चों को परेशान देखकर कर्मचारियों ने उन्हें शुक्रवार को आकर वैक्सीन लगवाने को कहकर टाल दिया।

यातायात नियमों की जानकारी के लिए चलाया अभियान

फरीदाबाद। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फरीदाबाद, फरीदाबाद पुलिस एवं रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन की तरफ से गुरुवार को स्पेशल सड़क सुरक्षा अभियान 2022 एंड रिफ्लेक्टिव टेप को साइकिल पर लगाने का अभियान उपायुक्त जितेंद्र यादव के आदेशनुसार व जितेंद्र गहलावत जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के नेतृत्व में चलाया गया।

इसमें अधिवक्ता सतीश आचार्य, लतेश, ट्रैफिक इंस्पेक्टर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फरीदाबाद एवं स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल हरियाणा सरकार एवं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोड सेफ्टी कमेटी भारत सरकार के सदस्य सरदार देवेंद्र सिंह एवं रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन के सहयोग से रिफ्लेक्टिव टेप साइकिल लगाने का अभियान एस.पी.एल. लिमिटेड कंपनी की तीनों यूनिटों सेक्टर-24 में चलाया गया।

थाना प्रभारी ने स्कूल के बच्चों में बांटे कॉपी पेन

फरीदाबाद। डबुआ थाना प्रबंधक इंस्पेक्टर महेंद्र पाठक की टीम ने छोटे बच्चों में शिक्षा का महत्व देखते हुए कॉपी पेन बांटने का सराहनीय कार्य किया है। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना डबुआ प्रभारी महेंद्र पाठक ने आज श्रम बस्तियों के स्कूल जाने वाले छोटे-छोटे बच्चों को कॉपी, किताब व पेन पेंसिल वितरण करते हुए बच्चों करते हुए शिक्षा का महत्व समझाया।

इस मौके पर थाना डबुआ की पुलिस टीम सहायक उप निरीक्षक भूपेंद्र, मुख्य सिपाही मुकेश, सिपाही सुरेंद्र व अन्य साथियों के साथ बच्चों को सभी पढ़ने लिखने की सामग्री वितरित की गई। सब पढ़े सब का नारा को आगे बढ़ाते हुए प्रबंधक थाना महेंद्र पाठक ने लोगों का दिल जीता। उन्होंने कहा की कोरोनावायरस काफी

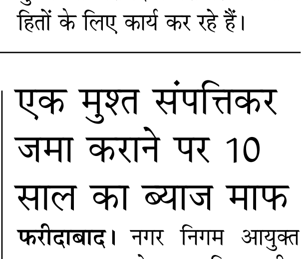

दिनों से स्कूल बंद है जो सरकार के आदेशों के बाद बच्चों को स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। बच्चों को स्कूल से काफी दिनों से दूर रहना पड़ा है जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि कम हुई है। रुचि को जागरूक करने के लिए थाना डबुआ पुलिस टीम ने बच्चों को कॉपी किताब और पेन वितरित करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी का अधिकार है जो सबको मिलना चाहिए। जिसमें हमारा भी फर्ज बनता है कि बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें।

संक्षिप्त समाचार

डालसा टीम ने ग्रामीणों को किया जागरूक

फरीदाबाद। सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश मगलेश कुमार चौबे के मार्गदर्शन में विभिन्न स्तर पर लोगों को कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों बारे जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पैनल अधिवक्ताओं ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए फेश मास्क और सामाजिक दूरी बनाए रखने बारे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा कानूनी जागरुकता के संबंध में कानूनी साक्षरता पुस्तकें, पैम्फलेट का वितरण करके पैनल अधिवक्ताओं ने लोगों को उनके बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए। पैनल अधिवक्ताओं ने सेक्टर-12 न्यायालय परिसर में भी कानूनी साक्षरता पुस्तकें वितरण की गई। सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने आगे बताया कि नालसा,हालसा और डालसा की विभिन्न योजनाओं के लिए डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान गांव सागरपुर में देने सहित लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के लिए जानकारी दी गई। इन गतिविधियों के माध्यम से 365 लोग लाभान्वित हुए। जहां पर पैनल अधिवक्ता रामबीर तंवर, राजेंद्र गुप्ता, राजेंद्र गौतम, लखी राम, शिव कुमार और पीएलवी, जयप्रकाश शामिल थे।

कोरोना: 277 पॉजिटिव, 631 ठीक

फरीदाबाद। जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या का आंकड़ा लगातार घट रहा है। बृहस्पतिवार को 277 पॉजिटिव पाए गए हैं। जिससे जिले में एक्टिव केसो की सख्या का आंकड़ा 2001 पर पहुंच गया है। जिसमें होम आईसोलेशन में 1929 मरीज है। वहीं 72 मरीज अस्पतालों में भर्ती है। जिसमें 9 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। 20 मरीज आईसीयू में गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीज हैं। वहीं चार मरीज वैंटीलेटर पर हैं। वहीं जिले में लगातार कोविड-19 के मरीजों की संख्या को कम करने के लिए अधिक से अधिक सैम्पल लेने के आदेश दिया है। जिसमें 3741 सैम्पल पिछले 24 घंटे में लिए गए। सरकारी प्रयोगशालाओं में 2764 सैम्पल और निजी प्रयोगशाला में 617 सैम्पलों की रिपोर्ट आनी शेष है। वहीं जिले में राहत की बात यह रही कि 631 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए। जिससे जिले का रिकवरी रेट 97.80 प्रतिशत पर पहुंच चुका है।

कैडेट्स को अग्निशमन की दी जानकारी

फरीदाबाद। डीएवी शताब्दी महाविद्यालय में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में कैडेट्स को अग्निशमन अधिकारियों द्वारा आग लगने की आपातकालीन परिस्थिति में बिना घबराएं क्या करना है। कौन सी बातों का ध्यान रखना है और आग के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। शिविर 150 से अधिक कैडेट्स निरंतर नौसैनिक विषयों के अलावा विभिन्न व्यावहारिक विषयों जैसे ड्रिल, फर्स्ट ऐड, वेपन ट्रेनिंग आदि का अभ्यास कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन और ऐसी स्थितियों में समाज की मदद करने के लिए एनसीसी कैडेटों की भूमिका पर व्याख्यान भी दिया गया। कैडेटों को ग्राउंड टास्किंग भी दी गई और उन्हें अनुशासन के मूल्य और एनसीसी में इसकी भूमिका के बारे में जागरूक किया गया। शिविर में कमांडिंग आफिसर कैप्टन (भारतीय नौसेना) विवेक कुमार द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण किया जा रहा है। कालेज की प्राचार्या डॉ सविता भगत स्वयं ने इस शिविर में सभी जरूरी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करती है ताकि प्रशिक्षण में कोई व्यवधान ना हो।

गुमशुदा लड़की को किया परिजनों के हवाले

फरीदाबाद। क्राइम ब्रांच कैट की टीम ने गुमशुदा लड़की को तलाश कर परिजनों से मिलाने का सराहनीय कार्य किया है। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गुमशुदा लड़की वजीरपुर रोड नैपकिन कंपनी में काम करती है। लड़की अपने घर से मनमुटाव के चलते 27 दिसम्बर को घर से निकल गई थी। गुमशुदा लड़की के परिवार वालों ने थाना खेडी पुल में सूचना दी। जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर महिला की तलाश शुरू की है। पुलिस टीम ने पुलिस कन्ट्रोल रुम से सभी थाना चौकियों में सूचना भेजी गई। फोटो सोशल मीडिया के पुलिस व्हाट्सएप ग्रुपों में डालकर लडकी के जानने वालों का फरीदाबाद में पता किया गया। क्राइम ब्रांच कैट की टीम में उपरोक्त मामले पर कार्रवाई करते हुए ददसिया फरीदाबाद में रहने वाली लडकी को गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर बदरपुर बॉर्डर दिल्ली से बरामद किया है। पुलिस टीम ने लडकी से परिवारजनों के सामने पूछताछ की। जिसमें पाया गया कि लडकी परिजनों से कुछ मनमुटाव था। इसलिए नाराजगी में घर से निकल गई थी। जो अब उनके साथ जाना चाहती है। पुलिस टीम ने कानूनी प्रक्रिया उपरांत लडकी को परिजनो के हवाले कर दिया है। महिला के परिजनो ने पुलिस टीम का तहे दिल से धन्यवाद किया।

आंगनबाड़ी वर्करों ने डीसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन

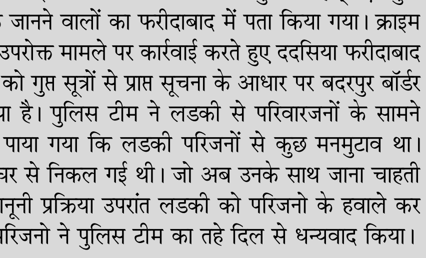

फरीदाबाद। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज उपायुक्त कार्यालय के सामने सेक्टर-12 फरीदाबाद में जोरदार प्रदर्शन किया। कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी बड़ी संख्या में वर्कर और हेल्पर लघु सचिवालय के प्रांगण में पहुंचे। यहां पर जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व राज्य प्रधान देवेंद्री शर्मा कर रही थी। जबकि कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव मालवती ने किया। इस अवसर पर सीटू के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह डंगवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि आज हड़ताल का 58वां दिन है। यह हड़ताल 8 दिसंबर से चल रही है। भाजपा की राज्य सरकार हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को लागू करने के बजाए संघर्ष को कमजोर करने के लिए दमन का रास्ता अपना रही है। अब तक फरीदाबाद में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने दर्जनों नेतृत्व कारी वर्कर हेल्पर की सेवाएं समाप्त करने कर दी है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ 29 दिसंबर को हुए फैसले को ज्यों का त्यों लागू करना, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 11 सितंबर 2018 को आंगनबाड़ी वर्कर के लिए वेतन में 1500 रुपये की बढ़ोत्तरी और सहायिकाओं के वेतन में 750 रूपए के वेतन बढ़ोतरी को लागू करना, सेवानिवृत्त के बाद तीन लाख की राशि का भुगतान करना, पोषण ट्रैकर एप डाउनलोड करने के आदेश को निरस्त करना, ऑनलाइन काम के वर्क को ऑप्शनल रखना इत्यादि हैं। आज के प्रदर्शन को सीमा यादव कोषाध्यक्ष, सुरिंद्री,कमलेश, शर्मा, आरती, संतोष ने भी संबोधित किया।

बेलदार यूनियन के चुनाव सम्पन्न हुए

फरीदाबाद। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की इकाई नगर निगम बेलदार यूनियन के चुनाव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य उप प्रधान कमला, जिला सचिव नानक चंद खैरालिया, सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता सुरेश देवी, धर्म सिंह मुल्ला की देखरेख में संपन्न हुए। चुनाव में शहाबुद्दीन को प्रधान चुना गया तथा जीतराम को सचिव, करतार को वरिष्ठ उपप्रधान, रामेश्वर उपप्रधान, रामपाल कोषाध्यक्ष, अमर सिंह सह सचिव, राशिद ऑडिटर, जयवीर संगठनकर्ता व ओम प्रकाश, रण सिंह, रामकिशन व मंगल को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने चुने हुए प्रतिनिधियों को ईमानदारी व कर्मठता के साथ काम करने की शपथ ग्रहण करवाई।

प्राकृतिक खेती
स्वास्थ्यवर्धक भोजन

मंगलवार को अपने बजट भाषण में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।' कृषि मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-आईएआरआई को इस महत्वपूर्ण घोषणा के समर्थन में काम करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि क्या प्राकृतिक खेती काफी उत्पादक तथा अच्छा लाभ देने वाली है। 2019 में सीतारमण ने कहा था कि किसानों को अपनी आय 'दूनी' करने के लिए 'ज़ीरो बजट' तकनीक प्रयोग करनी चाहिए। ज़ीरो बजट प्राकृतिक तकनीक का आविष्कार वर्धा के सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष पालेकर ने किया था। इसमें केवल प्राकृतिक चीजों जैसे गाय के गोबर, गौमूत्र व नीम का प्रयोग खाद, उर्वरक व कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। लेकिन इस तकनीक को गहन वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरना बाकी है। इससे निश्चित रूप से सरकार को राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा क्योंकि 2021-22 में उर्वरक मूल्य 79,530 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों से 60,000 करोड़ रुपये अधिक हो गए थे। 2022-23 का बजट अनुमान 1,05,222 करोड़ रुपये है। यदि इस साल उर्वरकों का अंतरराष्ट्रीय मूल्य कम नहीं होता है तो अतिरिक्त आबंटन की आवश्यकता होगी। इस दृष्टिकोण से देखने पर प्राकृतिक खेती अत्यधिक स्वागत योग्य है। लेकिन यह परिवर्तन रातोंरात नहीं हो सकता है। यदि सीतारमण इसकी उपयुक्तता का संकेत देती हैं तो भी इसका प्रयोग पहले छोटे कृषि क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार प्राकृतिक खेती से मृदा स्वास्थ्य सुधरेगा तथा खेती सस्ती होगी। लेकिन इससे अधिकांश किसान

उत्साहित नहीं होंगे क्योंकि परंपरागत खेती की तुलना में उपज कम होगी। प्राकृतिक कृषि विधियां इसलिए लोकप्रिय हो रही हैं क्योंकि अमीर लोग 'शुद्ध' कृषि उत्पादों के लिए ज्यादा कीमतें अदा करने को तैयार हैं। आर्गेनिक खेती में आर्गेनिक उर्वरक और खादें प्रयोग होती हैं। प्राकृतिक खेती रसायन या आर्गेनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करती है और बाहर से खरीदे जाने वाले निवेशों पर निर्भर नहीं रहती है। आर्गेनिक खेती अब भी खर्चीली है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर खादों की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती सस्ती है क्योंकि यह स्थानीय जैवविविधता पर पूरी तरह निर्भर होती है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती का प्रयोग कर रहे हैं, पर अधिक उपज के उनके दावों की वैज्ञानिक पुष्टि होनी चाहिए। माना जाता है कि समय बीतने के साथ उपज धीरे-धीरे बढ़ेगी। दीर्घकालीन सर्वेक्षणों से इन दावों की पुष्टि होनी चाहिए। इसके साथ ही आईएआरआई को इस अवसर पर सामने आ कर उपज में अंतर घटाने की विधियां बतानी चाहिए। उदाहरणार्थ, सदियों पुरानी कृषि व्यवस्थाओं में पोलीकल्चर व फसल चक्र परिवर्तन से उपज बढ़ सकती है। दूसरी ओर टमाटर और जौ जैसी फसलों के लिए प्राकृतिक या परंपरागत खेती से उपज समान होती है। सरकार को परंपरागत खेती से प्राकृतिक खेती में निवेश बढ़ाना चाहिए। प्राकृतिक फार्मों में तैयार बीज अच्छा काम नहीं करते हैं अत: बीजों के शोध व विकास की नई विधियां खोजी जानी चाहिए। प्राकृतिक खेती की ओर परिवर्तन कृषि के प्रति समग्र दृष्टिकोण का हिस्सा होना चाहिए। उपज में अंतर में कमी लाने का अर्थ ज्यादा पैसा और ज्यादा भोजन होगा। ज्यादा भोजन का अर्थ कम भुखमरी होगा। लेकिन खाने की बरबादी रोकना और अनाज भंडारण के मुद्दों का अर्थ भी ज्यादा भोजन और कम भुखमरी होगा। इससे प्राकृतिक खेती में परिवर्तन से आए उपज में अंतर से निपटने में भी सहायता मिलेगी।

गरीबों पर केंद्रित बजट

बजट के रूप में इसका उपभोग पर असर मध्यम होगा, वृद्धि के मामले यह औसत होगा तथा इसकी गति संभवत: इस साल जितनी अच्छी रहेगी।

शिवाजी सरकार
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

केंद्रीय बजट में क्रिप्टो करेंसी शुरू करने के साथ ही किसान व उद्योग को प्रोत्साहन दिए गए हैं, लेकिन वेतनभोगी कर्मचारियों को निराश किया गया है क्योंकि परोक्ष आयकर में कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई है कि 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन-पीएलआई योजना से 60 लाख रोजगार सृजित होंगे। सरकार को उम्मीद है कि इसमें 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है। यह उम्मीद आर्थिक सर्वेक्षण से भी थोड़ी अधिक है जो 'खर्च करो और मजा करो' के प्रति ज्यादा जोश नहीं दिखाता है। एमएसएमई को 2 लाख करोड़ का कर्ज समर्थन मिला है। उनकी स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में देखना होगा कि क्या यह कदम उनके फलने-फूलने में लाभकारी होगा। छात्रों और विद्वानों के लिए ई-विद्या व राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय स्वागत योग्य कदम है। यदि 5जी के बाद भी डेटा का खर्च कम बना रहता है तो इससे कम खर्च पर राष्ट्रव्यापी मानक शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सकता है। वित्त मंत्री ने खर्च में मामूली वृद्धि की है और यह 2021-22 में 37.70 लाख करोड़ से बढ़ कर 39.44 लाख करोड़ हो गया है। इसी प्रकार उधारी 15.91 लाख करोड़ की तुलना में 16.61 लाख करोड़ हो गई है। राजकोषीय घाटा घट कर 6.9 प्रतिशत था जो 2021-22 बजट अनुमान में 9.2 प्रतिशत था तथा अब 6.4 प्रतिशत हो गया है। वृद्धि के आंकड़ों का अनुमान 9 प्रतिशत है। हालांकि, यह आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार है, पर यह दो साल पहले के नकारात्मक सात प्रतिशत से वापसी है। इसके बावजूद यह अभी 2019 के स्तर पर वापस आया है।

बजट में आगे बढ़ने का रास्ता पूंजीगत खर्च, 5जी संचार तकनीक, केन्द्रीय बैंक डिजिटल-क्रिप्टो करेंसी, धान व गेंहूं की किसानों से भारी खरीद तथा सड़कों व राजमार्गों की योजनाओं से निकाला गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वे भारत के 'अमृत काल' या 75वें वर्ष की गति निर्धारित कर रही हैं और उनकी नजर भारत के अगले 25 सालों पर है। हालांकि, उन्होंने विभिन्न उद्योगों के लिए अनेक दरें घटाने या तार्किक बनाने के माध्यम से टैक्स लाभों का विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि दरों में विसंगतियां थीं और उन्होंने इसे यथार्थवादी स्तर प्रदान किया है। रसायनों और अन्य कच्चे मालों पर कस्टम ड्यूटी में कमी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमों के लिए स्वागत योग्य है। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा तथा प्रतियोगी दरों पर पुन: निर्यात संभव होगा। इससे निर्यात बढ़ेगा। सरकार ने पूंजीगत खर्च में भारी वृद्धि करते हुए इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 23 में 7.5 लाख करोड़ रखा है, जबकि यह पिछले बजट में 5.5 लाख करोड़ था। उम्मीद है कि इससे ढांचागत संरचनाओं में निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। यह इस सोच के अनुसार है कि बैंकों से ज्यादा ढांचागत फाइनेंसिंग के चलते ज्यादा लोगों को रोजगार देने की जरूरत होगी। इस वर्ष खर्च 2.48 लाख करोड़ या लगभग 49 प्रतिशत थे। यदि सरकार 7.5 लाख करोड़ की पूरी धनराशि खर्च करने में सफल होती है तो इसके आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि ब्लाकचेन व अन्य तकनीकों का प्रयोग कर आरबीआई एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी-रूपी शुरू करेगा। उन्होंने कहा, 'इससे अर्थव्यवस्था

> **बजट में आगे बढ़ने का रास्ता पूंजीगत खर्च, 5जी संचार तकनीक, केन्द्रीय बैंक डिजिटल-क्रिप्टो करेंसी, धान व गेहूं की किसानों से भारी खरीद तथा सड़कों व राजमार्गों की योजनाओं से निकाला गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वे भारत के 'अमृत काल' या 75वें वर्ष की गति निर्धारित कर रही हैं।**

को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा।' इससे अंतरराष्ट्रीय पूंजी का हस्तांतरण आसान हो जाएगा। इससे अनेक बिजनेस औपचारिक लेनदेन में गए बिना हो जाएंगे तथा पूंजी का देश में व देश से बाहर प्रवाह सरल हो जाएगा। एक प्रकार से इससे देश अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी से जुड़ सकेगा जिसके सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों का अध्ययन किया जा रहा है। चूंकि आरबीआई द्वारा जारी करेंसी नियमित होगी, इसलिए इससे अनियमित क्रिप्टो व्यवस्था जैसी परेशानियां नहीं होंगी। इसका संबंध कर समेकन से भी है। इसका एक प्रतिशत प्रत्येक लेनदेन पर तथा आमदनी पर आयकर प्राविधानों के अनुसार 30 प्रतिशत देना होगा। अनेक सरकारों ने अभी क्रिप्टो को स्वीकार नहीं किया है, पर वे स्वीकृत करेंसी के साथ समानान्तर बाजार में आ गई हैं।

चुनावों और तीन कृषि कानूनों की वापसी को मजबूर करने वाले हालिया किसान आंदोलन का ध्यान रखते हुए वित्त मंत्री ने धान और गेंहूं की खरीद एमएसपी पर करने की घोषणा की है। उन्होंने इसके लिए 2.37 लाख करोड़ के खर्च का प्राविधान कर उम्मीद जताई है कि इसका किसानों के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाजों के वर्ष पर जोर देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई है कि भोजन आदतों में विविधता से किसानों को विभिन्न फसलें उगाने के ज्यादा विकल्प मिलेंगे। पीएम किसान पेंशन में वृद्धि की उम्मीद पूरी नहीं हुई है। संभवत: यह ठीक है क्योंकि राजस्व में 67 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद अभी स्थिति अच्छी नहीं हुई है। वित्त मंत्री द्वारा हर साल 60 लाख रोजगारों के सृजन की उम्मीद अटल बिहारी वाजपेयी का युग याद दिला देती है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से बाहर निकल रही अर्थव्यवस्था में यह आशावादी कदम है। लेकिन इसके लिए उपभोग बढ़ना तथा विनिर्माण की स्थिति सुधरना जरूरी है। उद्योग का जीडीपी में हिस्सा 28 प्रतिशत है। लेकिन इसके बावजूद आय में सुधार धीमा है तथा अचानक उपभोग में वृद्धि की उम्मीद करना बहुत अधिक होगा। निवेश बढ़ेगा, पर इसके इच्छित स्तर पर आने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, अब तक शेयर बाजार जोश से भरा रहा है, लेकिन पूंजीगत निवेश को कोविड-19 संबंधी अनिश्चितताओं से मुक्ति पाने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

निर्मला सीतारमण ने कुछ मामूली प्रत्यक्ष कर सुधार किए हैं। इनका संबंध मुख्यत: राज्य सरकार कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान मानक छूट देने से है। उनका यह अनुमान गलत है कि देश में केवल 3.8 करोड़ करदाता हैं। इस देश में सभी लोग लगभग 40 प्रतिशत परोक्ष कर का भुगतान करते हैं तथा 82 प्रतिशत लोग आयकर के संजाल से बाहर हैं। वे जानती हैं कि 30 प्रतिशत व्यक्तिगत कर 22 प्रतिशत कार्पोरेट कर की तुलना में अधिक है। यह विसंगति अतार्किक है। वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या लगभग 3.75 करोड़ है और वे सभी कर संजाल में हैं। उनकी देयता ऐसी स्थिति में पूरी होती है, जब निजी क्षेत्र तथा कार्पोरेट क्षेत्र व्यक्तिगत करदाताओं की तुलना में कम टैक्स देते हैं। उनके अनुसार करापवंचन एक प्रकार का भ्रम है। मजेदार बात है कि लोग जीएसटी का भुगतान भी करते हैं जिससे जनवरी, 2022 में 1.40 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। कुल मिला कर कहें तो इस बजट में सपने, जोश तथा वृद्धि के परोक्ष अनुमान हैं। इसमें पेयजल परियोजनाओं पर जोर दिया है, आवासीय परियोजनाओं के लिए 28,000 करोड़ निर्धारित किए हैं, राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ सिस्टम तथा इंटीग्रेटेड रेल-सड़क परियोजनाओं की रूपरेखा पेश की है। लेकिन इससे जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर छूट गया है। यह तबका भयानक गरीबी का शिकार है तथा प्रवासी श्रमिकों के लिए कोई बेहतर प्राविधान नहीं किए गए हैं।

उम्मीद थी कि रोजगार सृजन करने वाले बजट में नागरिकों को ज्यादा उपहार दिए जाते। बजट के रूप में इसका उपभोग पर असर मध्यम होगा, वृद्धि के मामले यह औसत होगा तथा इसकी गति संभवत: इस साल जितनी अच्छी रहेगी।

भविष्योन्मुख है बजट-2022

> **बढ़ी हुई उधारी, निजी निवेश में कमी और अभी तक पूरी तरह से ठीक होने वाले सेवा क्षेत्र ने कर रियायतों के लिए शायद ही कोई गुंजाइश छोड़ी है।**

शशांक सौरव
(लेखक लोक नीति विश्लेषक हैं)

हमेशा की तरह, वेतनभोगी और मध्यम वर्ग कुछ कर कटौती की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन तंग वित्तीय स्थान को देखते हुए, वित्त मंत्री के लिए ऐसी कोई छूट देने की संभावना नहीं थी। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार की उधारी वित्त वर्ष 2011 में 49 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2012 में 59 प्रतिशत हो गई है। एक बढ़ी हुई उधारी, निजी निवेश में कमी और अभी तक पूरी तरह से ठीक होने वाले सेवा क्षेत्र ने कर रियायतों के लिए शायद ही कोई गुंजाइश छोड़ी है।

बजट से एक दिन पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जीडीपी अनुपात में निवेश 29.6 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो पिछले सात वर्षों में सबसे अधिक है। हालांकि, विकास की गति और रोजगार सृजन पर चिंता अभी भी बनी हुई है और बजटीय आवंटन ने उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ दिखाई दे रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जो 7.5 ट्रिलियन रुपये हो गया है।

यदि अनुदान और सहायता आधारित पूंजीगत व्यय को भी जोड़ दिया जाए, तो यह संख्या 10.6 ट्रिलियन रुपये से अधिक हो जाती है, जो 27 प्रतिशत की वृद्धि है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये की दीर्घकालिक, ब्याज मुक्त सहायता से रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी और राज्यों को विकास दिखाने के लिए वित्तीय कमरा उपलब्ध होगा। महामारी में एमएसएमई क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था और उन्हें अभी भी जीवित रहने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है। एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपये

और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 50 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण सहायता से इन क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं को मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन और हरित ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए बजटीय आवंटन से आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद मिलेगी। रक्षा खरीद में घरेलू खरीद की हिस्सेदारी बढ़ाने को केवल मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भारत को रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख निर्यातक बनने में मदद करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाना चाहिए।

कृषि क्षेत्र में, खाद्यान्न की खरीद के लिए आवंटन में वृद्धि उन लोगों को शांत करेगी जो कुछ महीने पहले तक आंदोलन कर रहे थे। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण एक स्वागत योग्य कदम है जो ग्रामीण क्षेत्र में मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करेगा। इस बजट में यथार्थवाद का भी स्पर्श है। डिजिटल मुद्राएं अब एक वास्तविकता हैं और सरकार ने भी क्रिप्टो, एनएफटी और इसी तरह कर लगाकर इस तथ्य को स्वीकार किया है। जल्दी या बाद में, नियामक भी क्रिप्टो को एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में मान्यता देंगे और आवश्यक रूपरेखा तैयार की जाएगी।

विनिवेश लक्ष्य भी साध्य दिखाई दे रहे हैं और इसलिए यह अधिक संभावना है कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत की लक्ष्य सीमा के भीतर रहेगा। इस बार बजट में बहुत अधिक कर प्रस्ताव नहीं थे लेकिन कुछ पहल मुकदमेबाजी प्रबंधन और करदाता सहायता की दिशा में अच्छी तरह से लक्षित हैं।

विशिष्ट मामलों में रिटर्न के संशोधन के लिए विस्तारित समय सीमा की अनुमति देना और कानून के समान प्रश्न के मामले में दोहराव की अपील से बचना एक स्वागत योग्य निर्णय है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में मामूली वृद्धि पर आलोचना है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये दोनों आइटम संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा हैं और इसलिए हमें केवल केंद्र सरकार के धन की ओर नहीं देखना चाहिए।

राज्य सरकारों को, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों, खराब स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और शिक्षा के क्षेत्र में निराशाजनक प्रदर्शन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। राज्यों के बजट आवंटन की उसी तरह जांच होनी चाहिए जैसे केंद्र के लिए की जाती है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नीति दस्तावेज पेश करने और इसे राजनीतिक दस्तावेज में बदलने से परहेज करने के लिए एफएम की सराहना की जानी चाहिए। सरकार ने अपना काम किया है और अब यह निजी क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास की जिम्मेदारी है।

आप की बात

दूरगामी बजट

निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसके बारे में विशेषज्ञों की राय यही थी कि यह किसी भी तरह से लोक-लुभावन बजट नहीं है। कुछ ने तो इसे 'नो-नॉनसेंस' बजट भी कहा। आम धारणा यही है कि जो बजट लोक-लुभावन नहीं होते, उनके फायदों को लोगों को समझाना टेढ़ी खीर होता है। यह भी कहा जाता है कि ऐसे बजट तार्किक रूप से भले मजबूत होते हों, पर राजनीतिक रूप से ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले नहीं होते, क्योंकि उसका मर्म लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाता।खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश स्वागतयोग्य है और इसकी जरूरत से इनकार किया भी नहीं जा सकता। लेकिन ड्रोन का इस्तेमाल कितने किसान कर पाएंगे, यह भी देखना होगा। देश में छोटे और सीमांत किसानों की आबादी अस्सी फीसद से ज्यादा ही है। किसानों का यह तबका जिन मुश्किल हालात में खेती करता है, वह किसी से छिपा नहीं है। बीज, खाद से लेकर सिंचाई के लिए पानी और बिजली जैसी समस्याएं कहीं ज्यादा बड़ी और गंभीर हैं इस बार सरकार ने अपने हितों की बलि चढ़ा कर दूरगामी बजट पेश किया अन्यथा विधानसभा चुनावों के बीच कोई भी सरकार जनता को खुश करने वाले बजट ही पेश करती!

– **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम

सोई हुई शेरनी

मायावती के नेतृत्व वाली बसपा को आगामी यूपी चुनावों में हाशिए का खिलाड़ी मानना गलत होगा, क्योंकि बसपा सूक्ष्म स्तर पर जाति इंजीनियरिंग पर अपनी चुनावी योजना बना रही है। इससे पहले 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी ऐसा किया था, उस समय भी बसपा को दावेदार के रूप में नहीं देखा गया था लेकिन चुनाव परिणाम बसपा के पक्ष में थे। बसपा पर हमेशा पार्टी टिकट के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन इस बार इसका टिकट वितरण पूरी तरह से राजनीतिक शोध और टिकट वितरण में भाजपा और सपा-रालोद गठबंधन दोनों द्वारा की गई गलतियों पर आधारित है। मायावती जी की चुप्पी आखिरकार बुधवार को आगरा में एक रैली को संबोधित करने के बाद टूट गई, जो कि बसपा का पारंपरिक गढ़ है। अखिलेश यादव के बड़े बोल और निरंतर सरकार मशीनरी और सोशल मीडिया पर शब्द प्रहार मायावती के विशाल सामाजिक प्रभाव पर भारी नहीं पड़ेगा। मायावती ने टिकट वितरण में देरी करने का विकल्प चुना, लेकिन प्रतियोगियों की सूची से पता चलता है कि उन्होंने जमीन की नब्ज नहीं खोई है।

– **परमवीर सिंह**, मेल से

महंगाई नियंत्रण आवश्यक

प्रतिवर्ष बजट की प्रक्रिया व बजट पेश किया जाता है। आम खास का कितना सार्थकता भरा बजट होता है वो तो परिस्थितियों से ही समझा जा सकता है। परन्तु इसमे कोई दो मत नही विगत वर्षो से महंगाई की मार ने मध्यम वर्गीय परिवारों का घर का बजट बिल्कुल असन्तुलित कर दिया है। जितनी महंगाई का ग्राफ बढ़ता है उतनी आय के स्त्रोत तुलनात्मक दृष्टिकोण से नगण्य नजर आते है। पेट्रोल-डीजल, गैस के दाम वर्धित तो ऐसे जनमानस के बीच तेज गति की मैराथन में शामिल होकर गोल्ड मेडल लेने की होड़ में लगे है। मूलभूत सुविधाओं में महंगाई सुरसा की भांति मुंह फैलाये आम लोगो की जीवन मे शामिल होकर दीमक की तरह अंदर के अंदर खोखला कर रही है। क्या महंगाई पर नियंत्रण या कारगर नीति रीति नही बनी? अगर सामान्य वस्तुओं के भाव आसमान छुएंगे तो आम जन जीवन कैसे यापन होगा विचारणीय है। इसमें दो राय नही महंगाई के पोषक पहलु बहुत से है। परंतु उनपर चिंतन तो जरूरी है। आखिर आम परिवार जिनकी आय का मापदंड कमजोर हो तो वो इस महंगाई का सामना कैसे कर पायेगा?

– **योगेश जोशी**, बड़वाह

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

फरमाया

महामारी के बीच विकसित किए गए यूनीकॉन की संख्या हमारे देश के युवाओं की सामर्थ्य का परिचायक है।

– **नरेंद्र मोदी**
प्रधानमंत्री

मुझे वर्तमान स्थिति की पूर्व की तुलना में अधिक गंभीर नजर नहीं आती।

– **व्लादोमायर जेलेंस्की**
यूक्रेन के राष्ट्रपति

मेरी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर अपने बल पर चुनाव लड़ रही है और सरकार भी बनाएगी।

– **मायावती**
बसपा सुप्रीमो

पश्चिम में अखिलेश-जयंत की जोड़ी भाजपा के लिए चुनौती

शिव विजय सिंह। लखनऊ

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा-रालोद गठबंधन से तैयार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी ने भगवा खेमे की चिंता बढ़ा दी है। पिछले तीन चुनावों से लगातार पश्चिमी यूपी में एकतरफा जीत हासिल कर रही भाजपा के सामने विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिमी यूपी में मुसलमान और जाटों के बीच दूरी से भाजपा लाभ उठाती रही। बीजेपी को 2014 के लोकसभा, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में एकतरफा जीत हासिल हुई। लेकिन तीन कृषि कानूनों के खिलाफचले आंदोलन की वजह से किसान जातियों की नाराजगी भाजपा पर भारी पड़ रही है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जातियों के आंदोलन में जाट गुर्जर और सिखों की प्रमुख भूमिका रही। यह तीनों तबका पश्चिमी यूपी में भाजपा का सबसे मजबूत वोट माना जाता था जो इस बार बीजेपी से छिटकता नजर आ रहा है।

पश्चिमी यूपी में करीब 20 प्रतिशत जाट हैं। किसान आंदोलन में जाट, गुर्जर, मुसलमान समेत अन्य सभी जातियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसान आंदोलन के जरिए पश्चिम की विभिन्न जातियां एक दूसरे के फिर करीब आ गई हैं। यही एकता भाजपा की मुसीबत बन गई है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर आम कार्यकर्ता तक मुजफ्फरनगर दंगा समेत अन्य मुद्दों की याद दिला कर किसान जातियों खासकर जाटों को एक बार फिर अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह सफल होगा या नहीं पह देखना होगा। गठबंधन को जाटों के साथ साथ गुर्जर और मुसलमान समेत अन्य किसान जातियों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। पश्चिम यूपी के खतौली सरधना समेत दर्जनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के प्रत्याशियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है।

पश्चिम यूपी में हो रहे पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ने हैं। इन सभी सीटों पर सत्तारूढ़ दल समेत सभी विपक्षी दलों ने अपने अपने मोहरे चुनावी रणभूमि में उतार दिए हैं। पश्चिम यूपी में पहले चरण के चुनाव में हालात यह है केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को दिल्ली में जाटों को मनाने के लिए बैठक करनी पड़ी। बीजेपी पश्चिमी यूपी में जहां लोगों को दंगे की याद दिला रही है वही जयंत चौधरी किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत 13 महीने घर से दूर किसानों के आंदोलन और हाथरस कांड में विरोध के दौरान उन पर चारों तरफसे घेर कर पड़ी लाठियों की याद दिला रहे हैं। अब देखना है कि 10 फ़रवरी को पश्चिम यूपी के मतदाताओं पर किस का जादू असर करता है।

जाट साधने को सपा ने पश्चिम में इस बार 10% कम मुस्लिम उम्मीदवार उतारे

शिव विजय सिंह। लखनऊ

प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दल रालोद के साथ गठबंधन करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा करीब 10 प्रतिशत कम मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। सपा के इस फैसले को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटरों को साधने की रणनीति बताया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगे के कारण जाट-मुस्लिम के मध्य जबरदस्त दरार पड़ गई थी जिसका वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव, वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव एवं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा फायदा मिला था। बीते लगातार तीन चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत हासिल करने की एक बड़ी वजह दलितों,मुसलमानों,जाटों के इतर अन्य छोटी जातियों के बीच पैठ बनाना भी था। इस क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में कश्यप, बाल्मीकि, ब्राह्मण, त्यागी, सैनी, गुर्जर, राजपूत बिरादरी की संख्या जीत-हार में निर्णायक भूमिका में रहती है। भाजपा ने करीब 30 फीसदी वोटर वाली इस बिरादरी को अपने पक्ष में गोलबंद किया जिसका उसे फायदा भी मिला। शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की इसी रणनीति को भांपते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दल रालोद के साथ मिलकर मुस्लिम उम्मीदवारों को कम बल्कि अन्य जातियों के लोगों पर ज्यादा विश्वास जताते हुए प्रत्याशी बनाया है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दल रालोद के साथ मिलकर सभी सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। प्रथम चरण का चुनाव दस फरवरी को मतदान होना है जबकि दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। तीनों चरणों के चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा के बड़े-बड़े दिग्गजों ने डेरा डाल रखा है वहीं बुधवार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपना चुनावी मोर्चा खोल दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने सहयोगी दल रालोद के साथ मिलकर जाट वोटरों के मध्य अपनी पैठ मजबूत करने में लगे हुए हैं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी व सहयोगी दल जाट वोटरों के बीच मुख्य रूप से किसानों का मुद्दा लेकर चल रहे हैं तो वही सत्तारूढ़ भाजपा सपा सरकार के दौरान हुए दंगों को अपना मुख्य हथियार बना रही है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार की अपेक्षा करीब 10 प्रतिशत कम मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी समर में उतारे हैं। सपा-आरएलडी के गठबंधन ने पश्चिमी यूपी की करीब 136 सीटों में से 33 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं।। इसमें समाजवादी पार्टी के टिकट पर 28 और आरएलडी के टिकट पर पांच उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यानी कि सपा ने 136 में से करीब 24 फीसदी मुसलमानों को टिकट दिए हैं। यदि इससे पहले 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन ने 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश की 136 में से 43 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से 33 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के टिकट पर और 10 कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। इस तरह से सपा-कांग्रेस के गठबंधन ने करीब 32 फीसदी मुसलमानों को टिकट दिए थे। सपा की रणनीति को जाट मुस्लिम वोट से जोड़कर देखा जा रहा है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मानती है कि यादव और मुस्लिम वोट तो उसके खेमे में तो है ही अब उसे बस जाट वोटरों को भी अपने वश में करना है। शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों पर कम दांव लगाया है।

निशाना सपा-भाजपा, तरजीह मुस्लिम वोट बैंक को

सतीश सिंह। लखनऊ

पश्चिमी उत्तरप्रदेश में बसपा भले ही ध्रुवीकरण की आशंका जता रही है और वह इसको लेकर भाजपा-सपा को लगातार निशाने पर लिए हुए है पर बसपा का मुस्लिम प्रेम न केवल पिछले चुनाव में बल्कि इस चुनाव में भी बराबर बना हुआ है। अभी तक बसपा ने कुल 403 सीटों में से 286 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किये हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। बात अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की करें तो बसपा ने कुल 403 सीटों में से 99 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार लड़ाए थे जो कि 24 फीसदी थे। इनमें से महज पांच ही जीत पाये थे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार के चुनाव में बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी कुछ ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर सकेंगे। इसके साथ एक सवाल यह भी है कि कहीं अपनी जीत से ज्यादा सपा को तो नुकसान नहीं पहुंचायेंगे।

बसपा ने मुस्लिमों पर खेला दांव

अभी तक पांचवे चरण की 61 सीटों पर घोषित उम्मीदवार की सूची में बसपा ने नौ उम्मीदवार मुस्लिम उतारे हैं जबकि चौथे चरण की सीटों के लिए मायावती ने 60 सीटों में से 17 सीटों पर मुस्लिमों को उतारा है। तीसरे चरण की सभी 59 सीटों में से बसपा ने पांच मुस्लिमों को उतारा है जबकि दूसरे चरण की सभी 55 सीटों पर बसपा ने 23 मुस्लिम उतारे हैं। इसी तरह पहले चरण की 58 सीटों में से 16 पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। यानी अभी तक घोषित कुल 286 सीटों में से बसपा ने 70 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं।

मायावती ने साधा दलित-मुसलमान समीकरण

बहरहाल 2017 में बसपा के 99 मुस्लिम कैंडिडेट में से सिर्फ पांच ही जीत पाये थे। ऐसे में फिर से वही दांव चलने के पीछे जानकारों का कहना है कि मायावती कभी नहीं चाहेंगी कि सपा उनसे वोट प्रतिशत के मामले में आगे निकल जाये। ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारकर वो दलित-मुसलमान गठजोड़ के सहारे इस कोशिश में लगी हैं कि जीत चाहे जितनी सीटों पर मिले लेकिन उनका वोट प्रतिशत न गिरे। बसपा को भाजपा से ज्यादा सपा से सियासी खतरा रहता है। इस बार तो अखिलेश ने उनके दलित वोट बैंक में सेंधमारी की भरपूर कोशिशें भी की हैं।

हाल ही में जातीय राजनीति पर साधा था निशाना

बसपा का यह स्टैंड तब है जब इस चुनाव में शुरू से ही मायावती यह कहती रही हैं कि भाजपा और सपा चुनाव को साम्प्रदायिक रंग देना चाह रही हैं। उन्होंने हाल ही में ट्वीट करके कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से धर्म व जाति की राजनीति हावी है और मीडिया में भी ऐसी खबरें भरी पड़ी रहती हैं उससे ऐसा लगता है कि यह सब सपा और बीजेपी की मिलीभगत के तहत ही हो रहा है और वे चुनाव को हिन्दू-मुस्लिम व जातीय नफरती रंग देना चाहती हैं।

कांग्रेस के लिए सहारनपुर में इस बार सूखे की नौबत

- 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जीती थीं दो सीटें
- दिग्गज नेता इमरान मसूद सहित दोनों विधायक छोड़ चुके हैं हाथ का साथ

विवेक श्रीवास्तव। लखनऊ

वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सबसे शर्मनाक पराजय हुई और 70 जिलों में पार्टी का खाता तक नहीं खुला था तब उस दौर में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की धरती उसके लिए उपजाऊ साबित हुई थी। कांग्रेस ने बेहट और सहारनपुर देहात सीट पर जीत का परचम लहराया था। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखा जाए तो इस विधानसभा चुनाव में सहारनपुर की उपजाऊ धरती पर वोटों की फसल उगाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं दिख रहा है। मौजूदा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सहारनपुर जिले में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उससे कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। जिले में काफी चर्चित और कांग्रेस के प्रभावशाली नेता माने जाने वाले पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने हाथ का साथ छोड़ कर साइकिल की सवारी कर ली। उनके साथ ही कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और सहारनपुर देहात सीट से विधायक मसूद अख्तर भी सपा में शामिल हो गए।

इमरान मसूद और मसूद अख्तर के सपा में जाने के ऐलान के बाद बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। हालांकि इमरान मसूद के खास होने के बावजूद नरेश सैनी ने सपा में जाने के बजाय भाजपा का दामन थामा । कुल मिलाकर इस घटनाक्रम के बाद सहारनपुर जिले में कांग्रेस के पैर के नीचे से राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। एक तरह से देखा जाए तो पार्टी इस इलाके में चेहरा विहीन हो चुकी है। जानकारों का कहना है कि बीते एक दशक से सहारनपुर में कांग्रेस की राजनीति इमरान मसूद के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर देहात और बेहट सीट पर कांग्रेस की जीत व जिले में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के पीछे इमरान मसूद और उनके परिवार का ही प्रभाव रहा है। जाहिर है कि इमरान मसूद के जाने के बाद अब कांग्रेस का चुनावी लड़ाई में बने रहना भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

प्रदेश की नंबर एक विधानसभा सीट बेहट में

प्रभावशाली चेहरे के अभाव में कांग्रेस ने इस बार महिला कार्ड खेला है। पूनम कांबोज कांग्रेस की ओर से बेहट विधानसभा सीट पर चुनाव मैदान में उतरी हैं। 2017 में यह सीट कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस प्रत्याशी नरेश सैनी ने भाजपा के महावीर राणा को हराया था। लेकिन इस बार नरेश सैनी भाजपा के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी लड़ाई में दूर-दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहीं हैं। सहारनपुर देहात सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी लहर के बीच भी कांग्रेस नेता मसूद अख्तर जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। इस बार उनके पाला बदलकर सपा में चले जाने के बाद कांग्रेस ने इस सीट से संदीप कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। सपा ने मसूद अख्तर को टिकट तो नहीं दिया है लेकिन वह सपा प्रत्याशी आशु मलिक के हाथ मजबूत कर रहे हैं। नकुड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने इस बार रणधीर सिंह को टिकट दिया है। पिछले चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता इमरान मसूद ने भाजपा के डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को कड़ी टक्कर देते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया था। योगी सरकार में मंत्री रहे सैनी इस बार पाला बदलकर सपा के साथ जा चुके हैं। सपा ने उन्हें इस सीट पर चुनाव मैदान में उतारा है। उनको कड़ी टक्कर देने वाले इमरान मसूद भी इस बार सपा में हैं। हालांकि इमरान मसूद को सपा ने टिकट नहीं दिया है। राजनीति में कुछ भी संभव है और इसे चरितार्थ करते हुए इस बार इमरान मसूद अपने धुर विरोधी धर्म सिंह सैनी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। सहारनपुर शहर सीट पर कांग्रेस ने इस बार महिला कार्ड खेलते हुए पंजाबी समुदाय की सुखविंदर कौर को चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट पर पंजाबी समुदाय एक लाख 10 हजार की आबादी के साथ अच्छी खासी संख्या में है। यही वजह है कि कांग्रेस के अलावा बसपा ने भी पंजाबी मूल के मनीष अरोड़ा को टिकट दिया है। दो पंजाबी उम्मीदवार देने से पंजाबी समुदाय के वोट बंटने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सीधी टक्कर सपा और भाजपा के बीच ही है। गंगोह सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने अशोक सैनी को प्रत्याशी बनाया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के प्रदीप चौधरी ने जीत दर्ज कराई थी। प्रदीप चौधरी के कैराना से चुनाव लड़ कर 2019 में लोकसभा चले जाने के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा के कीरत सिंह ने जीत हासिल की थी। भाजपा ने इस बार भी कीरत सिंह पर दांव लगाया है। रामपुर मनिहारन सीट पर कांग्रेस ने ओमपाल सिंह को टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा के देवेंद्र कुमार निम ने बसपा के रविंद्र मोल्हू को मामूली अंतर से हराया था। कांग्रेस प्रत्याशी विष्णु दयाल छोटन तीसरे नंबर पर रहे थे। भाजपा ने इस बार फिर देवेंद्र कुमार निम पर भरोसा जताया है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए चर्चा में रहने वाली देवबंद सीट पर कांग्रेस ने इस बार मुस्लिम कार्ड खेलते हुए राहत खलील को मैदान में उतारा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने पर देवबंद सीट सपा के खाते में चली गई थी। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुंवर बृजेश सिंह ने सपा के माविया अली को हराया था। भाजपा से बृजेश सिंह फिर मैदान में हैं जबकि सपा ने कार्तिकेय राणा और बसपा ने राजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार भी भाजपा मुकाबले में है और वह सीट निकाल सकती है। कांग्रेस मुस्लिम प्रत्याशी राहत खलील को उतारकर सिर्फ सपा या बसपा का ही खेल बिगाड़ेगी।

आधा दर्जन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर

पहले चरण का मतदान

कमल दुबे। लखनऊ

यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। मतदान की तारीख करीब आने के साथ साथ चुनावी अखाड़े में उतरे दावेदारों की धडकनें तेज होती जा रही हैं। पहले चरण में 13 जिलों की जिन 58 सीटों पर मतदान होना है उनमें योगी सरकार के छह मंत्री भी मैदान में हैं। इन सभी मंत्रियों की विपक्ष ने मजबूत घेराबंदी की है। सरकार के इन मंत्रियों के सामने जहां अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखने की चुनौती है वही विपक्षी दलों के उम्मीदवार इन दिग्गजों को मात देने के लिये हर तरह के चुनावी हथियारों का उपयोग कर रहे हैं।

पहले चरण में उम्मीदवारों के साथ-साथ राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की निगाहें लगी है। चाहे पीएम मोदी हो या सीएम योगी आदित्यनाथ अथवा केन्द्र और राज्य के अन्य बड़े नेता। हर किसी की कोशिश पहले चरण में अपने पक्ष में मतदान करा के सात चरणों में इस चुनाव में बड़ा संदेश देने की है ताकि अगले चरणों के मतदान में फायदा मिल सके। दरअसल पहले चरण में मतदान में वोटरों के रूझान का अगले चरणों के मतदान में साफ असर देखने को मिलता रहा है। जिसे देखते हुये सत्ताधारी भाजपा सहित अन्य सभी दलों की कोशिश शुरूआती बढ़त बनाने की है।

पहले और दूसरे चरण के मतदान में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमे अधिकतर पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की है। पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की कुल 136 सीटों में भाजपा ने 109 सीटों पर अपना परचम फहरा कर विपक्ष को बुरी तरह मात दी थी। वर्ष 2012 के चुनाव को देखा जाए तो निश्चित रूप से पहले चरण में सपा को भारी बढ़त मिली थी और बसपा दूसरे नंबर पर रही लेकिन जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तो पहले चरण के शामली,मुजफ्फरनगर,मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों की 58 विधानसभा सीटों में से 53 सीटों पर भाजपा की एक तरफा जीत हुई थी। पहले चरण की भाजपा की यह जीत आगे के दूसरे चरणों में भी बढ़ती गई और फिर एक हवा ऐसी बनी कि प्रदेश में भाजपा गठबंधन की 325 सीटों की सरकार बनी। इस रिकॉर्ड जीत का असर यह हुआ कि भाजपा ने पहले चरण की 58 सीटों में से छह विधायकों को मंत्री बनाया और अब यह सभी मंत्री 2022 के चुनाव मैदान में प्रत्याशी हैं जहां इनके प्रतिद्वंदी इन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

पहले चरण में शामली जिले की थानाभवन विधानसभा सीट से प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश राणा चुनाव मैदान में हैं। राणा के खिलाफसपा रालोद गठबंधन उम्मीदवार अशरफ अली बसपा के जहीर मलिक और कांग्रेस के हाजी अखलाक प्रत्याशी हैं। गन्ना मंत्री राणा क्षेत्र में लोकप्रिय हैं लेकिन सपा रालोद गठबंधन के अशरफ अली उन्हें सीधी टक्कर दे रहे हैं। इसी तरह मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट से प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल चुनाव मैदान में हैं। अग्रवाल वैसे तो लगातार चर्चा में रहते हैं लेकिन इस बार वह विधानसभा चुनाव के कारण चर्चा में हैं। अग्रवाल के खिलाफसपा रालोद गठबंधन के अजय, बसपा के पुष्पाकर लाल और कांग्रेस के सुबोध शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल अग्रवाल को रालोद प्रत्याशी अजय सीधी टक्कर दे रहे हैं जिससे सभी की निगाहें अग्रवाल की विधानसभा चुनाव की तरफ लगी हुई हैं।

विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ही प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री अतुल गर्ग गाजियाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गर्ग के खिलाफ सपा के विशाल वर्मा, बसपा के कृष्ण कुमार शर्मा और कांगेस के सुशांत गोयल चुनाव मैदान में है। गर्ग क्षेत्र में अपने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए जहां वोट मांग रहे हैं वहीं उनके प्रतिद्वंदी विशाल वर्मा कृष्ण कुमार शर्मा पांच साल में मंत्री रहते हुए कुछ भी न किए जाने का आरोप लगाते हुए चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पहले चरण के ही चुनाव में प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह अतरौली विधानसभा सीट प्रत्याशी हैं। संदीप सिंह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के संस्थापकों में से एक कल्याण सिंह के पौत्र हैं। अतरौली विधानसभा जहां सिंह की पारिवारिक सीट है वहीं उनके पिता राजवीर सिंह भी सांसद हैं जिसके कारण उनकी क्षेत्र में जबरदस्त पकड़ है। बावजूद इसके उनके खिलाफ सपा से वीरेश यादव बसपा से ओमवीर सिंह और कांग्रेस से धर्मेश कुमार प्रत्याशी हैं। सिंह को सपा और बसपा प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

पहले चरण के ही चुनाव में छाता विधानसभा से प्रदेश के दुग्ध विकास एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह प्रत्याशी हैं। सिंह क्षेत्र में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ सपा-रालोद गठबंधन के रालोद से तेजपाल सिंह, बसपा से सोनपाल सिंह और कांग्रेस से पूनम देवी प्रत्याशी हैं। विधानसभा चुनाव में चौधरी के प्रस्तावक की बीते दिनों हत्या हो गई जिसके कारण इस चुनाव में संघर्ष शुरू हो गया है। चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह को रालोद के तेजपाल सिंह कड़ी टक्कर दे रहे हैं और क्षेत्र में उनके खिलाफ जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मथुरा जिले की मथुरा विधानसभा सीट से ही प्रदेश सरकार के कद्दावर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा चुनाव मैदान में हैं। शर्मा के खिलाफ सपा के देवेंद्र अग्रवाल बसपा के सतीश कुमार शर्मा और कांग्रेस के प्रदीप माथुर चुनाव मैदान में हैं। फिलहाल शर्मा चुनाव मैदान में जितनी मजबूती से जुटे हैं ठीक उसी मजबूती से सपा के देवेंद्र अग्रवाल और कांग्रेस के प्रदीप माथुर भी उन्हें चुनावी टक्कर दे रहे हैं। जिले की इस हाई प्रोफाइल सीट सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई है क्योंकि जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है और मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है चुनाव रोमांचक होता जा रहा है।

पहले चरण के चुनाव में वैसे तो कई चर्चित नाम है। इसमें कैराना विधानसभा सीट से मृगांका सिंह, नाहिद हसन, बुढ़ाना से उमेश मलिक, बड़ौत से कृष्ण पाल सिंह, सरधना से संगीत सोम, लोनी से नंदकिशोर गुर्जर, नोएडा से पंकज सिंह,अनूपशहर से संजय शर्मा, बरौली से जय वीर सिंह, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय, एत्मादपुर से डॉक्टर धर्मपाल सैनी, आगरा कैंट से गिरिराज सिंह धर्मेश,आगरा ग्रामीण सुरक्षित से उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबू लाल और बाह विधानसभा सीट से रानी पक्षालिका सिंह चुनाव मैदान में हैं जिस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं।

घृणा फैलाने वाला भाषण देने वालों को सजा मिलनी चाहिए: इंद्रेश कुमार

●आरएसएस नेता ने कहा, धर्म कोई अपवाद नहीं, राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों पर भी साधा निशाना

भाषा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने हाल में हरिद्वार में हुई धर्म संसद में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित रूप से नफरती भाषण दिए जाने की निंदा की और कहा कि भड़काऊ व विभाजनकारी भाषण देने वालों को बिना किसी अपवाद के कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए। कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी कि एक हिंदुत्ववादी ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, को लेकर उनपर निशाना साधा और कहा कि यह भी घृणा भाषण है। कुमार ने नफरत की राजनीति को भ्रष्टाचार के समान करार दिया और सभी राजनीतिक दलों व उनके नेताओं से नफरत फैलाने तथा समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करने से बचने का आह्वान किया।

आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ने कहा कि किसी भी समुदाय, जाति या समूह के खिलाफ भड़काऊ और विभाजनकारी टिप्पणी करने के बजाय, उन्हें देश व उसके लोगों के सर्वोत्तम हित में भाईचारे और विकास की राजनीति करनी चाहिए।

उन्होंने उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद और हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसी तरह के एक कार्यक्रम में दिए गए कथित तौर पर घृणा फैलाने वाले भाषणों पर उनके विचार पूछे जाने पर कहा, किसी भी तरह की नफरती बयानबाजी निंदनीय है। सभी नफरती बयानों की निंदा की जानी चाहिए और कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। किसी को भी अपवाद नहीं माना जाना चाहिए।

कुमार ने कहा कि नफरती बयानबाजी के कई उदाहरण हैं और ऐसे सभी विभाजनकारी कृत्यों के खिलाफ कानूनी कार्वाई करना समय की आवश्यकता है क्योंकि वे देश का माहौल खराब करते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश ऐसी जगह है, जैसा लगता है की हर समय बस लड़ो और टूटो तो ठीक नहीं है। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस और उसकी विचारधारा को जिम्मेदार ठहराने के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि वे निराधार आरोप लगा रहे हैं जबकि उनके पास इन्हें साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

कुमार ने कहा, कि 60 साल से ज्यादा समय हो गया, हम सुनते आ रहे हैं कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस और उसकी विचारधारा का हाथ था[8230] संघ पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। लेकिन इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस और अन्य दल इसे (आरोप) साबित नहीं कर सके। आरएसएस के खिलाफ उनके निराधार आरोप भी नफरती बयान के समान हैं। उन्होंने पूछा कि अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी के लिए भी कांग्रेस पर निशाना साधा कि एक हिंदुत्ववादी ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बना कहा कि अब, वे कहते हैं कि हिंदुत्ववादियों ने गांधी को मार डाला। यह भी नफरती बयान है। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों के एक वर्ग या संगठन के खिलाफ नफरत पैदा करने वाले निराधार आरोपों को भी घृणा फैलाने वाला भाषण माना जाना चाहिए।

कुमार ने कहा कि सभी नफरती बयानों को एक ही चश्मे से देखा जाना चाहिए। हम घृणित, उत्तेजक और विभाजनकारी बयानों पर कार्वाई को लेकर अंतर नहीं कर सकते हैं, जबकि दोनों प्रकृति और सार में समान हैं।

उन्होंने कहा कि नफरती बयान देने वालों के खिलाफ कार्वाई की जानी चाहिए, चाहे वे कितने भी बड़े और प्रभावशाली हों या किसी पार्टी या समूह के हों। यह समय की जरूरत है। आरएसएस नेता ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए।

मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी पर साध्वी विभानंद गिरि को नोटिस

भाषा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने के मामले में साध्वी विभानंद गिरि को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। एनसीडब्ल्यू ने एक ट्वीट में कहा कि उसने 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। एक वीडियो में गिरि को कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी करते हुए सुना गया था। आयोग ने ट्वीट किया, मामले का संज्ञान लिया है और साध्वी गिरि से वीडियो में की गई टिप्पणी पर स्पष्टीकरण मांगा है।

धर्मशाला में निर्वासित तिब्बतियों ने बीजिंग ओलंपिक खेलों के उद्घाटन से एक दिन पहले चीन में मानवाधिकारों के हनन को उजागर करने के लिए सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया

शशिकला सहित छह लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

बेंगलुरु। भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो (एसीबी) की कर्नाटक इकाई ने केन्द्रीय कारागार में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे. जयललिता की करीबी सहयोगी वी. के. शशिकला को सुविधाएं मुहैया कराने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है। एसीबी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया कि कर्नाटक के दो वरिष्ठ कारागार अधिकारियों और शशिकला सहित छह लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

करोड़ों रुपए की आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला पाराप्पना अग्रहारा केन्द्रीय कारागार में चार साल की सजा काट चुकी है।

शिमला में गुरुवार को भारी बर्फबारी ने सड़क पर खड़ी कारों व आसपास के इलाके को ढक दिया

न्यायालय ने पांच को होने वाली गेट परीक्षा स्थगित करने से किया इनकार

भाषा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने देश के अलग-अलग हिस्सों में कोविड-19 संबंधी पाबंदियों के चलते पांच फरवरी को होने वाली इंजीनियरिंग में स्नातक अभिक्षमता परीक्षा (गेट) स्थगित करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि निर्धारित परीक्षा से 48 घंटे पहले गेट परीक्षा स्थगित करने से अराजकता एवं अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी। पीठ ने कहा कि वह उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, जिन्होंने इसके लिए तैयारी की है। पीठ ने कहा कि यह शिक्षण नीति का मामला है कि कब परीक्षा होनी चाहिए और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

शीर्ष अदालत ने कहा कि नौ लाख छात्र यह परीक्षा देने वाले हैं और करीब 20,000 छात्रों ने इसे स्थगित करने के संबंध में ऑनलाइन याचिका का समर्थन किया है। पीठ ने कहा कि छात्रों ने इसके लिए तैयारी की है और अदालत परीक्षा स्थगित करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। सुनवाई की शुरुआत में, पीठ ने कहा कि हम इस तरह से परीक्षा स्थगित करना शुरू नहीं कर सकते, अब सब कुछ खुल रहा है। हम इस तरह छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारे सामने याचिकाकर्ताओं में से एक कोचिंग सेंटर है। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता सतपाल सिंह ने कहा कि कई शहरों में लॉकडाउन और रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू हैं और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर ने कहा है कि हल्के लक्षणों वाले छात्रों को भी परीक्षा देने से रोका जा सकता है। अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल एक महीने के लिए परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध कर रहे हैं।

इस पर पीठ ने कहा कि वह इतने आश्वस्त कैसे हैं कि एक महीने बाद स्थिति बेहतर हो जाएगी। शीर्ष अदालत गेट परीक्षा स्थगित करने संबंधी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को बुधवार को सहमत हुई थी। 200 केन्द्रों पर नौ लाख छात्र परीक्षा देंगे।

डब्ल्यूएचओ जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखा रहा: टीएमसी सांसद

भाषा। नई दिल्ली

राज्यसभा में बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा जम्मू एवं कश्मीर को पाकिस्तान का और अरुणाचल प्रदेश को एक अलग हिस्से के रूप में दिखाए जाने का मामला उठाते हुए केंद्र सरकार से इस पर उचित कदम उठाने की मांग की।

उच्च सदन में शून्य काल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने जब यह मामला उठाया तो सभापति एम वेंकैया नायडू ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

सेन ने कहा कि एक कोरोना योद्धा के रूप में वह अक्सर अंतरराष्ट्रीय आंकड़े जानने के लिए कोविड-19 संबंधी डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट देखते हैं लेकिन उस समय उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर को पाकिस्तान का और अरुणाचल प्रदेश को अलग हिस्से के रूप में दिखाया गया। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को जब मैं अंतरराष्ट्रीय आंकड़े कोविड-19 डॉट डब्ल्यूएचओ डॉट आईएनटी पर देख रहा था तब मैंने पाया कि भारत के मानचित्र को ब्लू रंग में दिखाया गया है। आश्चर्यजनक रूप से जम्मू एवं कश्मीर का रंग अलग दिखाया गया था। जब मैं ब्लू रंग वाले हिस्से पर क्लिक कर रहा था तो उसमें भारत के आंकड़े दिखा रहा था लेकिन जब मैंने दूसरे रंग (जम्मू एवं कश्मीर) को क्लिक किया तो वह पाकिस्तान के आंकड़े दिखा रहा था।

उन्होंने कहा कि उन्हें उस समय और आश्चर्य हुआ जब जम्मू एवं कश्मीर के एक हिस्से को अलग रंग में दिखाया जा रहा था।

उन्होंने कहा, जम्मू एवं कश्मीर के हिस्से के भीतर के एक हिस्से को क्लिक करने पर वह चीन के आंकड़े बता रहा था। इतना ही नहीं, मैंने उस मानचित्र में यह भी देखा कि अरुणाचल प्रदेश को भी अलग हिस्से के रूप में दिखाया गया है।

सेन ने कहा कि इस मामले में सरकार को बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खासकर तब जब हमारी सरकार अपने ही मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं, विशेष रूप से हमारी पार्टी के नेता और महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सक्रिय होकर जासूसी के लिए पेगासस खरीद रही है।

राहुल खुद को भारत का राजा समझते हैं : किरण रिजिजू

भाषा। नई दिल्ली

कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बृहस्पतिवार को राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए दावा किया कि कांग्रेस नेता पहले युवराज की तरह व्यवहार करते थे और अब वह खुद को भारत का राजा समझते हैं।

रिजिजू ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर उनके (राहुल गांधी के)इस आरोप कि भाजपा सरकार ने दो भारत बना दिए हैं, को लेकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने गांधी के लगातार विदेशी दौरे की भी आलोचना की। कानून मंत्री ने ट्विटर पर कहा, दो भारत हैं- पहला, लोग उच्च वर्ग के समाज की जिंदगी जीते हैं, रेव पार्टी में जाते हैं, अकसर विदेशों की यात्रा करते हैं और काफी रंगीन जिंदगी जीते हैं। दूसरा, लोग भारत में सामान्य जीवन जीते हैं, हर वक्त जरूरतमंद लोगों के साथ रहते हैं, भारतीय की तरह सोचते हैं और भारतीय परंपराओं का पालन करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने दो भारत बना दिए हैं। एक अमीर लोगों के लिए और दूसरा गरीब लोगों के लिए। उन्होंने कहा था कि देश के लिए भाजपा सरकार का दृष्टिकोण राजा की तरह है जो शासन के लिए डंडा चलाता है न कि वार्ता एवं समझौते का रास्ता अपनाता है।

एक और गवाह बयान से पलटा एटीएस पर लगाया आरोप

मालेगांव विस्फोट

भाषा। मुंबई

वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के एक गवाह ने बृहस्पतिवार को यहां निचली अदालत में दावा किया कि महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने जांच के दौरान उसे प्रताड़ित किया गया और उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं का नाम लेने के लिए मजबूर किया गया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश पी आर सित्रे के समक्ष गवाह ने कहा कि उसने एटीएस को अपनी मर्जी से बयान नहीं दिया था। मामले में अब तक अभियोजन पक्ष के 222 गवाहों से पूछताछ की गई, जिनमें से 17 मुकर गए। मुकरने वाले इन गवाहों ने अभियोजन के मामले का समर्थन करने से इनकार कर दिया। गवाह ने बृहस्पतिवार को अदालत को बताया कि शुरुआत में मामले की जांच करने वाले एटीएस ने उसे कई बार हिरासत में लिया और उसे प्रताड़ित किया गया। गवाह ने आरोप लगाया कि एटीएस अधिकारियों ने उसे आरएसएस और उसके नेताओं का नाम लेने के लिए मजबूर किया। गवाह ने कहा कि वह आरएसएस का सदस्य नहीं था और न ही वह आरएसएस के किसी पदाधिकारी का नाम जानता था।

इससे पहले अभियोजन पक्ष के एक अन्य गवाह ने अदालत को बताया था कि एटीएस ने उसे योगी आदित्यनाथ (अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री) और आरएसएस के चार नेताओं का नाम लेने के लिए मजबूर किया। उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल से बंधे एक विस्फोटक उपकरण के फटने से छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए।

श्रीलंक ने 56 भारतीय मछुआरों को रिहा किया

नई दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि श्रीलंका ने 25 जनवरी को 56 भारतीय मछुआरों को रिहा किया और यह सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया कि दोनों पक्षों को किसी भी परिस्थिति में मछुआरा समुदाय के विरूद्ध बल प्रयोग नहीं करना चाहिए।

विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता देती है उनहोंने कहा कि विदेश मंत्री ने 15 जनवरी को श्रीलंका के वित्त मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में श्रीलंका की हिरासत से भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई के मुद्दे पर चर्चा की थी।

मुरलीधरन ने कहा कि परिणाम स्वरूप श्रीलंका की सरकार ने 56 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है और वर्तमान में श्रीलंका की हिरासत में कोई भारतीय मछुआरा नहीं है।

हाई कोर्ट ने वानखेड़े की अवमानना याचिका पर नवाब मलिक से मांगा जवाब

भाषा। मुंबई

बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की अवमानना याचिका पर जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति एसजे कथावाला और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की पीठ ने यह भी पूछा कि मलिक वानखेड़े परिवार के खिलाफ कोई मानहानिकारक टिप्पणी नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय को दिए गए हलफनामे के साथ बार-बार रियायतें क्यों ले रहे हैं। पीठ ने कहा कि अगर मंत्री इस तरह से रियायत का दुरुपयोग करते रहे तो अदालत इसे वापस ले लेगी। पिछले महीने ज्ञानदेव वानखेड़े ने मलिक के खिलाफ उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि मंत्री ने वानखेड़े परिवार के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं करने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के संबंध में पिछले साल दिसंबर में अदालत को दिए गए अपने वचन का जानबूझकर उल्लंघन किया।

ज्ञानदेव वानखेड़े ने पिछले साल उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें मलिक को ऐसी कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से रोकने का अनुरोध किया गया था जो उनके, उनके बेटे समीर या उनके परिवार के लिए अपमानजनक हो। अपनी अवमानना याचिका में ज्ञानदेव वानखेड़े ने दावा किया कि मलिक ने अपने वचन का उल्लंघन किया और हाल में इस साल दो और तीन जनवरी को आपत्तिजनक टिप्पणी की। बृहस्पतिवार को ज्ञानदेव के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने मलिक द्वारा अपना हलफनामा देने के बाद समीर वानखेड़े के खिलाफ जाति प्रमाण पत्र और क्रूज जहाज से मादक पदार्थ की जब्ती मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ी कुछ टिप्पणियों का जिक्र किया।

मलिक की टिप्पणियों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति कथावाला ने कहा कि अगर मंत्री को इस तरह से रियायत का दुरुपयोग करना है तो अदालत इसे वापस ले लेगी। पीठ ने पूछा, अगर आप इसी मंशा से रियायत लेते हैं तो हम रियायत वापस ले लेंगे। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप उनको बदनाम करना चाहते हैं। आपका इरादा क्या है? मलिक के वकील रमेश दुबे ने कहा कि मंत्री यह दिखाने के लिए अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं कि बयान रियायत (केवल एक लोक अधिकारी के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में टिप्पणी करने पर) के दायरे में आते हैं।

बिहार और किसी अन्य राज्य को विशेष दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है: केंद्र सरकार

भाषा। नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने कहा है कि बिहार और देश के किसी अन्य प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में जदयू के सांसदों राजीव रंजन सिंह उर्फ़ लल्लन सिंह और कौशलेंद्र कुमार की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी।

दोनों सांसदों ने सवाल किया था कि बिहार और कुछ अन्य राज्यों के पिछड़ेपन से संबंधित नीति आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर क्या बिहार को विशेष दर्जा देने की सरकार की कोई योजना है? इसके जवाब में मंत्री ने कहा, नीति आयोग ने राज्यों के पिछड़ेपन पर कोई रिपोर्ट जारी नहीं हैं। बहरहाल, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में बहुआयामी गरीब लोगों का उच्चतम अनुपात सबसे अधिक है जो राज्य की जनसंख्या का 51.91 प्रतिशत है। इसके बाद झारखंड में 42.16 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 37.79 प्रतिशत है। सिंह के मुताबिक, पहाड़ी, दुर्गम भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व और पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे सामरिक स्थानों जैसे विशेष मुद्दों पर विचार करते हुए अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद ने कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था।

उन्होंने कहा कि इसके बाद चौदहवें वित्त आयोग ने साझायोग्य करों के वितरण को लेकर सामान्य श्रेणी के राज्यों एवं विशेष श्रेणी के राज्यों में कोई अंतर नहीं किया।

मंत्री ने कुछ अन्य विवरण रखते हुए यह भी बताया कि 2015 में भारत सरकार ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, इस पृष्ठभूमि में बिहार सहित किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कांग्रेस ने झारखंड के लिए समन्वय समिति का गठन किया

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अपनी झारखंड इकाई के लिए 17 सदस्यीय समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश प्रभारी और महासचिव अविनाश पांडे करेंगे। पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए समन्वय समिति गठित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। अविनाश पांडे को इस समिति का अध्यक्ष और उमंग सिंगार को सह-अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस समिति में संयोजक की भूमिका निभाएंगे।

नासिक में पहाड़ की चोटी से गिरकर दो पर्वतारोहियों की मौत, एक घायल

भाषा। नासिक (**महाराष्ट्र**)

नासिक जिले के चांदवाड़ तालुका में पहाड़ की चोटी से गिरकर दो पर्वतारोहियों की मौत हो गई है जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है।

पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि दुर्घटना बुधवार की रात मनमाड के पास हदबीची शेंडी पर हुई। हदबीची शेंडी को थम्सअप चोटी भी कहा जाता है। एक अधिकारी ने बताया कि अहमदनगर से कम से कम 18 का पर्वतारोहियों एक दल 120 फुट ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचा, लेकिन वहां से नीचे आते हुए यह दुर्घटना हो गई।

उन्होंने बताया कि दल के दो सदस्य मयूर दत्तात्रेय महास्के (24) और अनिल शिवाजी वाग (34) करीब 100 फुट की ऊंचाई से गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जबकि प्रशांत पवार को गंभीर चोटें आई हैं।

किशन बोलिया हत्या मामले में तीन और आरोपी गिरफ्तार

भाषा। अहमदाबाद

गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने किशन बोलिया की हत्या के सिलसिले में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बोलिया को हाल में कथित आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट को लेकर गोली मार दी गई थी। सहायक पुलिस आयुक्त बी.एच. चावड़ा ने कहा कि बुधवार को हुईं गिरफ्तारियों के बाद एटीएस द्वारा अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या आठ हो गई है। गिरफ्तार लोगों में दो मुस्लिम धर्मगुरू भी शामिल हैं।

बोलिया की 25 जनवरी को अहमदाबाद जिले के धंधुका शहर में शब्बीर चोपडा और इम्तियाज पठान ने कथित तौर पर एक फेसबुक पोस्ट को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने दावा किया था कि इस पोस्ट से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। चावड़ा ने कहा कि चोपडा और उसके दोस्त पठान ने पहले भी इसी तरह की फेसबुक पोस्ट साझा करने के लिए पोरबंदर के निवासी साजन ओडेदरा को मारने की योजना बनाई थी।

बुधवार को राजकोट में रहने वाले पिस्तौल आपूर्तिकर्ता रमीज सेता, पोरबंदर के निवासी मोहम्मद हुसैन खत्री और धंधुका के मतीन मॉडन को गिरफ्तार किया गया।

अधिकारी ने कहा, दो आरोपी ओडेदरा को मारने के लिए पोरबंदर गए थे, जिन्होंने इसी तरह की पोस्ट साझा की थी। उस समय, खत्री ने उन्हें ओडेदरा का घर दिखाया था, रहने की व्यवस्था की थी और जानकारी इकट्ठा करने में दोनों की मदद की थी। चूंकि ओडेदरा उस समय जेल में था, इसलिए दोनों उसे मार नहीं सके और घर लौट गए।

शादी के जरिए आठ दूल्हों को ठगने वाली भगोड़ी दुल्हन गिरफ्तार

भाषा। जबलपुर

मध्य प्रदेश में जबलपुर पुलिस ने पुरुषों से शादी करने के बाद नकदी व गहने लेकर भाग जाने वाली 28 वर्षीय महिला सहित कथित ठग गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक उर्मिला अहिरवार उर्फ रेणु राजपूत पर इस तरह अब तक कम से कम आठ लोगों को ठगने का शक है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों की पहचान अर्चना बर्मन उर्फ अर्चना राजपूत (40), भागचंद कोरी (22) और अमर सिंह (50) के रुप में हुई है। ओमती थाने के प्रभारी निरीक्षक एस एस बघेल ने बताया कि ठग गिरोह का ताजा पीड़ित पड़ोस के सिवनी जिले का निवासी दशरथ पटेल (41) है। उन्होंने बताया कि उर्मिला ने इससे पहले सात अन्य लोगों को धोखा देने की बात कबूल की है। उन्होंने कहा कि वह एक व्यक्ति से शादी कर कुछ दिनों बाद उसके घर से गहने और नकदी लेकर भाग जाती थी। इस तरह उसने राजस्थान के जयपुर, कोटा, धौलपुर और मध्य प्रदेश के सागर एवं दमोह में पुरुषों को धोखा दिया है।

बघेल ने बताया कि सिवनी के पटेल का विवाह उर्मिला के साथ अर्चना, अमर सिंह और अन्य के माध्यम से तय हुआ था। प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक, अर्चना ने उर्मिला व अन्य को अपने रिश्तेदार के तौर पर पेश किया था और पटेल ने शादी के दौरान अमर सिंह को गहने, कपड़े और नकद राशि भेंट की थी। अमर सिंह व अन्य साथियों ने विवाह के दौरान दुल्हन का रिश्तेदार होने का नाटक किया।

अधिकारी ने मंगलवार को जबलपुर में विवाह के बाद दंपति कार से अपने गांव रवाना हुए तो रास्ते में उर्मिला एक स्थान पर अस्वस्थ होने की बात कहकर कार से उतर गई।

शेयर बाजार में तेजी थमी, सेंसेक्स 770 अंक टूटा

भाषा । मुंबई

शेयर बाजार में पिछले तीन दिन से जारी तेजी पर बृहस्पतिवार को विराम लगा और बीएसई सेंसेक्स 770 अंक का गोता लगाकर 59,000 अंक के नीचे बंद हुआ। आईटी, वित्तीय और बैंक शेयरों में मुनाफावसूली से यह गिरावट आई। कारोबारियों के अनुसार, यूरोपीय बाजारों में केंद्रीय बैठक की बैठकों से पहले निवेशकों में चिंता तथा घरेलू बाजार में कमजोर वृहत आर्थिक आंकड़े से निवेशक जोखिम लेने से बचे। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 770.31 अंक यानी 1.29 प्रतिशत टूटकर 58,788.02 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 219.80 अंक यानी 1.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,560.20 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स शेयरों में 3.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे अधिक नुकसान में एचडीएफसी का शेयर रहा। इसके अलावा इन्फोसिस, एलएंडटी, कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व और टेक महिंद्रा में भी प्रमुख रूप से गिरावट रही। सेंसेक्स के 25 शेयर नुकसान में जबकि पांच लाभ में रहे। लाभ में रहने वाले पांच शेयर आईटीसी, मारुति, टाइटन, एसबीआई और एशियन पेंट्स हैं। इनमें 1.14 प्रतिशत तक की तेजी रही। वृहत आर्थिक मोर्चे पर देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां जनवरी के महीने में नरम पड़ी हैं। बृहस्पतिवार को जारी एक मासिक सर्वे के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बढ़ने के बीच इसकी रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों और मुद्रास्फीतिक दबाव के साथ नए कारोबार में काफी धीमी गति से वृद्धि हुई। आईएचएस मार्किट के अनुसार मौसमी रूप से समायोजित भारत सेवा व्यापार गतिविधियां सूचकांक जनवरी में मासिक आधार पर घटकर 51.5 रहा, जो दिसंबर में 55.5 था। यह पिछले छह महीने में विस्तार की सबसे धीमी दर है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, वैश्विक बाजारों में बिकवाली से हुआ नुकसान मंदड़ियों के पक्ष में रहा और घरेलू बाजार में गिरावट रही।

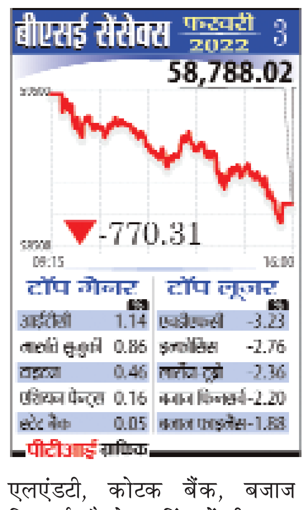

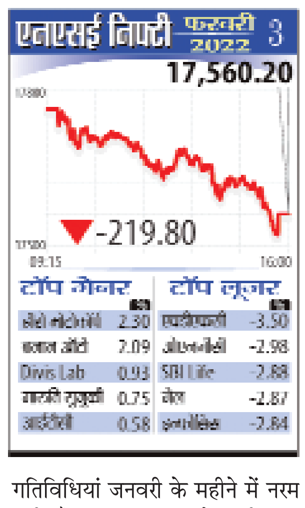

सभी प्रमुख क्षेत्रों में बिकवाली दबाव रहा। हालांकि, वाहन बिक्री आंकड़े जनवरी में सकारात्मक रहने से वाहन शेयरों में कुछ प्रतिरोध दिखा। उन्होंने कहा, अमेरिकी वायदा बाजार में दबाव दिखा। इसका कारण मेटा (पूर्व में फेसबुक) का वित्तीय परिणाम कमजोर रहना है। वहीं यूरोपीय बाजारों में केंद्रीय बैंक की नीतिगत घोषणा में ब्याज दर बढ़ाए जाने की आशंका में गिरावट का रुख रहा। रेलिगेयर ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्रा ने कहा, ...वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू बाजार में उठा-पटक रही और यह रुख अभी बना रह सकता है। इसका कारण वैश्विक बाजार का रुख तथा कंपनियों के वित्तीय परिणाम हैं। एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्की नुकसान में जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहा। चीन और हांगकांग समेत एशिया के कई अन्य बाजार चंद्र नववर्ष के मौके पर बंद रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में ज्यादातर में गिरावट का रुख रहा।इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.65 प्रतिशत फिसलकर 88.89 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर पांच पैसे की गिरावट के साथ 74.88 पर बंद हुई। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक पूंजी बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे। उन्होंने बुधवार को 183.60 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे।

गेल का तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ दोगुना से अधिक होकर 3,288 करोड़ रुपए पर

नई दिल्ली (भाषा)

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2021) में दोगुना से अधिक होकर 3,287.99 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ने से कंपनी के लाभ में वृद्धि हुई है। गेल (इंडिया) ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ बढ़कर 3,287.99 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की इसी अवधि में यह।,487.33 करोड़ रुपए था। कंपनी ने अनुसार, उसका लाभ जुलाई-सितंबर तिमाही की तुलना में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 15 प्रतिशत अधिक रहा है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में ईंधन के विपणन से।,749.71 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। एक साल पहले की इसी अवधि में कंपनी ने ईंधन विपणन पर 73.70 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।

क्विक न्यूज

एक्जिम बैंक ने श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों के लिए 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा दी

मुंबई। भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों के वित्तपोषण के लिए 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा दी है। एक्जिम बैंक ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि उसने श्रीलंका को 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा के लिए एक समझौता किया है। इसके साथ एक्जिम बैंक भारत सरकार की तरफ से अबतक श्रीलंका को कुल 2.18 अरब डॉलर मूल्य की 10 कर्ज सुविधाएं उपलब्ध करा चुका है। श्रीलंका को दी गई कर्ज सुविधाओं के तहत शामिल परियोजनाओं में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति, रेलवे और रक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं।

2022-23 में बिजली क्षेत्र की मांग में वृद्धि के वापस सामान्य होने की उम्मीद: इंड-रा

नई दिल्ली। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) ने वित्त वर्ष 2022-23 में बिजली क्षेत्र के लिए एक नरम दृष्टिकोण के साथ अगले वित्त वर्ष में मांग में वृद्धि के छह से सात प्रतिशत के सामान्य स्तर पर वापस आने की उम्मीद जताई है। इंड-रा ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, वित्त वर्ष 2022-23 में बिजली क्षेत्र के लिए एक तटस्थ दृष्टिकोण की उम्मीद है। हमारा मानना है कि थर्मल बिजली संयंत्रों के समग्र प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) में सुधार जारी रहेगा और अगले वित्त वर्ष में 60 प्रतिशत के करीब पहुंच जाएगा। पीएलएफ में सुधार काफी हद तक बिजली की मांग में लगातार वृद्धि और कोयला आधारित उत्पादन पर निरंतर निर्भरता के कारण हुआ है। इसके अलावा इंड-रा को उम्मीद है कि उच्च आधार को देखते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मांग में वृद्धि छह से सात प्रतिशत के सामान्य स्तर पर वापस आ जाएगी।

आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए एक अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी

इस्लामाबाद (भाषा)। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान के लिए अपने छह अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आईएमएफ नकदी की कमी का सामना कर रहे पाकिस्तान को लगभग एक अरब डॉलर के ऋण की तत्काल एक किश्त जारी करेगा। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को वाशिंगटन डीसी में छठी समीक्षा पूरी करने और विस्तारित फंड सुविधा के तहत एक अरब डॉलर की किश्त जारी करने के पाकिस्तान के अनुरोध पर विचार करने के लिए एक बैठक की। इसके बाद यह किश्त जारी की गई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तारिन ने भी एक ट्वीट में मंजूरी की पुष्टि की है। गौरतलब है कि पाकिस्तान और आईएमएफ ने जुलाई 2019 में तीन साल की विस्तारित फंड सुविधा के तहत आर्थिक नीतियों पर एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को 39 महीने की अवधि के लिए लगभग छह अरब डॉलर दिए जाएंगे।

सेबी ने निपटान आदेशों पर उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति में बदलाव किया

नई दिल्ली । पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निपटान आदेशों और अपराध शमन (कंपाउंडिंग) पर गठित चार सदस्ईय उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दी जानकारी के मुताबिक समिति की अध्यक्षता अब कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जय नारायण पटेल करेंगे। इससे पहले समिति की अध्यक्षता बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय सी डागा कर रहे थे। सेबी ने अपनी समिति में फेरबदल करते हुए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के पूर्व अध्यक्ष एम एस साहू और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पूर्णिमा आडवाणी को नए सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत सरकार के कानून तथा न्याय मंत्रालय मे पूर्व कानून सचिव पी के मल्होत्रा समिति के सदस्य के रूप में बने रहेंगे।

रिजर्व बैंक अगले हफ्ते मौद्रिक समीक्षा में रिवर्स रेपो दर 0.25 प्रतिशत बढ़ा सकता है: रिपोर्ट

मुंबई। ब्रिटेन की एक ब्रोकरेज फर्म ने बृहस्पतिवार को कहा कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) अतिरिक्त नकदी को सोखने के लिए रिवर्स रेपो दर में 0.25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती है, हालांकि रेपो दर, जिस पर केंद्रीय बैंक उधार देता है, में यथास्थिति बनी रह सकती है। बार्कलेज के विश्लेषकों ने अगले सप्ताह होने वाली एमपीसी की बैठक से पहले कहा, ओमीक्रोन स्वरूप के प्रकोप और अपेक्षाकृत अनुकूल मुद्रास्फीति के बीच रिजर्व बैंक के पास वृद्धि समर्थक मौद्रिक नीति को बनाए रखने के लिए गुंजाइश है। बार्कलेज ने रिपोर्ट में कहा कि केंद्रीय बैंक अपने नकदी प्रबंधन उपायों के मद्देनजर रिवर्स रेपो दर में 0.20-0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है। इसके अलावा भी कई विश्लेषकों ने रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। उनका कहना है कि सरकारी उधारी में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी के कारण रिजर्व बैंक नीति सामान्ईकरण की ओर बढ़ सकता है।

बजट में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए 283.5 करोड़ रुपए का आवंटन

नई दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड (शुरुआती कोष) योजना के लिए 283.5 करोड़ रुपए आवंटित किए है। यह राशि लगभग 100 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से अधिक है। स्टार्टअप इकाइयों के लिए कोषों के कोष (फंड ऑफ फंड्स) के तहत बजटीय आवंटन।,000 करोड़ रुपए था। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के फंड[8360] ऑफ फंड्स (एफएफएस) की स्थापना की थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एफएफएस का परिचालन करने वाली एजेंसी है। इसके बाद अप्रैल, 2021 में सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस) की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप को अवधारणा के प्रमाण, मूल विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसाईकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के लिए आवंटन को 2021-22 में संशोधित अनुमान 32.83 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2022-23 के लिए 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) का बजट भी अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ाकर 66.16 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि इस वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में यह 60.67 करोड़ रुपए था। फुटवियर, लेदर एंड एक्सेसरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफएलएडीपी) के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 208 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारों के लिए आवंटन 2021-22 में संशोधित अनुमान।,335.15 करोड़ रुपए से बढ़ाकर।,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

देश का चीनी उत्पादन अक्टूबर-जनवरी में 5.64 प्रतिशत बढ़कर 1.87 करोड़ टन पर

भाषा । नई दिल्ली

चालू विपणन वर्ष 2021-22 की अक्टूबर-जनवरी की अवधि के दौरान देश का चीनी उत्पादन साल भर पहले की समान अवधि के मुकाबले 5.64 प्रतिशत बढ़कर 1.87 करोड़ टन होने का अनुमान है। उद्योग निकाय इस्मा ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। चीनी मिलों ने पिछले विपणन वर्ष 2020-21 (अक्टूबर-सितंबर) की इसी अवधि में 1.77 करोड़ टन चीनी का उत्पादन किया था। भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के अनुसार, उत्तर प्रदेश (देश का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य) में चीनी उत्पादन इस विपणन वर्ष की अक्टूबर-जनवरी की अवधि के दौरान कम यानी 50.3 लाख टन रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 54.4 लाख टन रहा था।

हालांकि, देश के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन 63.8 लाख टन से बढ़कर 72.9 लाख टन हो गया। देश के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य, कर्नाटक में उक्त अवधि में चीनी उत्पादन 34.5 लाख टन से बढ़कर 38.7 लाख टन हो गया। चालू विपणन वर्ष में जनवरी तक गुजरात में चीनी का उत्पादन 5,75,000 टन और तमिलनाडु में 2,88,000 टन तक पहुंच गया। इस्मा ने एक बयान में कहा कि शेष राज्यों ने सामूहिक रूप से समीक्षाधीन अवधि में 16.4 लाख टन चीनी का उत्पादन किया।

● उद्योग निकाय ने चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान में चीनी उद्योग के लिए आवंटन बढ़ाकर 6,844 करोड़ रुपए करने के कदम का स्वागत किया है

उद्योग निकाय ने चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान में चीनी उद्योग के लिए आवंटन बढ़ाकर 6,844 करोड़ रुपए करने के कदम का स्वागत किया है। पहले यह 4,337 करोड़ रुपए था। इस्मा का कहना है कि यह गन्ने के भुगतान का निपटान करने की दिशा में सकारात्मक कदम है। इस्मा ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए बजट आवंटन में 300 करोड़ रुपए की वृद्धि (एथनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि के मकसद से चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने के लिए) एथनॉल सम्मिश्रण के लिए एथनॉल आपूर्ति को बढ़ावा देगी और देश के तेल आयात के मद में होने वाले खर्चे को कम करेगी।

प्रत्यक्ष कर संग्रह 12.50 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से अधिक रहने की उम्मीद : सीबीडीटी प्रमुख

भाषा। नई दिल्ली

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन जे बी महापात्र ने कहा है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष के अंत तक 12.50 लाख करोड़ रुपए के संशोधित लक्ष्य को पार कर सकता है। उन्होंने इसके अबतक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद भी जताई। उन्होंने कहा कि करदाताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया आसान बनाने तथा आंकड़ों के प्रसंस्करण को लेकर कर अधिकारियों की दक्षता में सुधार जैसे कई कारणों से कंपनी कर और व्यक्तिगत आयकर मद में कर संग्रह बढ़ने की उम्मीद है।

महापात्र ने बातचीत में कहा, एक फरवरी तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 10.38 लाख करोड़ रुपए है। यह बजटीय अनुमान से केवल 70,000 करोड़ रुपए कम है। इस समय यह आंकड़ा पिछले साल के कुल संग्रह के मुकाबले बेहतर है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष कर संग्रह अबतक 11.18 लाख करोड़ रुपए से ऊपर कभी नहीं गया है।सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, इस साल हम 12 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं...हमारा लक्ष्य 12.50 लाख करोड़ (संशोधित अनुमान) रुपए का है। और हमें न केवल इस लक्ष्य को हासिल करने बल्कि संभवत: इसे पार कर जाने का भरोसा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के समाप्त होने में अभी दो महीने है। ऐसे में लक्ष्य दायरे में जान पड़ रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 12.50 लाख करोड़ रुपए में से 6.35 लाख करोड़ रुपए कंपनी कर श्रेणी में जबकि 6.15 लाख करोड़ रुपए व्यक्तिगत आयकर खंड में आने का अनुमान है। महापात्र ने कहा कि इस बार कर विभाग बेहतर स्थिति में है। इसका कारण विभिन्न उपाय हैं, जो पिछले कुछ साल में करदाताओं और कर प्राधिकरण दोनों के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रणाली को दुरुस्त करने को लेकर किए गए हैं। उन्होंने कहा, हम लंबे समय तक ऐसी स्थिति में नहीं थे, जैसे आज हैं। इसका कारण हमने करदाताओं के लिए कर अनुपालन को आसान बनाया है। साथ ही हमें आयकर विभाग की आंकड़ा प्रसंस्करण क्षमता पर भरोसा है। सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि इसके अलावा कारोबार के संगठित रूप में आने, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), बाजार नियामक सेबी समेत विभिन्न एजेंसियों के बीच आंकड़ों को साझा करने से भी हमें मदद मिली है। इससे आंकड़े एकत्रित करने में मदद मिली। हम सभी अन्य एजेंसियों का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, कर अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों में इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े प्राप्त हुए हैं। अत: उन्हें कर चोरी करने वालों पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही करदाताओं के लिए स्वैच्छिक अनुपालन प्रक्रिया भी लाई गई है। महापात्र के अनुसार, 2018-19 में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.18 लाख करोड़ रुपए, 2019-20 में 10.28 लाख करोड़ रुपए और 2020-21 में यह 9.24 लाख करोड़ रुपए था।

देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां जनवरी के दौरान नरम पड़ीं

भाषा । नई दिल्ली

देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां जनवरी के महीने में नरम पड़ गईं। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ने के बीच नए कारोबार में काफी धीमी गति से वृद्धि हुई। बृहस्पतिवार को जारी एक मासिक सर्वे में यह कहा गया। मौसमी रूप से समायोजित भारत सेवा व्यापार गतिविधियां सूचकांक जनवरी में मासिक आधार पर घटकर 51.5 रहा, जो दिसंबर में 55.5 था। यह पिछले छह महीने में विस्तार की सबसे धीमी दर की ओर इशारा करता है। यह लगातार छठा महीना है जब सेवा क्षेत्र ने उत्पादन में विस्तार देखा। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) 50 से ऊपर गतिविधियों में तेजी को सूचित करता है जबकि 50 से नीचे गिरावट को बताता है। सर्वेक्षण में भाग लेने वालों के अनुसार, कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के तेजी से प्रसार से देश के कुछ हिस्सों में प्रतिबंध लगाए जाने के कारण मांग में कमी आई है। आईएचएस मार्किट की इकनॉमिक्स एसोसिएट निदेशक पॉलिएना डि लीमा ने कहा, महामारी के बढ़ने और प्रतिबंधों को फिर से लगाए जाने से सेवा क्षेत्र के विकास पर नकरात्मक प्रभाव पड़ा। नए कारोबार और उत्पादन दोनों ही मामूली दरों पर बढ़े जो छह महीने में सबसे कमजोर थे। इसके अलावा कंपनियों के बीच चिंता बढ़ी है और कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रतिबंधों को फिर से लागू करने और मुद्रास्फीति के दबाव से विकास को नुकसान होगा।

वित्त सचिव सोमनाथन ने कहा, क्रिप्टो करेंसी कभी भी वैध मुद्रा नहीं बनेगी

नई दिल्ली (भाषा)

वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने बृहस्पतिवार को क्रिप्टोकरेंसी की वैधता को लेकर चीजें साफ करते हुए कहा कि निजी डिजिटल मुद्रा कभी भी कानूनी मुद्रा नहीं बनेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह संसद में पेश 2022-23 के बजट में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों में लेन-देन पर होने वाले लाभ को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया। साथ ही एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने की भी घोषणा की। सोमनाथन ने बातचीत में कहा कि

जिस प्रकार सोना और हीरा मूल्यवान होने के बावजूद वैध मुद्रा नहीं है, निजी क्रिप्टोकरेंसी भी कभी वैध मुद्रा नहीं होंगी। उन्होंने कहा, क्रिप्टो कभी भी वैध मुद्रा नहीं होगी। कानून के हिसाब से वैध मुद्रा का मतलब है कि उसे कर्ज के निपटान में स्वीकार किया जाएगा। भारत किसी भी क्रिप्टो संपत्ति को वैध मुद्रा नहीं बनाएगा। केवल भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल रुपया ही देश में वैध मुद्रा होगा। दुनिया में केवल अल-सल्वाडोर ने ही पिछले साल सितंबर में बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। किसी भी अन्य देश में क्रिप्टो को वैध मुद्रा का दर्जा नहीं मिला है।देश में क्रिप्टो मुद्रा के लिए नियम बनाने को लेकर विचार-विमर्श जारी है। लेकिन अब तक कोई मसौदा जारी नहीं किया गया है। इस बीच, केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा अगले वित्त वर्ष से परिचालन में आएगी। यह पूछे जाने पर कि संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो संपत्ति के नियमन को लेकर विधेयक लाने की बात संसद के कामकाज में शामिल थी लेकिन मौजूदा बजट सत्र में ऐसा नहीं है, सोमनाथन ने कहा, यह महसूस किया गया कि क्रिप्टो पर कानून लाने से पहले इस पर व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है। इस विचार-विमर्श का मकसद इस बात पर गौर करना है कि क्या इसके लिए नियमन की जरूरत है। वित्त सचिव ने कहा, हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सरकार कुछ शुरू करती है लेकिन फिर प्रतिक्रिया होती है। सरकार उस प्रतिक्रिया को सुन रही है और उसके आधार अभी तक अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है...। इस बीच, चूंकि क्रिप्टो और अन्य डिजिटल संपत्तियों में लेन-देन लगातार बढ़ रहा था, अत: कर स्पष्टता की जरूरत थी।

पेज एक का शेष

चीन के...

और सैनिकों को शिक्षाने शहीद कब्रिस्तान में संगठित रूप से ले जाया गया जहां पार्टी के सदस्यों को नायकों के लिए कब्रों को साफ किया गया और शपथ लेने के लिए संगठित किया गया। जांच में मुख्य रूप से वहां के चीनी ब्लॉगर्स के साथ चर्चा, चीनी नागरिकों से प्राप्त जानकारी और मीडिया रिपोर्ट शामिल हैं जिन्हें चीनी अधिकारियों द्वारा हटा दिया गया है।

पांच फीसद...

ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, महामारी की स्थिति में सुधार हुआ है। कुछ ऐसे राज्य और जिले हैं जहां स्थिति चिंताजनक है लेकिन कुल मिलाकर संक्रमण फैलने की दर में कमी आई है जो अच्छी बात है। ऐसे 268 जिले हैं जहां संक्रमण की दर पांच प्रतिशत से कम है। स्पष्ट रूप से, यह जिले गैर-कोविड देखभाल की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और और अन्य आर्थिक गतिविधियों तथा स्कूलों को पुन: खोलने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय राज्य सरकारों, जिला प्रशासन को लेना है लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि हम अब भी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रिया के तहत स्कूल खुलें और चलें क्योंकि हम अब भी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं।

महामारी ढलान...

मामले लगातार गिर रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि हम कोविड मामलों में गिरावट देख रहे हैं। हम लहर और चरम जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मामले बढ़ रहे हैं। कोविड प्रबंधन रणनीतियों को अभी भी लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बीते 21 जनवरी से 3 फरवरी के बीच के दो हफ्तों में दैनिक कोविड के मामले 347254 से 50 प्रतिशत गिरकर 172433 हो गए हैं। इसी अवधि के दौरानए सकारात्मकता दर या प्रति 100 टेस्ट में संक्रमणों की संख्या 39 प्रतिशत गिरकर 17.94 प्रतिशत से 10.99 प्रतिशत हो गई है। हालाँकि 10 प्रतिशत से अधिक की सकारात्मकता दर वाले जिलों की संख्या एक सप्ताह पहले 400 से गिरकर अब 300 से कम हो गई है। केरल और मिजोरम में अभी भी सकारात्मकता दर और मामलों में वृद्धि हो रही है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि 44 वर्ष की औसत आयु के साथ तुलनात्मक रूप से युवा आबादी इस कोविड लहर में अधिक संक्रमित हुई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सहित 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड 19 मामलों और सकारात्मकता दर में गिरावट आ रही है। डेटा से पता चलता है कि 297 जिलों में अभी भी 10 प्रतिशत से अधिक की सकारात्मकता दर है जबकि 169 जिलों में सकारात्मकता दर 5 से 10 प्रतिशत के बीच है तथा 268 जिलों मेंए सकारात्मकता दर पांच प्रतिशत से कम है।

असदुद्दीन ओवैसी...

काफिले पर हुए हमले की समाजवादी पार्टी ने निंदा की है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र में किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं होगी।

पेगासस पैनल...

में प्रोफेसर नवीन कुमार चौधरी, प्रभारन और अश्विन गुमस्ते शामिल हैं। तकनीकी समिति ने मोबाइल फोन प्राप्त करने और डिजिटल कॉपी करने के लिए आईआईटी दिल्ली परिसर में एक कार्यालय खोला है।

हरियाणा में...

लोगों को मासिक वेतनादिहाड़ी पर नौकरी देने वाले कार्यालयों, विनिर्माण क्षेत्र आदि पर लागू होता है। उधर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक के एक कॉलेज प्रशासन पर हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों को प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर आरोप लगाया कि लड़कियों को शिक्षित करने का उसका नारा खोखला है क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। वहीं अब्दुल्ला ने योगी आदित्यनाथ, भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती और भोपाल से लोकसभा सदस्य प्रज्ञा ठाकुर की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें हिजाब पहने हुए मुस्लिम छात्राओं की भी एक तस्वीर है।

तमिलनाडु के...

खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के हितों के खिलाफ है। बयान में कहा गया है, इसलिए माननीय राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष को एक फरवरी 2022 को विस्तृत कारण बताते हुए सदन द्वारा दोबारा विचार करने के लिए यह विधेयक वापस कर दिया है। बयान के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2020) मामले में सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से इस मुद्दे की व्यापक जांच की है और नीट को बरकरार रखा है, क्योंकि यह गरीब छात्रों के आर्थिक शोषण को रोकता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। राज्यपाल का यह फैसला मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नवंबर में उनसे मुलाकात कर विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आगे बढ़ाने का आग्रह करने के महीनों बाद आया है। इसके अलावा स्टालिन की अध्यक्षता में तमिलनाडु में पिछले महीने हुई एक सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया गया था कि नीट के खिलाफ साझा कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। तमिलनाडु में नीट के विरोध को भावनात्मक समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि परीक्षा में कम अंक हासिल करने या फेल होने की आशंकाओं को लेकर राज्य में चिकित्सा

शिपिंग कॉरपोरेशन, बीईएमएल, बीपीसीएल का निजीकरण अगले वित्त वर्ष में, तीन आईपीओ भी लाने की तैयारी

भाषा। नई दिल्ली

● आम बजट में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 65 हजार करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य तय किया गया

सरकार अगले वित्त वर्ष में शिपिंग कॉरपोरेशन, बीईएमएल और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) की रणनीतिक बिक्री के अलावा ईसीजीसी सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तीन कंपनियों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ लाएगी। एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। आम बजट में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 65,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य तय किया गया है। यह आंकड़ा 2021-22 के लिए अनुमानित 1.75 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से काफी कम है, हालांकि सरकार ने संशोधित अनुमानों में 2021-22 के लक्ष्य को घटाकर 78,000 करोड़ रुपए कर दिया है।

निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि अगले साल के लक्ष्य को सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री, सीपीएसई को सूचीबद्ध करके और रणनीतिक बिक्री के जरिए पूरा किया जाएगा। पांडेय ने बताया, हमें पवन हंस के लिए कई वित्तीय बोलियां मिली हैं, हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। शिपिंग कॉरपोरेशन, बीईएमएल और बीपीसीएल की वित्तीय बोली की प्रक्रिया चल रही है। एचएलएल लाइफकेयर और पीडीआईएल ईओआई चरण में हैं। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष में हम ईसीजीसी, वैपकोस और नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन के आईपीओ भी लाएंगे। कुछ अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री भी की जाएगी, लेकिन इसकी गुंजाइश कम हो सकती है। यह पूछे जाने पर कि क्या पवन हंस की बिक्री मार्च के अंत तक पूरी हो जाएगी, उन्होंने कहा, हमें देखना होगा कि क्या हम काम पूरा कर सकते हैं। हमें अभी बोलियां खोलनी हैं और फिर मंजूरी हासिल करने के लिए कुछ समय की जरूरत होगी।

सचिव ने कहा कि शिपिंग कॉरपोरेशन और बीईएमएल की मुख्य और गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के विघटन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद उसकी रणनीतिक बिक्री के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। बीपीसीएल के निजीकरण के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, हम बोलीदाताओं के साथ फंस गए हैं और इसे तेजी से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे बोली लगाने के लिए तैयार हों। सरकार बीपीसीएल में 52.98 प्रतिशत, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 63.75 प्रतिशत, बीईएमएल में 26 फीसदी और पवन हंस में 51 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है।

केंद्र ने ओडिशा में रेलवे विकास के लिए 9,734 करोड़ रुपए आवंटित किए

भाषा। भुवनेश्वर

आम बजट 2022-23 में ओडिशा को रेलवे के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए लगभग 9,734 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है, जो इस मद में अबतक का सबसे अधिक बजटीय प्रावधान है और राज्य की मांग से अधिक है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। हालांकि, रेलवे ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के चलते लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर आवंटन का आंकड़ा आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया, लेकिन अधिकारी ने कहा कि ओडिशा के लिए इस साल का बजट आवंटन पिछले साल के 6,995.58 करोड़ रुपए के आवंटन से 2,738.5 करोड़ रुपए अधिक है। इसमें राज्य का हिस्सा और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) जैसे ऋण शामिल हैं। राज्य सरकार ने ओडिशा में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय बजट से 7,600 करोड़ रुपए मांगे थे।

यूक्रेन तनाव : बाइडन का अधिक सैनिक यूरोप भेजने का फैसला

● राजनयिक समाधान के प्रयास जारी

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पोलैंड और जर्मनी में 2,000 अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया है और जर्मनी से रोमानिया में 1,000 और सैनिक स्थानांतरित किए जा रहे हैं। पेंटागन ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। ऐसा कर बाइडन यूक्रेन पर रूस के सैन्य आक्रमण की आशंका के बीच नाटो के पूर्वी हिस्से पर अपने सहयोगियों के प्रति अमेरिकी कटिबद्धता प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं।

रूस ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए इस तैनाती को निराधार और विनाशकारी बताया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ फोन पर बातचीत भी की। हालांकि, दोनों देशों की सरकारों की ओर से जारी बयानों से प्रतीत होता है कि मामले को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। पुतिन ने कहा कि कि रूस की सुरक्षा चिंताओं पर पश्चिम कोई ध्यान नहीं दे रहा, वहीं जॉनसन ने यूक्रेन की सीमा पर रूस की शत्रुतापूर्ण गतिविधि के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की और वहां तैनात रूस के 100,000 सैनिकों का जिक्र भी किया।

बाइडन प्रशासन अब संकट के राजनयिक समाधान खोजने के प्रयासों को कम किए बिना अमेरिकी प्रतिबद्धता दर्शाने की कोशिश कर रहा है। बाइडन प्रशासन ने हालांकि, नाटो के पूर्वी हिस्से में बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में सैनिक नहीं भेजे हैं। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि शीघ्र ही की जाने वाली अमेरिकी सैन्यबलों की तैनाती का मकसद अमेरिका और संबद्ध सहयोगियों का मनोबल बढ़ाना है। उन्होंने कहा, यह स्थाई कार्वाई नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रूस लगातार यूक्रेन सीमा के पास सैनिकों की तैनाती कर रहा है, यहां तक की पिछले 24 में भी उसने ऐसा किया है, जबकि अमेरिका उससे लगातार स्थिति नहीं बिगड़ने देने की अपील कर रहा है। इस बीच, रूस के उपविदेश मंत्री एलेक्जेंडर ग्रुशको ने संवाद समिति इंटरफैक्स से कहा, बेबुनियाद विध्वंसक कदमों से सैन्य तनाव बढ़ेगा ही और राजनीतिक निर्णयों के लिए गुजाइंश कम होगी।

पुतिन ने शी से वार्ता से पहले ओलंपिक का बहिष्कार करने के लिए अमेरिका की आलोचना की

बीजिंग। यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों के साथ बढ़े तनाव के बीच चीन के दौरे पर आ रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका समेत कुछ देशों द्वारा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की निंदा की और कहा कि अपने स्वार्थ के लिए ओलंपिक चार्टर के खिलाफ खेलों का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है।

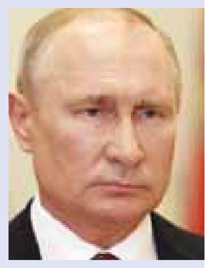

चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग शुक्रवार को 17 दिवसीय बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का उद्घाटन करेंगे। पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और 30 राष्ट्राध्यक्ष तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले हैं। हालांकि, चीन के अशांत शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को उजागर करने के लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ (ईयू) और कई अन्य देशों द्वारा राजनयिक रूप से इसका बहिष्कार किया जा रहा है। यात्रा से पहले बृहस्पतिवार को सरकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी द्वारा जारी अपने लेख में पुतिन ने कहा, दुख की बात है कि कई देशों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए खेलों का राजनीतिकरण करने के प्रयास हाल में तेज हो गए हैं। पुतिन ने लिखा है, खेलों की शक्ति और विशिष्टता यह है कि वे लोगों को एक साथ लाते हैं, जीत का मौका देते हैं और राष्ट्रीय गौरव के साथ-साथ निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और प्रतिस्पर्धा का आनंद मुहैया कराते हैं। इन दृष्टिकोणों को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक आयोजन में भाग लेने वाले अधिकतर देशों द्वारा साझा किया जाता है। चीनी अधिकारियों ने कहा है कि बीजिंग पुतिन की यात्रा को बहुत महत्व देता है, क्योंकि इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य पश्चिमी देशों के साथ बढ़ती प्रतिकूल परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में एकजुटता और रणनीतिक संबंधों को फिर से लागू करना है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने कहा कि चीन और रूस की हमेशा से प्रगाढ़ दोस्ती आकस्मिक रूप से नहीं पनप रही है, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों के महत्व तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों नेताओं के सामान्य दृष्टिकोण से यह आगे बढ़ती गई है। पुतिन का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका और नाटो की चेतावनी के कारण तनाव काफी बढ़ गया है।

सीरिया में अमेरिकी हमले में आईएस का प्रमुख मारा गया : बाइडन

अतमह (सीरिया)। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि सीरिया में देर रात अमेरिकी विशेष बलों के हमले में इस्लामिक स्टेट समूह का प्रमुख मारा गया। हमले में अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल-कुरैशी को निशाना बनाया गया, जिसने अबू बकर अल बगदादी के इसी इलाके में एक अमेरिकी हमले में मारे जाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को आतंकी संगठन की बागडोर संभाली थी। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी सैनिकों के पहुंचने पर जिस तरह बगदादी ने एक बम विस्फोट कर खुद को अपने परिवार के सदस्यों को मार डाला था उसी तरह अल कुरैशी की मौत हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अमेरिकी विशेष बल सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले एक इलाके में उतरे और एक मकान पर धावा बोला।

सीरिया के इदलिब प्रांत में सीरिया के गांव अतमेह में अमेरिकी सेना द्वारा एक ऑपरेशन के बाद नष्ट हुए घर का निरीक्षण करते लोग, अमेरिकी विशेष अभियान बलों ने उत्तर-पश्चिमी सीरिया में रात भर बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी छापेमारी की। पेंटागन ने गुरुवार को कहा कि वह एक सफल मिशन था। निवासियों और कार्यकर्ताओं ने हमले में नागरिकों सहित कई मौतों की सूचना दी

कांगो की राजधानी में बिजली के हाई-वोल्टेज तार की चपेट में आने से 26 लोगों की मौत

भाषा। किंशासा

कांगो की राजधानी किंशासा में बृहस्पतिवार को हाई-वोल्टेज बिजली की तार की चपेट में आने से 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर स्थानीय बाजार में काम करने वाली महिलाएं हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री समा लुकोंडे ने कहा कि खराब मौसम की वजह से मातादी किबाला बाजार में हाई-वोल्टेज तार गिरने के कारण करंट लगने से कई लोगों मौत हो गई।अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में 24 महिलाएं हैं। एक स्थानीय विक्रेता चार्लेन ट्वा ने कहा, हम लोग एक गिरजाघर में एकत्रित थे और बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। अचानक, हमने आग की लपटें देखीं और हम चिल्लाए भगवान, हमारी रक्षा करो। जब हम बाहर निकले तो हमने वहां सामान बेचने वाले सभी लोगों को बेजान जमीन पर पड़ा देखा। सरकार के प्रवक्ता पैट्रिक मुयाया ने कहा कि बाजार को वहां से हटाने का काम शुरू हो चुका है।

क्विक न्यूज

भारतीय-अमेरिकी समूह का पाकिस्तान के दूत के रूप में मसूद खान की नियुक्ति खारिज करने का आग्रह

वाशिंगटन। प्रवासी भारतीयों के एक शीर्ष समूह ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से देश में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में मसूद खान की नियुक्ति को खारिज करने का आग्रह करते हुए आरोप लगाया कि खान आतंकवादी संगठनों के हमदर्द और समर्थक हैं। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (एफआईआईडीएस) ने बुधवार को एक बयान में बाइडन से आग्रह किया कि वह जिहादी-आतंकवादी समर्थक मसूद खान की अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत के रूप में नियुक्ति को खारिज कर दें। एफआईआईडीएस ने कहा, हम विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और विदेश मामलों पर सीनेट और प्रतिनिधि सभा की समितियों के सदस्यों से भी इसका समर्थन करने का अनुरोध करते हैं। समूह ने कहा, मसूद खान ने कई बार जिहादी-आतंकवादियों के लिए नरम रुख दिखाया है, जिसमें आफिया सिद्दीकी भी शामिल है, जिसे लेडी अल-कायदा के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी कानून के तहत घोषित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत-उल-मुजाहिदीन (एचयूएम) और जमात-ए-इस्लामी आदि के प्रति उनका समर्थन न केवल अमेरिकी हितों के लिए बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी नुकसानदायक है। एफआईआईडीएस भारत-अमेरिका नीति पर अध्ययन और जागरूकता के लिए अमेरिका-स्थित एक संस्थान है। एफआईआईडीएस ने कहा, अमेरिका में खान की राजनयिक भूमिका आतंकवादी संगठनों के लिए अमेरिकी संस्थानों तक पहुंच का मार्ग खोल सकती है। इसके अलावा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के प्रमुख के रूप में उनकी पूर्व में सक्रिय भूमिका अपने रणनीतिक साझेदार भारत के साथ अमेरिकी संबंधों को जटिल बनाएगी। तालिबान के प्रति उनके समर्थन से अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

बांग्लादेश में ओमीक्रोन के प्रसार के बीच स्कूल बंद, लेकिन मेलों का आयोजन

ढाका। बांग्लादेश मे महामारी के चलते 543 दिन तक बंद रहने के बाद सितंबर मे जब स्कूल खुले तो राजधानी ढाका स्थित एक अग्रणी निजी स्कूल मे शिक्षक तथा अकादमिक पर्यवेक्षक रफ्सा हसीना अफरोज ने राहत की सांस ली और उन्हें लगा कि अब ऑनलाइन कक्षाएं नही लेनी पड़ेगी, लेकिन यह राहत बहुत छोटी थी। हाल मे कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के चलते संक्रमण के मामलो मे हुई तेज वृद्धि के बाद अधिकारियो ने एक बार फिर स्कूल बंद करने का निर्देश दे दिया। अफरोज कहती है, स्कूल मे पहले जैसा माहौल तो नही था, लेकिन हम वापस लौटकर खुश थे। पूरी अवधि के दौरान मै अपने छात्रों और सहकर्मियों को याद करती रही। नई वास्तविकता से तालमेल बिठाना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है। अफरोज की तरह कई और शिक्षक तथा छात्र निराश है। वह कहती है, हम दोबारा कैद हो गए है। हमारे छात्र स्कूल नही आ पा रहे। ओमीक्रोन फैल रहा है, जो इसका वैध कारण है। हम फिर से ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे है। यह संतोषजनक नही है। छात्रों के बिना स्कूल बेरौनक है।

उत्तरी कैलीफोर्निया में बस में गोलीबारी, एक की मौत, कई अन्य घायल

ओरोविल (कैलीफोर्निया)। अमेरिका के उत्तरी कैलीफोर्निया मे एक ग्रेहाउंड बस मे गोलीबारी मे एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए एवं बाद मे हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बुधवार रात को यह जानकारी दी। बूट काउंट शेरीफ के कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार सैक्रोमेंटो के उत्तर मे छोटे से शहर ओरोविल मे पुलिस को रात साढ़े सात बजे के बाद सूचना मिली की कि एक किराना स्टोर के बाहर बस मे कोई गोलीबारी कर रही है। शेरीफ कार्यालय ने बताया कि उसके कर्मियो और पुलिस अधिकारियो को मौके पर कई लोगो को घायल एवं एक व्यक्ति को मृत पाया। हालांकि इन अधिकारियो के पहुंचने से पहले हमलावर मौके से भाग गया था लेकिन उन्होने वालमार्ट के अंदर संदिग्ध हमलावर का पता लगा लिया एवं हिरासत मे ले लिया।

बाफ्टा -22 में ड्यून और द पावर ऑफ द डॉग को सबसे ज्यादा नामांकन

लंदन। डेनिस विल्लेनुव की साई-फाई फिल्म ड्यून को बाफ्टा 2022 मे सबसे ज्यादा श्रेणियो मे नामांकित किया गया है। नामांकन को लेकर दूसरे नंबर पर जेन चैम्पियन की फिल्म द पावर ऑफ द डॉग है। ब्रिटिश टेलीविजन की हस्तियो ए. जे. ओदुदु और टॉम एलेन ने नामांकनो की घोषणा की। लेखक फ्रैंक हर्बर्ट के 1965 के उपन्यास पर आधारित ड्यून को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, एडॉप्टेड पटकथा, संगीत और आठ अन्य तकनीकी श्रेणियो सहित कुल 11 श्रेणियो मे नामांकन हासिल हुआ है। चैम्पियन की पावर ऑफ द डॉग को आठ श्रेणियो मे नामांकन हासिल हुआ है। मुख्य किरदार निभाने वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैश को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी मे, जबकि उनके सह कलाकारो जेसी और कोडी -मैक्फी को सर्वश्रेष्ठ सह-कलाकारो की श्रेणी मे नामांकन हासिल हुआ है।

अमेरिका भाजपा नीत सरकार के फैसलों पर राहुल गांधी की टिप्पणी का समर्थन नहीं करता : विदेश विभाग

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि अमेरिका कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस टिप्पणी का समर्थन नहीं करता जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार की विदेश नीति के फैसलों ने चीन और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक साथ ला दिया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बुधवार को लोकसभा में गांधी की टिप्पणियों से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा, मैं इसे पाकिस्तान और चीन के लोगों पर उनके संबंधों पर बात करने के लिए छोड़ना चाहूंगा। मैं निश्चित रूप से उन टिप्पणियों का समर्थन नहीं करूंगा। एक अन्य सवाल के जवाब में प्राइस ने कहा कि देशों को अमेरिका और चीन के बीच चयन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, हमने हमेशा यह बात रखी है कि दुनिया के किसी भी देश के लिए अमेरिका और चीन के बीच चयन करने की आवश्यकता नहीं है। जब अमेरिका के साथ संबंधों की बात आती है तो हमारा इरादा देशों को विकल्प प्रदान करने का है। हमें लगता है कि अमेरिका के साथ साझेदारी से कई लाभ मिलते हैं जो देशों को आमतौर पर तब नहीं मिलते जब यह अलग तरह की साझेदारी होती है। चीन ने जिस तरह के रिश्तों की तलाश की है, जैसा वह दुनिया भर में करना चाहता है, इस तरह साझेदारी गलत शब्द हो सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए बृहस्पतिवार को चीन के लिए रवाना हुए।

अमेरिका के खुफिया उपग्रह का कैलिफोर्निया से प्रक्षेपण

भाषा। लॉस एंजिलिस (अमेरिका)

अमेरिका के राष्ट्रीय टोही कार्यालय (एनआरओ) के लिए एक विशेष उपग्रह को बृहस्पतिवार को कैलिफोर्निया से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। एनआरओएल-87 उपग्रह को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट पर प्रक्षेपित किया गया।

प्रक्षेपण का वेबकास्ट तब तक किया गया, जब तक कि पहले चरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो गई। फाल्कन के पहले चरण का हिस्सा लॉस एंजिलिस के उत्तर-पश्चिम में समुद्र तट पर वापस आ गया, ताकि भविष्य में एनआरओ के अभियान में इसका पुन: उपयोग किया जा सके। एनआरओ ने एनआरओएल-87 उपग्रह को केवल राष्ट्रीय सुरक्षा पेलोड के रूप में वर्णित किया। 2019 में वायु सेना ने ऐसे तीन प्रक्षेपण के लिए स्पेसएक्स को 29.7 करोड़ अमेरीकी डॉलर का संयुक्त भुगतान किया था, जिसके तहत ही यह प्रक्षेपण कियाा गया। एनआरओ अमेरिकी उपग्रहों के विकास, निर्माण, प्रक्षेपण और रखरखाव के लिए प्रभारी सरकारी एजेंसी है, जो वरिष्ठ नीति निर्माताओं, खुफिया समुदाय और रक्षा विभाग को खुफिया डेटा प्रदान करती है। कार्यालय ने लगभग एक दर्जन पेलोड को कक्षा

में स्थापित करने के लिए इस वर्ष आधा दर्जन से अधिक प्रक्षेपण करने की योजना बनाई है।

बड़े पैमाने पर कोविड का पता लगाने के लिए त्वरित ब्रेथएनालाइजर जांच विकसित

सिंगापुर। वैज्ञानिकों ने एक नई ब्रेथएनालाइजर जांच विकसित की है, जिसमें स्वाब का नमूना लिए बगैर ही कोरोना वायरस के संक्रमण का सटीक पता लगाया जा सकता है। जिन लोगों में लक्षण नहीं दिख रहे हैं उनमें भी संक्रमण का पता महज पांच मिनट में लगाया जा सकता है। पत्रिका एसीएस नैनो में इस जांच के बारे में कहा गया है कि इससे सम्मेलन या शादी-विवाह आदि भीड़ वाले कार्यक्रमों में आसानी से लोगों के संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। फिलहाल कोविड की सटीक जांच के लिए आरटी-पीसीआर तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसमें नाक और मुंह से लिए गए स्वाब के नमूने का इस्तेमाल होता है।

सार्वजनिक सूचना

यह सार्वजनिक सूचना मेरी मुवक्किल **श्री हरीश कोहली पुत्र** स्व. श्री केशव नंद कोहली **निवासी पी-32, तीसरी मंजिल, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली -110008 एवं श्रीमती सोनिया कोहली पत्नी श्री हरीश कोहली की ओर से जारी की जा रही है।** एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल की बेटी **अनुयक्षा वर्धन कोहली** ने उनकी इच्छा और स्वीकृति के खिलाफ जाकर **श्री वरुण देहर** के साथ शादी की है। मेरे मुवक्किल की बेटी उनके साथ दुर्व्यवहार और परेशान कर रही है और मेरे मुवक्किलों ने दोनों के साथ अपने सभी संबंध विच्छेद कर दोनों को बेदखल कर दिया है। मेरे मुवक्किल की बेटी अनुयक्षा वर्धन कोहली और उसके पति श्री वरुण देहर का मेरी किसी भी चल और अचल संपति पर और साथ ही मेसर्स सिमटेक कंप्यूटर्स के नाम से चल रहे मेरे व्यवसाय में भी कोई दावा नहीं है। जे-39, जी. एफ., वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008. भविष्य में, इन दोनों के साथ व्यवहार करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर ऐसा करेगा। मेरे मुवक्किल उनके किसी भी कृत्य और कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। **क्षितिज महिपाल (एडवोकेट)**
Enrl. No. D-1168/2004, मोबाइल : 9999994372
1304 Lawyers Chambers Rohini Court, New Delhi-85

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that Mr. Hemant Verma (hereinafter referred to as the said Mortgagors/Borrowers) is purchasing the Second Floor (Without Roof Rights) built on Property Bearing No. A-2/1, Built on Old Plot No. 29 & 31, area measuring 50 Sq. Yds., i.e., 41.80 Sq. Mtrs., Out of Khasra No. 730/77/58, Situated at Village Sikdarpur, in the Abadi of West Jyoti Nagar, Delhi-110094 from Sh. Gaurav Chauhan who became owner of the said floor vide Relinquishment Deed dated 30.11.2021, Sub- Registrar- IV A Shahdara New Delhi, as Doc No. 7580, Book No. I, Vol No. 3882, Page No. 14-21 on 30.11.2021 executed by Smt. Sushila Chauhan & Smt. Nancy Chauhan and Now, Mr. Hemant Verma has agreed to create mortgage in respect of the said property in favour of our clients **IDFC FIRST Bank Limited.** Further, if any person, body, individual, institution having any claim, title, interest and/or objection in respect of or against or relating to or touching upon said property or part of the property by way of sale, exchange, lease, lien, mortgage, charge, encumbrance, gift, trust, easement, maintenance, inheritance, testamentary deposition or otherwise or having in their custody any title, documents pertaining the said property shall communicate the same to the undersigned at below mentioned address within 10 days from the publication of this notice with documentary evidence in support thereof, failing which all the claim, of such person shall be considered to have been waived and or abandoned. Any objections raised after the completion of the 10 days shall not be binding upon the said property or my Client & in case anyone has any objection, the same may be raised within **10 days** of this publication to **Mr. Muneesh Dhawan/Mr. Sudhir Jain (Advocates)**, Law Veritas, Unit no 907, 9th Floor, GD-ITL Tower, (B-08), Netaji Subhash Place, Delhi-110034 or contact at (M). 9066707172/9818228636

Public Notice

To be known to all that I **Sh. Ashok Kumar Arora** S/o Late. Sh. Harbans Lal Arora, **R/o-Flat.No-243, 2nd Floor,SFS Flat,Block-B,Pocket-5, Sector-8,** Rohini, New Delhi-85 has applied for conversion of the aforesaid flat from **leasehold to freehold** vide application **DDAHCA2149193** dt **28/10/2021** in DDA. The original documents ie. **5th & Final Demand Letter** of the above flat have been lost. An FIR to this effect has been lodged in PS Crime branch Delhi. Any person claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/ contact with above named person at above Mobile No. **9837183252** within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objections with respect to this property can personally inform or write to Dy. Director (LAB) Housing, 3rd floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

PUBLIC NOTICE

My client, Sh. Sunil Kumar S/o Late Sh. Jai Pal Verma (60 SQ. YADS) And Sh. Sulabh S/o Sunil Kumar (27 SQ. YADS) Both R/o 28A/1/5, Street No. 2, East Azad Nagar, Krishna Nagar H.O. East Delhi-110051 is the Registered owner of property bearing address - 28A/1/5, PLOT NO. 63-A, Khasra No. 261, East Azad Nagar Vill. Ghondli, Illaqa Shahdara, Delhi-110051. vide Registered Gift deed dated 07.08.2002 Doc. No. 4494 And Registered Will dated 07.08.2002 Doc. No. 6856. Any person/bank/financial institution having any claim/right, lien any objection whatsoever in regard to above property, should notified to the undersigned/Adv. Vishal Mehan, E-713, Karkardooma Court, Delhi-110092 along with documentary evidence under address through registered A/D within 15 days from the date of publication of this notice failing which any claim, lien or objection shall be deemed to have been waived.

Vishal Mehan (Advocate)
Ch. No. E-713, Karkardooma Court,
Delhi-110092

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री सत्यकेतु सौरव पुत्र स्वर्गीय श्री परंजय कुमार और श्रीमती सुमन पत्नी स्वर्गीय श्री परंजय कुमार दोनों निवासी एम1-6/24, रोड नंबर 11, राजेंद्र नगर, विंध्य कला मंदिर, संपतचक, पटना, बिहार - 800016 ने दिनांक 15.11.21 को श्रीमती अंजू गुप्ता पत्नी स्वर्गीय श्री संदीप गुप्ता निवासी हाउस नंबर 8, तीसरी मंजिल, चित्रा विहार, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली -110092 के साथ बेचने के लिए एक समझौता किया है जो मालिक है फ्लैट यूनिट नंबर जे/सीएच-504, 5वीं मंजिल पर, "आदित्य सेलिब्रिटी होम्स" के नाम से जाना जाने वाला परिसर, प्लॉट नंबर जीएच-01/बी, सेक्टर-76 पर निर्मित, जिसका सुपर एरिया 1445 वर्ग फुट व 3-बीएचके है नोएडा, जिला गौतम बौद्ध नगर, उत्तर प्रदेश को आवंटित पार्किंग स्थान के साथ इसे खरीदने के लिए और उसके आंशिक भुगतान को बिक्री के प्रतिफल के लिए अग्रिम कर दिया है। इसलिए आम जनता को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि उक्त संपत्ति की खरीद के संबंध में किसी भी समझौते में प्रवेश करने से बचना चाहिए क्योंकि मेरे मुवक्किल का इस पर पहला अधिकार होगा। ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को जोखिम और परिणामों के संबंध में अपनी लागत पर ऐसा करने वाला माना जाएगा।

विवेक अग्रवाल (अधिवक्ता)
ई-10, एलजीएफ, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-24

पाकिस्तान में सुरक्षा चौकियों पर हमला

● 15 आतंकवादी ढेर चार सैनिकों की मौत

भाषा। कराची (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के अशांत दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में हथियारों से लैस हमलावरों ने सुरक्षा बलों के दो शिविरों पर हमला कर दिया, जिसके बाद भीषण गोलीबारी में कम से कम 15 आतंकवादियों को मार गिराया गया और चार सैनिकों की भी मौत हुई। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ इसे बड़ी सफलता बताया है। प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने बुधवार को पंजगुर और नौशकी जिलों में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। पंजगुर में, हमलावरों ने दो स्थानों से सुरक्षा बलों के शिविर में प्रवेश करने की कोशिश की, जबकि नौशकी में उन्होंने फ्रंटियर कोर (एफसी) पोस्ट में घुसने का प्रयास किया था, जिसका माकूल जवाब दिया गया। गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने एक वीडियो संदेश में कहा कि नौशकी में नौ आतंकवादी और चार सैनिक मारे गए जबकि पंजगुर में छह आतंकवादी मारे गए। उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता करार देते हुए कहा, पाकिस्तानी सेना ने दोनों जगहों से आतंकियों को खदेड़ दिया। पंजगुर में सेना ने चार से पांच लोगों को घेर लिया है और उन्हें मात दी जाएगी। प्रधानमंत्री इमरान खान ने बलूचिस्तान में शिविरों पर आतंकी हमलों को नाकाम करने के लिए बृहस्पतिवार को ट्विटर पर सुरक्षा बलों को बधाई दी। इससे पहले, सेना की मीडिया इकाई इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने एक बयान में कहा, दोनों हमलों का माकूल जवाब दिया गया..। फ्रंटियर कोर के एक प्रवक्ता ने पंजगुर और नौशकी स्थित शिविरों के पास दो विस्फोट होने की पुष्टि की थी, जिसके बाद भीषण गोलीबारी शुरू हुई। बीएलए ने एक बयान जारी कर इन हमलों की जिम्मेदारी ली। अलगाववादी संगठन ने हाल में सुरक्षा बलों और प्रतिष्ठानों पर हमले तेज किए हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमा में हिंसा खत्म करने का आह्वान किया

भाषा। संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने बृहस्पतिवार को म्यांमा में सैन्य तख्तापलट के एक साल पूरे होने पर देश में जारी हिंसा को तत्काल खत्म करने का और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति समर्थन दोहराते हुए आंग सान सू ची सहित हिरासत में लिए गए सभी नेताओं की रिहाई का आह्वान किया। म्यांमा की सेना ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई, सू ची के नेतृत्व वाली सरकार को एक फरवरी 2021 को अपदस्थ कर दिया था। सुरक्षा परिषद ने 15 सदस्य देशों के अनुमोदन वाले बयान में म्यांमा में सैन्य शासन द्वारा एक साल पहले लगाए गए आपातकाल पर और कोविड महामारी के चलते महिलाओं, बच्चों व अन्य संवेदनशील समूहों को मानवीय सहायता की जरूरत में हुए नाटकीय इजाफे पर गंभीर चिंता जताई। म्यांमा में मंगलवार को सैन्य तख्तापलट के एक साल पूरे होने पर देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन, हड़ताल और हिंसा हुई थी। अधिकारियों के कथित समर्थन से सेना के पक्ष में भी कई प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। म्यांमा में सैन्य तख्तापलट के विरोध में हुए प्रदर्शनों में अब तक लगभग 1,500 नागरिक मारे जा चुके हैं। हालांकि, सैन्य शासन देशभर में जारी विरोध-प्रदर्शनों पर काबू पाने में नाकाम रहा है।

यूएई ने शत्रुओं के तीन ड्रोन गिराए

● हालिया हफ्तों में देश पर यह चौथा हमला

भाषा। दुबई

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने बुधवार देर रात देश की ओर दागे गए कई ड्रोन को बीच में ही रोक कर नष्ट कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात की सेना ने बताया कि हाल के हफ्तों में हुआ यह चौथा हमला है। सेना ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ड्रोन किसने लक्षित किए थे, लेकिन हालिया घटनाओं को देखते हुए संदेह यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों पर किया जा रहा है। हूती विद्रोहियों ने हाल में यूएई पर हुए कई ड्रोन और मिसाइल हमलों की जिम्मेदारी ली है। अमीरात रक्षा मंत्रालय ने बुधवार आधी रात को ट्विटर पर एक संक्षिप्त बयान में कहा कि उसने तीन शत्रु ड्रोन नष्ट कर दिए हैं, जिन्होंने देर रात संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया था। मंत्रालय ने बिना विस्तृत जानकारी दिए कहा कि ड्रोन को आबादी वाले क्षेत्र से दूर रोका गया। व्रिदोहियों के 2015 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद से ही हूती सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन से मुकाबला कर रहा है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात शामिल भी है। गौरतलब है कि यमन के हूती विद्राहियों ने सबसे पहले पिछले महीने अमीरात पर ड्रोन और मिसाइल

हमले किए थे। अमेरिका और अमीरात बलों ने संयुक्त रूप से पिछले दो हवाई हमलों को रोक था। इनमें से एक हमला इज़राइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग के खाड़ी अरब देश की एतिहासिक यात्रा के दौरान किया गया था। वहीं, अबू धाबी पर पिछले महीने हूती विद्राहियों द्वारा किए गए हमले में भारत और पाकिस्तान के तीन कर्मचारियों की मौत हो गई थी और छह अन्य घायल हुए थे। हूती व्रिदोहियों की ओर से बृहस्पतिवार को किए गए ड्रोन हमले को लेकर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हालांकि, विद्रोही समूह के मीडिया कार्यालय ने ट्रू प्रॉमिस ब्रिगेड नामक एक समूह का एक पोस्ट साझा किया, जिसमें बिना सबूत के दावा किया गया था कि उसने क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के हस्तक्षेप के जवाब में चार ड्रोन भेजे हैं। यूएई का कहना है कि वह किसी भी तरह के खतरे से निपटने को तैयार है और देश को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

पाक में हिंदू कारोबारी की जमीन विवाद मामले में सिंध में गोली मार कर हत्या

कराची। पाकिस्तान में एक हिंदू कारोबारी की जमीन विवाद को लेकर सिंध प्रांत में दहार समुदाय के कुछ लोगों ने गोली मार कर कथित तौर पर हत्या कर दी। मीडिया की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। ट्रिब्यून ने अपनी खबर में बताया कि कारोबारी सतन लाल की घोटकी जिले में सोमवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की इस घटना के बाद जिले के कई कस्बों में विरोध प्रदर्शन हुए। लाल की हत्या के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध किया। इन धरना प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने लाल की हत्या के आरोपी बचल दहार और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया।

सार्वजनिक सूचना : आईडी कार्ड खोने के संबंध में

ICICI Bank | शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली-110085

समस्त जन साधारण को सूचना दी जाती है कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा जारी श्री मन्नू शर्मा का आईडी कार्ड नंबर 2137414, दिनांक 02 फरवरी, 2022 को कहीं खो गया/गुम हो गया है। किसी भी व्यक्ति, जिसको उक्त आईडी कार्ड मिले, से उक्त आईडी कार्ड मैनेजर डेट सर्विसेज ऐंड एम्प ; मैनेजमेंट ग्रुप, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एसडी टावर, रोहिणी, सेक्टर-8, दिल्ली-84 को लौटाने का अनुरोध किया जाता है।

अतएव, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के सभी ग्राहकों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे उक्त आईडी कार्ड नंबर 2137414 धारक किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को कोई भुगतान नही करें।

कृपया आगे सूचित हों कि उक्त आईडी कार्ड धारक किसी भी व्यक्ति को कोई भुगतान करने वाला व्यक्ति ऐसा अपनी स्वयं की लागत, जोखिम और खतरे पर ऐसा करेगा तथा आईसीआईसीआई बैंक किसी भी भुगतान के लिए बाध्य नहीं होगा तथा/अथवा जिम्मेदार नहीं होगा।

तिथि:04फरवरी,2020
स्थान : दिल्ली
हस्ता./-
वास्ते आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

प्रसव कक्ष में हिंसा

स्वास्थ्यरक्षा संबंधी मुद्दों एवं महिलाओं के सामने आने वाली दैनिक जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डाल रहीं हैं गुरप्रिया सिंह।

पटना की एक 29 वर्षीय महिला रामरती के लिए अपने पहले बच्चे की संस्थागत डिलीवरी का अपना अनुभव बताना काफी दर्दनाक था। शादी के दो महीने बाद वह गर्भवती हो गई। उसने अपनी अच्छी देखभाल की, और सभी प्रसव पूर्व दवाएं और परीक्षण समय पर लिए। लेकिन रामरती को अस्पताल में बिताई चार रातें अच्छी तरह याद हैं। ''चार दिन तक मैं दर्द से कराहती रही। नर्स कभी-कभी गाली-गलौज या अभद्र टिप्पणी करती थी, वह कहती थी, 'जब आप अपने पति के साथ अंतरंग हो रही थीं, तो आपको दर्द नहीं हुआ, आप यहां आ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं।' वे कभी-कभी जाति बना लेते थे। /धर्म आधारित टिप्पणी, या हमें ऑपरेशन के लिए पैसे देने के लिए कहें। डॉक्टर और इंटर्न ने एक उंगली परीक्षण किया, मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं प्रसव के लिए नहीं बल्कि उनके लिए मेरे शरीर से निरीक्षण और सीखने के लिए हूं'', रामरती ने समझाया।

नई दिल्ली स्थित युवा-नेतृत्व और युवाओं द्वारा संचालित संगठन वाईपी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में उंगली के परीक्षण के समान अनुभव को नोट किया गया है, जो एक युवा व्यक्ति ने लखनऊ के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मिस्ट्री ऑडिट करते समय अनुभव किया था। महिलाओं द्वारा ऐसे कई उदाहरण बताए गए हैं, जहां गर्भावस्था का पता लगाने के विकल्प नहीं दिए गए हैं, और चिकित्सक बिना सूचित सहमति के नियमित रूप से गर्भ का आकलन करने के लिए द्विवार्षिक (आंतरिक) श्रोणि परीक्षा आयोजित करते हैं।

भले ही कार्य सद्भावपूर्वक किया गया हो - रोगी की भलाई और हाथ में समय के हित में - व्यवसायी ने रोगी को स्पष्ट करने या सूचित सहमति लेने के लिए आवश्यक नहीं समझा था, क्या वह इस तरह के आक्रामक के साथ सहज होगी या नहीं उसके शरीर पर प्रक्रिया की जा रही है।

यह उस आक्रोश का एक उदाहरण है जिसका अनुभव महिलाएं नियमित रूप से लेबर रूम में करती हैं। लेबर रूम हिंसा अज्ञात नहीं है - यह शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार, गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे की उपेक्षा, सूचित सहमति या पसंद की कमी और वित्तीय दुरुपयोग से लेकर है।

खुद से पूछे अभियान के हिस्से के रूप में, बिहार में एक महिला-नेतृत्व वाला आंदोलन, पटना में कई संगठनों द्वारा समर्थित, जिसमें सखी, बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स, गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन शामिल हैं। महिलाओं में सम्मानजनक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में पहचान बनाने के लिए, कई महिलाओं ने स्वास्थ्य सेवा में विविध अनुभवों पर विचार किया।

अभियान के हिस्से के रूप में, कई महिलाओं ने अत्यधिक निर्णय और शर्मिंदगी के बारे में बात की, जो उन्हें अनुभव करना पड़ा, जब देरी / चूक / दर्दनाक अवधि चक्रों के कारण स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच रही थी। चिकित्सा निदान और उपचार के बजाय, महिलाओं से व्यक्तिगत, संदर्भ से बाहर और असहज प्रश्न पूछे गए जैसे कि उनके प्रेमी थे, या यदि उनके अंतरंग संबंध या संबंध थे। मुखर तरीके से सुनने से पहले ही कुछ महिलाओं को गर्भवती होने की बात कह दी गई। इन सभी प्रतिक्रियाओं ने महिलाओं को अपने आप को ठगा हुआ महसूस कराया है। जिन लोगों ने दर्द का अनुभव किया, उन्हें कहा गया कि वे लचीला होना सीखें या यह कि शादी के बाद या पहले बच्चे के बाद यह बेहतर हो जाएगा। उनके दर्द को खारिज कर दिया गया और व्यक्तिगत टिप्पणियां की गईं। इन सभी अनुभवों में, महिलाओं ने महसूस किया कि संदेह और शर्म की एक निगाह है, जो महिला रोगियों को और अधिक आघात और चुप कराती है। झिझक और बाधाएं, जो कभी-कभी युवा, अविवाहित महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं का दौरा करने के लिए दूर होती हैं, महिलाओं की सेवाओं तक पहुंच को बाधित करती हैं।

किशोरावस्था से यौन स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े कलंक के कारण, महिलाएं चिंता व्यक्त करने या साझा करने में असमर्थ हैं, और स्तन विषमता, स्तन कैंसर से संबंधित मुद्दों, योनि स्राव,

मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी प्रश्नों या शरीर के बारे में सामान्य जिज्ञासा पर चर्चा करने में झिझक होती है। और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक उचित और सम्मानजनक पहुंच की कमी, जो अक्सर झिझक, कलंक और शर्म से भरी होती हैं, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।

नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस) के अनुसार, देखभाल की गुणवत्ता इस बात से मापी जाती है कि क्या उपयोगकर्ताओं को परिवार नियोजन की वर्तमान पद्धति के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया था। उदाहरण के लिए, पटना में, केवल 46.4 प्रतिशत महिलाओं को इसके बारे में जागरूक किया गया था, और केवल 18.6 प्रतिशत महिलाएं जो परिवार नियोजन सेवाओं तक नहीं पहुंच पाती थीं, उन्हें इसके बारे में परामर्श दिया गया था। आधी से भी कम महिलाओं को साइड इफेक्ट के बारे में जागरूक नहीं किया गया था, और भी कम को कोई परामर्श दिया गया था, जबकि परिवार नियोजन के बारे में मिथक और गलत धारणाएं आम हैं। महिलाओं की अधूरी ज़रूरतों में केवल दो प्रतिशत की कमी के साथ, 15 प्रतिशत अधूरी ज़रूरतें अधिक हैं, जहाँ महिलाएं अगले जन्म को स्थगित करने के लिए गर्भ निरोधकों का उपयोग करना चाहती हैं। सभी तीन कारक उचित परामर्श की कमी से जुड़े हैं, जो महिलाओं में असंतोष और असंतोष की ओर जाता है।

महिलाओं द्वारा अनुभव किए गए अपमान का दूसरा बड़ा पहलू उम्र, जाति, वर्ग, धर्म, योग्यता, कामुकता, लिंग, रोजगार, शिक्षा, उपस्थिति और संचार में प्रवाह के कारण भेदभाव, विभेदक उपचार और उपचार में पूर्वाग्रह है।

जिस तरह से डॉक्टर, कंपाउंडर या नर्स ने उन्हें छुआ, उससे बहुत सी महिलाओं ने अपमानित या असहज महसूस किया - उनमें से कुछ ने महसूस किया कि उन्हें अनुचित तरीके से छुआ गया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किसे बताना है या किसे रिपोर्ट करना है। सबने चुप्पी साध ली।

ज्यादातर मामलों में महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किससे संपर्क करना है, कैसे या किससे इन अनुभवों को समझाना है, घर पर या स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिक में हमेशा यह कहा जाने का डर होता है कि वे ध्यान आकर्षित कर रही हैं, वे अतिरंजना कर रही हैं, या तुच्छ होना। लेबर रूम में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पर सीईएचएटी की एक रिपोर्ट में, इसी तरह की स्थितियों में, डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के आदेशों ने उल्लेख किया कि यह महिलाएं थीं जिन्होंने स्थिति को गलत समझा, और डॉक्टर के कार्यों में यौन प्रकृति का कुछ भी शामिल नहीं था।

कई महिलाओं ने नहीं सोचा था कि वे इन अनुभवों को अपने परिवार के साथ साझा कर सकती हैं, इस डर से कि उन्हें ठीक से कपड़े पहनने, क्लिनिक में व्यवहार करने या भविष्य में क्लिनिक जाने से इनकार करने के डर से। चिकित्सा बिरादरी के हाथों में महत्वपूर्ण शक्ति है, जहां इलाज और देखभाल के लिए एजेंसी, शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता से समझौता किया जाता है।

स्वास्थ्य चिकित्सक और विशेषज्ञ ध्यान दें कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सदस्य उसी समाज का हिस्सा हैं जो हर दिन इन प्रथाओं को सामान्य करता है और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के गैर-प्रशिक्षण / संवेदीकरण के कारण ये स्वास्थ्य देखभाल में प्रतिबिंबित होते हैं।

खुद से पूछे कार्यशालाओं के दौरान, महिलाएं फीडबैक बॉक्स, लिंग संवेदीकरण और संवेदनशीलता प्रशिक्षण, नैतिकता प्रशिक्षण, हेल्पलाइन, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सत्र या समितियां स्थापित करने का सुझाव देती हैं जो इन अनुभवों पर ध्यान दे सकती हैं और स्थिति को नेविगेट करने में मदद कर सकती हैं।

जबकि स्वास्थ्य सेवा में अपमान के अनुभवों को सार्वभौमिक रूप से समझा जाता है, व्यक्ति की व्यक्तिगत परिस्थितियां उनके स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती हैं। यह उस अभियान में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था जिसके लिए उपरोक्त अधिकांश उपाख्यानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जैसे कि आवास की गुणवत्ता, पारिवारिक संरचना, हिंसा या संघर्ष, काम करने की स्थिति, शिक्षा, दैनिक जीवन शैली, लिंग या कामुकता, जाति, धर्म या वर्ग जैसे कारक, महिलाओं ने स्वास्थ्य सेवा तक कैसे पहुंच बनाई, इस पर एक बड़ी भूमिका निभाई।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) नोट करता है कि स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को उचित रूप से संबोधित करना स्वास्थ्य और भलाई में सुधार के लिए मौलिक है। इनमें प्रारंभिक बचपन और विकास, शिक्षा, आय और रोजगार, आवास, कार्य-जीवन संतुलन और स्थितियां, हिंसा, अन्य शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिला स्वास्थ्य चाहने वालों को एक समरूप समूह के रूप में नहीं देखा जाता है और मूल और अंतर्निहित कारणों पर विचार किया जाता है। उपचार प्रक्रिया।

(लेखिका बिहार में महिलाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन खुद से पूछे में कैंपेन लीड हैं

समसामयिक कला

उमा नायर कहती हैं, कढ़ाई वाले टेपेस्ट्री मुसी रोडिन में भारतीय कलाकारों, मनु और माधवी पारेख की प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं।

मुसी रोडिन ने कशीदाकारी टेपेस्ट्री के रूप में बनाई गई भारतीय समकालीन कला के रचनात्मक करिश्मे की प्रतिभा के लिए अपने पोर्टल खोले। मनु पारेख के बनारस शब्दचित्र और माधवी पारेख के आदिवासी लोक रूपांकनों को एक शानदार पृष्ठभूमि के लिए बनाया गया है, क्योंकि क्रिश्चियन डायर मॉडल मोनोक्रोमैटिक डलसेट हाउते कॉउचर में हैं। और पूरे सीन को क्रिएटिव डायरेक्टर मारिया ग्राजिया चिउरी ने कोरियोग्राफ किया था।

मारिया, मनु और माधवीक

जब से चिउरी ने डायर की बागडोर संभाली है, उन्हें उनके काम के नारीवादी रुख के लिए सलाम किया जाता है, हमेशा कला को उनके संदेश के केंद्र में रखा जाता है। पिछले हफ्ते मुसी रोडिन पेरिस में, डायर स्प्रिंग/समर 2022 हाउते कॉउचर शो के दौरान, कलाकारों माधवी और मनु पारेख के काम को उनके अनुवादित टेपेस्ट्री की अविश्वसनीय सजावट के साथ सम्मानित किया गया था।

इन शानदार स्मारकीय टेपेस्ट्री के बीच, मनु पारेख के बनारस में दो काम थे, जिन्होंने अपनी सारी महिमा में एक डूबते सूरज को दिखाया और माधवी के 2006 के काम टू हेड्स ऑफ ए ब्लैक क्वीन को 2007 में वदेहरास में उनकी एकल प्रदर्शनी में दिखाया गया।

इतिहास से भी पुराना है बनारस

मनु का बनारस एक मादक आनंद है। यह

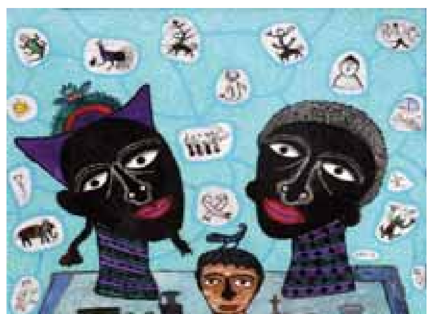

मंदिरों के सिल्हूट, रोशनी और दैनिक पूजा के उत्साह को गले लगाता है। बटरकप पीले और धुएँ के रंग के रसेट रंगों के गर्म स्वरों में बनाया गया, यह काम लय की एक रजाई है और गहरी प्रतिध्वनि है जो मानव टकटकी को आमंत्रित करती है और आध्यात्मिक उत्साह का जश्न मनाती है। मनु के बनारस में पारिस्थितिक और साथ ही एक सुंदर प्रतिध्वनि दोनों हैं क्योंकि यह एक ऐसी दुनिया में मृत्यु दर के विरोधाभास के साथ प्रार्थना के सामंजस्य का उपयोग करता है जहां अनुष्ठान और अवशेष कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। इस कृति में न केवल संध्या की बल्कि गोधूलि की कीमिया के भी कई रंग हैं, जब आप डूबते सूरज के प्रतिबिम्ब को देखते हैं। यह टुकड़ा अंग्रेजी लेखक और साहित्य मार्क ट्वेन के शब्दों की सच्चाई को दर्शाता है, जो शहर की किंवदंती और पवित्रता से मंत्रमुग्ध थे और उन्होंने लिखा, ''इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, किंवदंती से भी पुराना है और दो बार दिखता है। जितने पुराने सभी को एक साथ रखा गया है।''

एक काली रानी के माधवी के दो सिर

माधवी की टू हेड्स ऑफ ए ब्लैक क्वीन कलेक्टर और पारखी त्रिपत कालरा की है, जिन्होंने इसे 2007 में वदेहरास से खरीदा था, जब उन्होंने उसे अकेले रखा था। त्रिपत का कहना है कि उन्होंने काम खरीदा क्योंकि इसकी अपनी पहचान थी और संवाद और आयामों से परे जाना प्रतीत होता था क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान दोनों थे।

रंग और रूपरेखा उसके काम के दो सबसे प्रमुख पहलू हैं। सालों पहले एक साक्षात्कार में उसने कहा था- एक बच्चे के रूप में, गुजरात के ग्रामीण इलाकों से, मैंने प्रकृति की सबसे शानदार रोशनी देखी है। स्कूल से लौटते समय, डूबता सूरज पूरी दुनिया को आग लगा देता और उसे झिलमिलाती सुनहरी रोशनी में नहला देता। वे रंग मेरा अभिन्न अंग बन गए हैं और वे मेरे पास काफी स्वाभाविक रूप से आते हैं। मेरे चित्रों में बिंदीदार रेखाएं कढ़ाई के चल रहे टांके का आभास देती हैं जो मैंने एक बच्चे के रूप में किया था।

आसमानी नीले रंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ दो चेहरों की स्थिति, छोटे तत्वों से भरपूर, दर्शाती है कि उसे डिजाइन के लिए एक सहज अनुभव है और रूप उसके लिए स्वाभाविक रूप से आता है। यह हमें सजावटी फर्श डिजाइन (रंगोली), और झोपड़ियों पर दीवार की सजावट की पुरानी लोक कला प्रथाओं की याद दिलाता है। वह गुजरात के साधारण गांवों और घरों में पारंपरिक कला प्रथाओं की सुंदरता और प्राचीनता का प्रतिनिधित्व करती हैं।

एक सप्ताह तक चलने वाले, स्मारकीय कढ़ाई वाले कार्यों ने न केवल फैशन शो की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य किया, बल्कि रॉडिन की मूर्तियों के साथ दुर्लभ तीव्रता का तालमेल भी बनाया। रॉडिन की अप्सराओं और अर्ध-देवताओं की भारतीय मंदिरों से मुलाकात की कल्पना करना, कढ़ाई में प्रतीक देवत्व और व्यक्तित्व उदात्त अनुपात का अनुभव है। एक विचित्र और जिज्ञासु तरीके से, हम नर/मादा द्विभाजन की खोज और पूरकता की उनकी अंतर्निहित विशेषताओं को भी देख रहे हैं। मुसी रोडिन में, मारिया ग्रेसियस ने उद्धारकर्ता और दुर्लभ शिल्प कौशल के सिद्धांतों की पुष्टि की है। सामग्री, रूपक और रंग के मेल में, मुंबई में चाणक्य स्कूल ऑफ क्राफ्ट की कढ़ाई की तकनीक पर प्रकाश डाला गया है और इसे सम्मान का स्थान दिया गया है।

ये दो रचनाएं एक संपूर्ण आध्यात्मिक आयाम और दर्शकों की कल्पना में एक कला विसर्जन लाती हैं, जहाँ विचित्र, जिज्ञासु और परिचित वास्तविक, काल्पनिक और असली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं।

पारिस्थितिकीय तंत्र की पुनर्कल्पना

अलका गाडगिल मैंग्रोव के संरक्षण और तितलियों के संरक्षण के तरीकों पर विचार करती हैं।

तितलियाँ हममें प्रेम, शान और वैभव की कई भावनाएँ जगाती हैं। वे अपने पंखों पर जो अनोखे पैटर्न रखते हैं, वे न केवल मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं, बल्कि कई मायनों में चिकित्सीय भी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ तालुका की बीस वर्षीय स्वराली गोगेट ने इन रंगीन मक्खियों में उसे पुकारा।

स्वराली पुणे के अबासाहेब गरवारे कॉलेज से जूलॉजी में बीएससी कर रही हैं। मार्च 2020 में देश में कोविड -19 के प्रकोप के बाद, उनके कॉलेज ने, राष्ट्रीय तालाबंदी के बाद, अनिश्चित काल के लिए बंद करने की घोषणा की। स्वराली को घर लौटना पड़ा और कुछ दिनों के आराम के बाद, उसे अपने गाँव के चारों ओर मैंग्रोव फैलाने की ललक महसूस हुई। उन्होंने अपने कॉलेज के प्रोफेसर, डॉ आनंद पाध्ये से मार्गदर्शन मांगा, जिन्होंने उन्हें तितलियों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

''विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण ने हमारी जैव विविधता को रौंद डाला है। कोविड -19 महामारी वनस्पतियों और जीवों के लिए एक वरदान के रूप में आई थी, लेकिन लॉकडाउन के उत्थान के साथ, हानिकारक प्रभाव एक बार फिर दिखाई दे रहे हैं'', स्वराली बताती हैं।

सड़क और भवन निर्माण के लिए पेड़ों और झाड़ियों को काटने के कारण तितलियों के पतन को देखते हुए, स्वराली हरकत में आ गई। जब वह एक पेड़ की एक शाखा पर कैटरपिलर के लार्वा को देखती है, तो वह शाखा को पालने के लिए घर ले आती है। उसने पहले तालाबंदी के बाद से सैकड़ों कैटरपिलर का संरक्षण किया है। उन्होंने इन मक्खियों के लार्वा के पालन से लेकर तितली में परिवर्तन तक की यात्रा का भी दस्तावेजीकरण किया। अब तक, उसने कॉमन मॉर्मन, लाइम बटरफ्लाई, टेल्ड जे और कॉमन जे प्रजाति की मक्खियों का संरक्षण किया है।

महामारी के दौरान, उसकी तितली परियोजना ने उसके समुदाय और उसके आसपास के युवाओं में जिज्ञासा पैदा की। हर कोई जिसने उसके तितली संरक्षण को देखा, एक तितली के जीवन चक्र के चरणों को देखकर चकित रह गया। ''इतनी छोटी कोठरी में इतनी बड़ी तितली कैसे समा सकती है?'' उन्होंने सोचा। उसके काम से प्रेरित होकर, उन्होंने वादा किया कि वे पेड़ों से लार्वा नहीं हटाएंगे और कीटनाशकों के छिड़काव से परहेज करेंगे।

स्वराली की बचपन से ही वनस्पतियों और जीवों में अत्यधिक जिज्ञासा और रुचि थी। जबकि उसके गाँव के अधिकांश बच्चे कार्टून देखने में रुचि रखते थे, वह एनिमल प्लैनेट देखती थी। एक बच्चे के रूप में, वह सोचती थी कि वह इन जानवरों को कब देख पाएगी? वे कैसे रहते थे? उन्होंने कैसा व्यवहार किया? आसपास के साथ उनका क्या संबंध है?

''अपनी बचपन की जिज्ञासा का उत्तर खोजने में मदद करने के लिए, मैंने पुणे में प्राकृतिक इतिहास शिक्षा और अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित एक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, जिससे मुझे बहुत मदद मिली। जल में सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं और उनमें भी विविधता होती है। मैं टैक्सोनॉमी से परिचित हुआ जो प्रजातियों के वर्गीकरण, पहचान और नामकरण का विज्ञान है'' स्वराली ने कहा।

देवगढ़ में उसके घर के पास नाले के चारों ओर मैंग्रोव और आर्द्रभूमि थी। क्षेत्र के कुछ गांवों की मुख्य भूमि तक सीधी पहुंच नहीं थी। रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति एक गंभीर मुद्दा था क्योंकि एक सिलेंडर को दूर-दराज के स्थानों तक ले जाना मुश्किल था। नतीजतन, लोग जलाऊ लकड़ी पर निर्भर थे और पेड़ों को काट रहे थे। समस्या को हल करने के लिए, नाले के पार एक पुल बनाया गया था। इसने मैंग्रोव के पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर दिया। झींगे और झींगे को प्रभावित करने वाले भारी खंभों के कारण क्रीक की जल धाराएं अलग हो गईं। ये मछलियां आर्द्रभूमि में प्रजनन करती हैं और विनाश ने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया है।

स्वराली ने इस क्षेत्र में अपना शोध केंद्रित किया। वनस्पतियों और जीवों के अध्ययन के साथ, उन्होंने देवगढ़ के मैंग्रोव के आसपास कीट और पक्षी विविधता का भी अध्ययन किया। उसने तीन पैरों वाले कीड़ों और जानवरों का भी अध्ययन किया और कीड़ों और मक्खियों के साथ लगभग 125 प्रकार के पक्षियों को रिकॉर्ड किया।

मैंग्रोव के संरक्षण के लिए राज्य स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैंग्रोव पौधों के बीज लगाकर जल निकायों के पास मैंग्रोव को फिर से बनाया जा रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में, पुनर्निर्मित मैंग्रोव ने जैव विविधता, उत्पादकता में वृद्धि, पानी की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ कुल कार्बनिक कार्बन में कमी पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया है। हालांकि विकास का प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों की आजीविका पर पड़ता है, लेकिन नुकसान को कम करने के तरीके हैं। देवगढ़ ब्लॉक के स्वयं सहायता समूहों ने महाराष्ट्र सरकार के मैंग्रोव सेल के साथ साझेदारी में मैंग्रोव पौधों की एक नर्सरी शुरू की है।

भारत अंडर-विश्व कप के फाइनल में

कप्तान धुल के शतकीय प्रहार की मदद से आस्ट्रेलिया को 96 रनों से हराया

●अब शनिवार को इंग्लैंड से होगा खिताबी मुकाबला

भाषा। ओसबोर्न

अपनी असाधारण प्रतिभा की बानगी पेश करने वाले कप्तान यश धुल के शानदार शतक की मदद से भारत ने आस्ट्रेलिया को 96 रन से हराकर लगातार चौथी बार अंडर -19 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। धुल ने 110 गेंद में 110 रन बनाए और उपकप्तान शेख रशीद के साथ 204 रन की साझेदारी की। रशीद ने 108 गेंद में 94 रन बनाए। दोनों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम को पांच विकेट पर 290 रन तक पहुंचाया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और आस्ट्रेलिया को 41.5 ओवर में 194 रन पर आउट कर दिया। आस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ लाचलान शॉ 51 रन बना सके लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

भारत के लिए विकी ओस्तवाल ने तीन , रवि कुमार और निशांत सिंधू ने दो-दो और कुशाल ताम्बे ने एक विकेट लिया। वहीं तेज गेंदबाज राजवर्धन हंगरगेकर ने किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 26 रन दिए।

रिकॉर्ड चार बार के चैम्पियन भारत का सामना अब शनिवार को फाइनल में इंग्लैंड से होगा। धुल टूर्नामेंट के इतिहास में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय कप्तान हो गए। इससे पहले विराट कोहली (2008) और उन्मुक्त चंद (2012) यह कमाल कर चुके हैं और तीनों दिल्ली के हैं। धुल ने मैच के बाद कहा कि रशीद और मैं आखिर तक बल्लेबाजी करना चाहते थे और यह रणनीति कामयाब रही। टूर्नामेंट में शतक बनाने वाला तीसरा भारतीय कप्तान बनना गर्व का पल है।

उन्होंने कहा कि बहुत शॉट्स खेले बिना डटकर बल्लेबाजी करनी थी। हम दोनों का तालमेल अच्छा था। टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे कामयाब टीम भारत को शुरूआत में कोरोना संक्रमण से जूझना पड़ा जिसकी वजह से धुल और रशीद दो मैच नहीं खेल पाए लेकिन टीम में गहराई इतनी है कि नाकआउट तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जीत के लिए रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए आस्ट्रेलिया ने फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज टीग वीली का विकेट जल्दी गंवा दिए। रवि कुमार ने उन्हें पहली वैध गेंद पर पगबाधा आउट किया। कैंपबेल केल्लावे (30) और कोरी मिलर (38) ने 68 रन की साझेदारी की लेकिन छह गेंद के भीतर अपने विकेट गंवा बैठे। आस्ट्रेलिया का स्कोर इस समय तीन विकेट पर 73 रन था। बाएं हाथ के स्पिनर ओस्तवाल ने अपना दूसरा विकेट लेते हुए 30वें ओवर में आस्ट्रेलिया का स्कोर छह विकेट पर 119 रन कर दिया। धुल ने न सिर्फ बल्लेबाजी में प्रभावित किया बल्कि बतौर कप्तान भी सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनरों की बजाय अनियमित आफ स्पिनर अंगकृष रघुवंशी को गेंद सौंपी जिसने मिलर को आउट करके इस फैसले को सही साबित किया।

शतक पूरा करने के बाद कप्तान यश धुल

उपकप्तान शेख रशीद ने 94 रन की बेहतरीन पारी खेली

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर कठिन पिच पर बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरूआती पावरप्ले में आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत के सलामी बल्लेबाजों रघुवंशी और हरनूर सिंह काफी संभलकर खेल रहे थे जिससे दबाव बनने लगा।

विलियम साल्जमैन ने रघुवंशी को पवेलियन भेजा। हरनूर एक बार फिर नाकाम रहे और टोबिया स्नेल की उछाल लेती गेंद को खेलने के प्रयास में विकेट के पीछे कैच दे बैठे।इसके बाद रशीद और धुल ने कमान संभाली। टूर्नामेंट में अपना तीसरा ही मैच खेल रहे दोनों बल्लेबाजों ने काफी परिपक्वता दिखाई। रशीद ने अपनी पारी में आठ चौके और एक छक्का लगाया। वहीं धुल ने 10 चौके और एक छक्का जड़। उन्होंने 45वें ओवर में शतक पूरा किया और अगली गेंद पर टॉम विटनी को पारी का दूसरा छक्का लगाया।

धुल के आउट होने के बाद रशीद शतक से चूक गए और निसबेट की गेंद पर बैकवर्ड प्वाइंट में कैच दे बैठे। आस्ट्रेलिया ने रशीद को 24 के स्कोर पर जीवनदान दिया और धुल को रन आउट करने का मौका उस समय गंवाया जब वह 74 रन पर खेल रहे थे। आखिरी दस ओवर में आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने 108 रन दिए।

डटकर बल्लेबाजी करने की रणनीति थी : धुल

ओसबोर्न। भारत के अंडर-19 कप्तान यश धुल ने कहा कि उनकी और शेख रशीद की 40वें ओवर तक कोई जोखिम लिए बिना डटकर बल्लेबाजी करने की रणनीति थी जो आस्ट्रेलिया पर सेमीफाइनल में 96 रन से जीत दिलाने में कारगर साबित हुई। धुल ने कहा कि मेरी और रशीद की रणनीति आखिर तक बल्लेबाजी करने की थी जो कारगर साबित हुई। हमने ज्यादा शॉट्स नहीं लगाए और 46वें ओवर तक विकेट नहीं खोया।

कप्तान ने कहा कि रशीद और मेरा तालमेल अच्छा था जो नजर आया। टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद यहां तक पहुंचने के लिए टीम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हम शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। रशीद मानसिक रूप से काफी मजबूत है।

हम बबल में साथ में थे और वह मानसिक तौर पर हमेशा तैयार रहता है। आस्ट्रेलिया के कप्तान कूपर कोनोली ने कहा कि आखिरी दस ओवर में मैच उनकी पकड़ से छूट गया जब भारतीय बल्लेबाजों ने सौ से अधिक रन बनाए। उन्होंने कहा , हम 40वें ओवर तक अच्छी स्थिति में थे लेकिन उन्होंने आखिरी दस ओवर में 100 से ज्यादा रन बना दिए। 290 रन का लक्ष्य आसान नहीं था।

रणजी ट्रॉफी का पहला चरण 10 से 30 मई से होंगे नॉकआउट मुकाबले

फाइल फोटो

●टूर्नामेंट में 62 दिनों में 52 मुकाबले खेले जाएंगे

भाषा। नई दिल्ली

बहुप्रतीक्षित रणजी ट्रॉफी का पहला चरण 10 फरवरी से 15 मार्च तक खेला जाएगा जिसके बाद देश की शीर्ष घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता को इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान ब्रेक दिया जाएगा। टूर्नामेंट का अगला चरण 30 मई से 26 जून तक होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने राज्य इकाइयों को गुरुवार को यह जानकारी दी।

शाह के पत्र से स्पष्ट हो गया है कि यह सबसे छोटे प्रथम श्रेणी सत्र में से एक होगा जिसमें अधिकांश टीम को सिर्फ तीन मैच खेलने को मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि ग्रुप लीग चरण से बाहर होने वाली टीम को बढ़ी हुई मैच फीस का अधिक फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि अधिकांश टीम ग्रुप चरण से बाहर हो जाएंगी।

इसमें चार-चार टीम के आठ एलीट ग्रुप बनाए जाएंगे जबकि बाकी बची छह टीम को प्लेट डिविजन में जगह मिलेगी। मैच फीस के नए स्लैब के अनुसार 40 से अधिक मुकाबले खेलने वालों को प्रतिदिन 60 हजार रुपए का भुगतान होगा जो 35 हजार रुपए प्रति दिन की पिछली मैच फीस से काफी अधिक है। इसके अलावा 21 से 40 मैच का अनुभव रखने वाले खिलाड़ियों को प्रतिदिन 50 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा। टूर्नामेंट के दौरान 62 दिन में 64 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले चरण में 57 मैच होंगे। दूसरे चरण में सात नॉकआउट मैच होंगे जिसमें चार क्वार्टर फाइनल, दो सेमीफाइनल और फाइनल होगा।

एलीट ग्रुप के मैच राजकोट, कटक, चेन्नई, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, दिल्ली, हरियाणा और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। प्लेट लीग मैच कोलकाता में होंगे। टूर्नामेंट के दौरान नौ स्थलों पर नौ जैविक रूप से सुरक्षित माहौल की जरूरत पड़ेगी। पिछले साल रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार इस टूर्नामेंट को रद्द किया गया था और इस साल भी कोविड-19 की तीसरी लहर के कारण बीसीसीआई को टूर्नामेंट को स्थगित करने को बाध्य होना पड़ा। यह टूर्नामेंट पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13 जनवरी को शुरू होना था।

भारत में लाल गेंद से पिछला घरेलू क्रिकेट मुकाबला मार्च 2020 में खेला गया था। शाह ने राज्य इकाइयों को भेजे पत्र में लिखा कि मुझे आपके साथ यह साझा करने की खुशी है कि हम अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट दोनों को बहाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे धैर्य के साथ इंतजार किया कि महामारी की पकड़ ढीली हो और समय आ गया है कि हमारे क्रिकेटर एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बनें।

उन्होंने लिखा कि संशोधित रणजी ट्रॉफी का प्रारूप अब तैयार है। प्रसार के खतरे को कम करने के लिए हमने देश के नौ अलग स्थलों पर रणजी ट्रॉफी का आयोजन करने का फैसला किया है जबकि यह भी सुनिश्चित किया है कि जैविक रूप से सुरक्षित माहौल पर अधिक जोर नहीं पड़े। अतीत में जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में कोविड दस्तक दे चुका है और इसमें आईपीएल भी शामिल है। शाह ने हालांकि कहा कि बोर्ड ने आपात योजना तैयार की है।

शाह ने लिखा कि वायरस जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में भी घुस रहा है, इस ढांचे को तैयार करते हुए हमने अपने अतीत के अनुभव के आधार पर आपात योजना भी तैयार की है। एलीट ग्रुप में प्रत्एक स्थल पर दो स्टेडियम में मैच का आयोजन होगा जबकि कोलकाता में प्लेट ग्रुप में तीन स्टेडियम उपयोग में लाए जाएंगे। दिल्ली को एलीट एच ग्रुप में तमिलनाडु, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ रखा गया है जिसके मुकाबले गुवाहाटी में होंगे। गत चैंपियन सौराष्ट्र की टीम अपने ग्रुप मुकाबले अहमदाबाद में खेलेगी। टीम को एलीट डी ग्रुप में मुंबई, ओडिशा और गोवा के साथ रखा गया है।

पुजारा व रहाणे की निगाहें रणजी से टेस्ट कैरियर पटरी पर लाने पर

भाषा। नई दिल्ली

रणजी ट्राफी के 10 फरवरी से शुरू होने से अनुभवी क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को अपना टेस्ट करियर फिर से पटरी पर लाने का मौका मिल जाएगा क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला भी मार्च के पहले हफ्ते से खेली जाएगी।

श्रीलंका के खिलाफ टी-20 मैच 25 फरवरी से शुरू हो रहे हैं जिससे इन दोनों अनुभवी क्रिकेटरों के पास रणजी ट्राफी में बड़ा शतक जड़कर आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका होगा और शायद उनके प्रदर्शन से वे भारतीय टीम में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें।

एलीट ग्रुप मैच 16 फरवरी से शुरू होंगे जबकि प्लेट ग्रुप मैच 10 फरवरी से खेले जाएंगे। आलोचनाओं से घिरे दोनों सीनियर खिलाड़ियों को चयनकर्ताओं का भरोसा हासिल करने में कम से कम दो मैच तो मिलेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही अपनी अपनी मुंबई और सौराष्ट्र की टीमों के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है और दोनों ही उम्मीद के अनुरूप बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे।

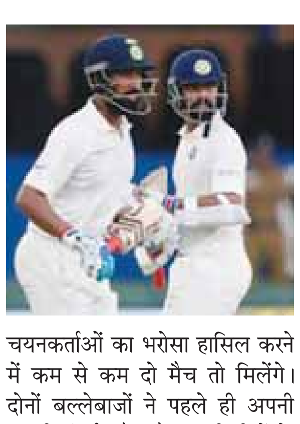

बल्कि अगर वे अहमदाबाद में सौराष्ट्र और मुंबई के बीच होने वाले मैच के लिए टीम का हिस्सा होंगे तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। मुंबई के कोच अमोल मजूमदार ने कहा कि अजिंक्य निश्चित रूप से तैयार हैं। हम कई बार मिल चुके हैं, वह मुंबई टीम के साथ अभ्यास कर रहा है। उसने दो सत्र कर लिए हैं। वह अच्छी फॉर्म में लग रहा है। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है लेकिन हमारे सामने अभी रणजी ट्राफी है। दोनों को एक बड़ी पारी की जरूरत है।

मुझे लगता है कि यह बस आत्मविश्वास का सवाल है। कभी कभार बल्लेबाजी कुछ नहीं बस आत्मविश्वास होती है। आप किसी भी तरह इस आत्मविश्वास को वापस ला सकते हो। ऐसा तभी होगा जब आप एक बड़ा शतक जड़ोगे।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली को भी पुजारा और रहाणे से इस घरेलू प्रतियोगिता में रन जोड़ने की उम्मीद है।

शीतकालीन ओलंपिक आज से, समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे भारतीय राजनयिक

भाषा। बीजिंग

भारतीय राजनयिक शुक्रवार को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के भव्य उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे जिसे चीन के शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के कारण अमेरिका और उनके सहयोगियों के राजनयिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है।

एक पखवाड़े तक चलने वाले शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत की घोषणा राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और कई पश्चिमी देशों ने उद्घाटन समारोह के राजनयिक बहिष्कार का फैसला किया है। इस बीच कोविड-19 संक्रमण का खतरा भी बरकरार है। शुक्रवार को होने वाले उद्घाटन समारोह से पहले जिनपिंग ने कहा कि चीन सुरक्षित और शानदार शीतकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा।

रोहन बोपन्ना-रामकुमार रामनाथन की जोड़ी युगल सेमीफाइनल में

●युकी भांबरी टाटा ओपन से बाहर

भाषा। पुणे

रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की भारतीय जोड़ी ने गुरूवार को यहां बालेवाड़ी स्टेडियम में 2022 टाटा ओपन महाराष्ट्र के युगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया जबकि युकी भांबरी का अभियान एकल वर्ग के दूसरे दौर में खत्म हो गया।

बोपन्ना और रामकुमार ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर एर्लर और चेक गणराज्य के जिरी वेस्ली की चुनौती को 7-6 (7-3), 7-6 (7-4) से समाप्त किया। दक्षिण एशिया के इस एकमात्र एटीपी 250 टूर्नामेंट के चौथे संस्करण के रूप में बोपन्ना और रामकुमार एक साथ अपना दूसरा एटीपी टूर्नामेंट खेल रहे हैं। अब सेमीफाइनल में बोपन्ना और रामकुमार का सामना सादियो डौम्बिया और फैबियन रेबौल से होगा। फ्रांस की इस जोड़ी ने फेडेरिको गियो और लोरेंजो मुसेट्टी के खिलाफ 4-6, 6-3, 10-2 से जीत के साथ अंतिम चार में प्रवेश किया।

एन श्रीराम बालाजी और विष्णु वर्धन की एक अन्य भारतीय जोड़ी भी सेमीफाइनल में खेलेगी क्योंकि उनके विरोधी जियानलुका मैगर और एमिल रुसुवुओरी चोट के कारण अंतिम आठ मैच से हट गए। वैकल्पिक जोड़ी के रूप में मुख्य ड्रा में जगह बनाने वाली बालाजी और वर्धन की भारतीय जोड़ी ने पहले दौर में बुधवार रात स्थानीय खिलाड़ी अर्जुन काधे और पूरव राजा की जोड़ी को 6-1, 6-4 से हराया। हालांकि युकी का सफर एकल स्पर्धा के दूसरे दौर के मैच में हार से समाप्त हो गया। भारत के शीर्ष खिलाड़ियों में से एक युकी को आठवीं वरीयता प्राप्त इटली के स्टेफानो ट्रैवाग्लिया ने 6-3, 6-2 से हराया। इससे पहले स्वीडन के एलियास एमेर ने शीर्ष वरीय और दुनिया के 15वें नंबर के खिलाड़ी असलान करात्सेव को सीधे सेटों में हराकर एकल क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया। एमेरे ने एक घंटे 36 मिनट तक चले दूसरे दौर के मैच में करात्सेव को 6-2, 7-6 (7-3) से हराया।

क्वालीफायर से प्रवेश करने वाले 25 वर्षीय एमेर ने मुकाबले की अच्छी शुरूआत की और करात्सेव के खिलाफ 3-। की बढ़त बना ली। पहले दौर में बाई मिलने के बाद करात्सेव महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस संघ द्वारा आयोजित किए जा रहे इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलते हुए लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

जोकोविच ने वीजा प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया

बेलग्रेड। नोवाक जोकोविच ने आस्ट्रेलिया में खुद को हिरासत में रखने और निर्वासित किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया जिसके कारण वह आस्ट्रेलियाई ओपन में अपने खिताब का बचाव नहीं कर पाए। उन्होंने साथ ही सर्बियाई राष्ट्रपति को उनके समर्थन के लिए शुक्रिया भी कहा।

आस्ट्रेलिया की सख्त कोविड-19 टीकाकरण जरूरतों को पूरा कर पाने में विफल होने के कारण जोकोविच को देश से निर्वासित कर दिया गया। शीर्ष रैंकिंग टेनिस स्टार सर्बियाई राष्ट्रपति से मिला और आस्ट्रेलिया में प्रवेश वीजा को लेकर हुई 11 दिन की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। जोकोविच ने कहा कि, मैं आज आपसे मिलना चाहता था क्योंकि आपने और राज्य संस्थानों ने आस्ट्रेलिया में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के दौरान जिस तरह से मेरा समर्थन किया था, उसके लिए सर्बिया के नागरिक होने के नाते मुझे आपको शुक्रिया कहना था।

माने के शानदार प्रदर्शन से सेनेगल अफ्रीकी कप के फाइनल में

एपी। याओंडे (**कैमरून**)

लिवरपूल के स्ट्राइकर सादियो माने के शानदार प्रदर्शन के दम पर सेनेगल ने बुर्किना फासो को 3-1 गोलों से हराकर लगातार दूसरी बार अफ्रीकी कप आफ नेशंस फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश कर लिया। माने ने एक गोल में सहायता की और दूसरा गोल खुद किया। इस मैच में सभी गोल 20 मिनट के भीतर हुए।

डिफेंडर अब्दु दायलो ने 70वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके सेनेगल को बढत दिलाई। माने ने 76वें मिनट में बाम्बा डिएंग के गोल में सूत्रधार की भूमिका निभाई। बुर्किना फासो के लिए ब्लाटी टॉरे ने 82वें मिनट में गोल किया। वहीं माने ने 87वें मिनट में सेनेगल का तीसरा गोल दागा।

सेनेगल अब तक यह टूर्नामेंट जीत नहीं सका है। उसे 2002 और 2019 में पराजय का सामना करना पड़ा।

खेल में सुधार के लिए आईपीएल नहीं खेलने का फैसला किया : जैमीसन

भाषा। आकलैंड

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने इस साल पृथकवास और बायो बबल से दूर रहकर घर पर समय बिताने और अपने खेल में सुधार के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं खेलने का फैसला किया है। जैमीसन पिछले साल आईपीएल में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 15 करोड़ रूपए में खरीदा था। जैमीसन ने कहा कि मैने कई कारणों से यह फैसला लिया है। पिछले बारह महीने बायो बबल और पृथकवास में काफी समय बिताया। अगले 12 महीने के शेड्यूल को देखते हुए अब परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं।

भारत के खिलाफ फरवरी 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले जैमीसन 12 टेस्ट, पांच वनडे और आठ टी20 खेल चुके हैं।

उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह है कि मैं अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत नया हूं। दो ही साल हुए हैं तो मैं अपने खेल पर मेहनत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जहां पर मुझे होना चाहिए, उस स्तर पर नहीं पहुंच सका हूं। अगर तीनों प्रारूपों में खेलना है तो अपने खेल पर मेहनत करनी होगी। जैमीसन ने कहा कि आईपीएल नहीं खेलने का फैसला कठिन था लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह भविष्य में इस लीग का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि यह शुरूआत में काफी कठिन फैसला था। मैंने इस पर काफी विचार किया। लेकिन मैं अपने कैरियर पर फोकस करना चाहता हूं और अपने खेल पर काम करना चाहता हूं।

एशेज सीरीज में शर्मनाक हार के बाद एश्ले जाइल्स को पद छोड़ना पड़ा

लंदन। एशेज श्रृंखला में आस्ट्रेलिया के हाथों शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड टीम के प्रबंध निदेशक एशले जाइल्स को पद से हटा दिया गया है जो तीन साल से यह पद संभाल रहे थे। पूर्व टेस्ट कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस अंतरिम तौर पर उनकी जगह लेंगे। इंग्लैंड को एशेज श्रृंखला में 4-0 से पराजय मिली थी।

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी टॉम हैरीसन ने कहा कि इस बार एशेज श्रृंखला में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद हमें आगे इसके दोहराव से बचने के लिए काम करना होगा। जाइल्स के साथ इंग्लैंड ने पहली बार 50 ओवरों का विश्व कप जीता लेकिन टेस्ट प्रारूप में प्रदर्शन निराशाजनक रहा।

इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट स्पिनर जाइल्स ने कहा कि पिछले कुछ साल काफी चुनौतीपूर्ण रहे। मुझे गर्व है कि कठिन परिस्थितियों में भी हम अच्छा प्रदर्शन कर सके।

टीम इंडिया ने शुरू किया अभ्यास

●मयंक अग्रवाल को मिला मौका

भाषा। अहमदाबाद

शिखर धवन, रूतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर की तिकड़ी को छोड़कर भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपनी आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद गुरूवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभ्यास शुरू कर दिया। मयंक अग्रवाल टीम से जुड़ गए हैं लेकिन वह मैच के दिन ही उपलब्ध होंगे क्योंकि उनका तीन दिवसीय अनिवार्य पृथकवास शुरू हो चुका है। टीम प्रबंधन ने ईशान किशन को वनडे के लिए टीम में शामिल किया है।

भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे श्रृंखला खेलनी है जो छह फरवरी से यहां शुरू होगी। इसकी जानकारी रखने वाले एक अनुभवी अधिकारी ने कहा कि आज का सत्र हल्के अभ्यास वाला रहा जिसमें खिलाड़ियों के साथ ट्रेनर भी थे। पता चला है कि विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को भी वनडे टीम में शामिल किया है जो एक विशेषज्ञ सलामी बल्लेबाज हैं। बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम के तीन मुख्य खिलाड़ी - सीनियर सलामी बल्लेबाज धवन, रिजर्व सलामी बल्लेबाज गायकवाड़ और मध्यक्रम के बल्लेबाज अय्यर - वेस्टइंडीज श्रृंखला शुरू होने से पहले अनिवार्य पृथकवास के दौरान हुई कोविड-19 जांच में पॉजिटिव आए थे। चार अन्य लोग भी कोविड-19 जांच में पॉजिटिव आए थे जिसमें नेट गेंदबाज नवदीप सैनी भी शामिल थे। सैनी भी स्टैंडबाई सूची में शामिल हैं। कोविड-19 पॉजिटिव आने वाले अन्य तीन सदस्य क्षेत्ररक्षण कोच टी दिलीप, सुरक्षा संपर्क अधिकारी बी लोकेश और मालिशिया राजीव कुमार हैं। भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी सफेद गेंद की श्रृंखला के लिए 31 जनवरी को अहमदाबाद में इकट्ठा हुई थी।